कल्पमेधा

हमेशा वास्तविक बने रहो। खुद को अभिव्यक्त करो। अपने ऊपर विश्वास रखो। किसी भी सफल शख्सियत की नकल नहीं करो।

– ब्रूस ली

सेहत की सुध

किसी भी रोग की दवा से लेकर रसायनों के मिश्रण से तैयार हर वह पदार्थ हमेशा ही संबंधित एजंसियों की निगरानी के दायरे में होना चाहिए, जो इंसानी सेहत के लिए जोखिम का कारक बन सकते हैं। हालांकि सरकार के मातहत इसके लिए बाकायदा एक तंत्र है, लेकिन इसके बावजूद बाजार में ऐसी दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों की बिक्री खुलेआम होती रहती है, जिनके उपयोग के बाद स्वास्थ्य कई तरह के जोखिम के दायरे में आ जाता है। ऐसा नहीं है कि इस तरह के खतरनाक रसायनों के इस्तेमाल पर रोक के लिए कानून नहीं हैं, लेकिन या तो वे अपर्याप्त हैं या फिर उन्हें सख्ती से लागू करने को लेकर सरकारी एजंसियों के भीतर कोई इच्छाशक्ति नहीं है। यह बेवजह नहीं है कि ऐसी दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों के इस्तेमाल से कई बार नाहक ही लोगों की मौत होने या स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचने की खबरें आती रहती हैं। यों तो सरकार को इससे संबंधित नियम-कायदों को पहले ही सख्ती से लागू करना चाहिए था, लेकिन अब नए सिरे से नकली या जोखिम का वाहक बनने वाली दवाओं और नुकसानदेह सौंदर्य प्रसाधनों पर नकेल कसने की तैयारी हो रही है।

दरअसल, हाल ही में कुछ राज्यों में खांसी की दवा पीने से कई बच्चों की मौत की खबरें आईं और इससे हर तरफ चिंता पैदा हुई। अब केंद्र सरकार दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों की सख्त गुणवत्ता जांच और निगरानी के लिए कानून लाने जा रही है। इस संबंध में 'औषधि, चिकित्सा उपकरण और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 2025' का मसविदा संसद के आगामी सत्र में पेश किया जा सकता है। देश भर में आए दिन नकली दवाओं की बिक्री और उससे पैदा खतरों को लेकर सवाल उठते रहते हैं। अगर कभी कोई मामला तूल पकड़ लेता है, तब थोड़ी सख्ती और कार्रवाई होती दिखती है। मगर आमतौर पर कार्रवाई के दायरे में निचले स्तर के कुछ कर्मचारी या अधिकारी ही आते हैं। मामला शांत होने के बाद फिर दवाओं के निर्माण को लेकर गुणवत्ता और तय कसौटियों में व्यापक लापरवाही बदस्तूर जारी रहती है।

इसी के मद्देनजर विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ-साथ विश्व भर के कई बड़े स्वास्थ्य नियामकों की ओर से भारतीय दवा निर्माताओं की गुणवत्ता संबंधी गंभीर खामियों को लेकर बार-बार शिकायतें और चिंता दर्ज कराई गईं। मगर ऐसा लगता है भारत में सरकार और दवा कंपनियों की नींद तब तक नहीं खुलती, जब तक कोई बड़ा नुकसान नहीं हो जाता और कुछ लोगों की जान नहीं चली जाती। ऐसी दवाओं के बारे में भी खबरें आती रहती हैं, जो दूसरे कुछ देशों में प्रतिबंधित होती हैं, लेकिन यहां वे धड़ल्ले से चिकित्सकों के परामर्श तक में शामिल दिख जाती हैं। इसी तरह, सौंदर्य प्रसाधनों में कई ऐसे हैं, जिनमें हानिकारक रसायन मिले होते हैं और वे दीर्घकालिक तौर पर शरीर या इसके खास हिस्से को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। मगर बिना किसी निगरानी और जांच-परख के नकली दवाओं से लेकर सौंदर्य प्रसाधनों के उत्पाद खुले बाजार में खरीदे-बेचे जाते रहते हैं। दूसरी ओर, लोगों के बीच भी अपने स्तर पर किसी उत्पाद या दवा की जांच कराने की सुविधा से लेकर अपेक्षित जागरूकता का अभाव देखा जाता है। अब यह देखने की बात होगी कि इस संबंध में प्रस्तावित कानून किस रूप में सामने आता है और सरकार के संबंधित महकमे जोखिम का वाहक बनने वाली दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों की बिक्री और उत्पादन पर रोक लगाने के लिए कैसी इच्छाशक्ति के साथ काम करते हैं।

भुखमरी के सामने

विकास के तमाम दावों के समांतर दुनिया में आज भी करोड़ों लोग भुखमरी का सामना कर रहे हैं। यह समझना मुश्किल है कि एक ओर कुछ देशों की अरबों-खरबों की अर्थव्यवस्था की बात हो रही है तो दूसरी ओर कई देशों में करोड़ों नागरिक आज भी भूखे पेट क्यों सो रहे हैं। क्या यह संसाधनों के असंतुलित बंटवारे से उपजी समस्या है? भुखमरी की समस्या को लेकर संयुक्त राष्ट्र की वित्तपोषित एजंसी विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लूएफपी) की नई रपट विचलित करती है। इसके मुताबिक, दुनिया के छह देशों के एक करोड़ चालीस लाख लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच सकते हैं। समझा जा सकता है कि आज भी भूख और कुपोषण कितनी बड़ी चुनौती है। यह तब है जब दुनिया भर में कृषि प्रौद्योगिकी को उन्नत अवस्था में बताया जाता है। कई देशों में अनाज भंडार भरे हुए हैं। ऐसे में दुनिया के किसी कोने में कोई व्यक्ति भूखा रह जाता है, तो इसके जिम्मेदार वे बड़े देश भी हैं, जो खाद्य सहायता कार्यक्रम को आर्थिक सहायता देने से हाथ खींच रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सहायता एजंसी का कहना है कि उसके प्रमुख दानदाताओं, खासकर अमेरिका और प्रमुख पश्चिमी देशों ने अनुदान में भारी कटौती की है। नतीजतन, हैती, सोमालिया, सूडान, कांगो, दक्षिण सूडान और अफगानिस्तान में नागरिकों तक खाद्य सहायता नहीं पहुंच रही और वहां के लोग भुखमरी का सामना करने को लाचार हैं।

गरीबी, कुपोषण और भुखमरी से बेहाल देशों की दुर्दशा को संयुक्त राष्ट्र एजंसी के इस कथन से समझा जा सकता है कि हम लाखों लोगों की जीवनरेखा को अपनी आंखों के सामने टूटते हुए देख रहे हैं। वैश्विक स्तर पर भुखमरी का यह भयावह परिदृश्य है। विज्ञान में इतनी प्रगति के बाद भी भुखमरी आज भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। करीब इकतीस करोड़ से अधिक नागरिक गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। इनमें भी करीब साढ़े चार करोड़ नागरिक आपात स्थिति में पहुंच चुके हैं। सोमालिया में गरीबी और भुखमरी पूरी मानवता को लज्जित करती है। यह नहीं भूलना चाहिए कि कई बड़े राष्ट्र छोटे देशों में संसाधनों का दोहन करते आए हैं। ऐसे में सवाल है कि अंतरराष्ट्रीय खाद्य सहायता कार्यक्रम से पीछे हट रहे बड़े देश आखिर कैसी दुनिया देखना चाहते हैं?

आभासी दुनिया के वास्तविक जोखिम

सोशल मीडिया के दौर में संक्षिप्त वीडियो बनाना केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि पैसा और शोहरत कमाने का माध्यम बन चुका है। यह डिजिटल संस्कृति अब युवाओं के जीवन में वास्तविक और आभासी दुनिया के बीच की सीमाओं को धुंधला कर रही है।

सुनील कुमार

पिछले कुछ वर्षों से यह साफ देखा जा सकता है कि स्मार्टफोन का किस स्तर पर विस्तार हुआ है और युवाओं के बीच इसका उपयोग किस कदर बढ़ गया है। ऐसे उदाहरण आसानी से मिल जाएंगे, जिसमें युवा पढ़ाई और किसी नियमित रोजगार का मार्ग चुनने के बजाय 'रील' बना कर सोशल मीडिया पर प्रसारित कर उससे कमाई के रास्ते तलाश रहे हैं। यह अब लाखों युवाओं की हकीकत बन चुकी है। आज सोशल मीडिया के इस दौर में 'रील' केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि यह पैसा और शोहरत कमाने का माध्यम बन चुका है। यह मानसिकता पढ़े-लिखे युवाओं से लेकर आम गृहिणियों, कामकाजी महिलाओं और ट्रक चालकों से लेकर घर-घर सामान पहुंचाने वालों तक फैल चुकी है। कभी मनोरंजन के लिए शुरू हुई यह डिजिटल संस्कृति अब युवाओं के जीवन में वास्तविक और आभासी दुनिया के बीच की सीमाओं को धुंधला कर रही है। गांव, शहर, कस्बा और महानगर हर जगह युवा कैमरे के सामने अभिनय करते, सड़कों पर नाचते या खतरनाक करतब करते दिखाई देते हैं। इस क्रम में वे अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डालने से भी नहीं चूकते हैं।

पहले युवा वर्ग डाक्टर, इंजीनियर, अधिकारी, लेखक, सैनिक या खिलाड़ी आदि बनने का सपना देखता था। कुछ युवा फिल्मों से प्रभावित होकर अभिनय की दुनिया में कदम रखने के लिए वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद अपना स्थान मुश्किल से बना पाते थे। मगर आज का युवा परिश्रम के बजाय 'इन्फ्लुएंसर' (समाज में अपना प्रभाव बनाने वाला) बनना चाहता है। अब लक्ष्य ज्ञान या कौशल नहीं, बल्कि लोकप्रियता हासिल करना और थोड़े समय में दौलतमंद बन जाना है। यह संस्कृति एक नई मानसिकता को जन्म दे रही है, जो सामाजिक विकृति का कारण भी बन रही है। 'रील' बनाना अब कला नहीं, बल्कि एक प्रतिस्पर्धा है।

समाज में सहयोग की जगह तुलना और प्रतियोगिता ने ले ली है, जहां हर कोई दूसरों से अधिक लोकप्रियता पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। कोई चलती ट्रेन के पास नृत्य करता है, कोई पुल से कूदता है, कोई सड़क पर करतब दिखाता है, तो कोई सामाजिक मर्यादाओं को ताक पर रख कर सोशल मीडिया के लिए सामग्री तैयार करता है। इससे कई तरह की मानसिक और सामाजिक विकृतियां भी पैदा हो रही हैं, जो कई बार हत्या या आत्महत्या जैसी आपराधिक घटनाओं के रूप में सामने आती है। युवा सोचते हैं कि यदि उन्होंने कुछ अनोखा किया, चाहे उसमें जान का जोखिम क्यों न हो, उससे उन्हें प्रसिद्धि मिलेगी। मगर कई बार इसकी कीमत जान गंवा कर चुकानी पड़ती है।

देश में रेल मार्ग के पास इस तरह के वीडियो बनाते हुए कितने लोगों की जान जा चुकी है, इसका कोई निश्चित आंकड़ा नहीं है। मगर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे और नागपुर मंडल के एक अनुमान के मुताबिक, वर्ष 2025 के शुरुआती पांच महीनों में सत्तानबे लोग ट्रेन से कट कर मारे गए, जो 'रील' बनाने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिका की 'बार्बर ला फर्म' की रपट के अनुसार, दुनिया भर में सेल्फी लेते समय मौत की घटनाओं में से

42.1 फीसद घटनाएं भारत में हुई हैं। ये महज हादसे नहीं, बल्कि उस समाज की त्रासदी है, जिसने वास्तविक जीवन के बजाय आभासी छवि को अधिक मूल्यवान बना दिया है। युवाओं में बढ़ती यह प्रवृत्ति उन्हें वास्तविक संवाद, पढ़ाई, संबंध और सामाजिक जिम्मेदारी से दूर ले जा रही है।

> **सोशल मीडिया पर 'रील' का जुनून केवल व्यक्ति का बाहरी व्यवहार नहीं बदलता, बल्कि उसके भीतर की दुनिया को भी विकृत कर देता है। अब सफलता की दर प्रसिद्धि और समर्थकों की संख्या से मापी जाने लगी है। यही तत्त्व दोस्ती, प्रेम और आत्मविश्वास का पैमाना बन गए हैं। युवा इस भ्रम को हकीकत मानने लगे हैं कि सोशल मीडिया पर सराहना ही उनकी असली पहचान है। इस प्रवृत्ति के कारण वे वास्तविक जीवन से कटने लगे हैं। युवाओं को यह समझना होगा कि असली पहचान स्क्रीन पर नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन में है। जरूरत है आज की युवा पीढ़ी को सही दिशा देने की, ताकि कैमरे के सामने सिर्फ दिखावे के बजाय विचार, संवेदना और परिवर्तन की सच्ची तस्वीर बने।**

इस संस्कृति का एक और खतरनाक पहलू अभद्रता और हिंसा का महिमामंडन है। आज सोशल मीडिया पर मौजूद अधिकांश सामग्री सामाजिक शालीनता की सीमाओं को लांघ चुकी है। विडंबना यह है कि इस तरह की सामग्री को दर्शक भी पसंद करने लगे हैं। किसी समाज की सभ्यता का आकलन इस बात से भी किया जाता है कि वह अपने युवाओं को किस दिशा में प्रेरित करता है। जब युवाओं की ऊर्जा ऐसी सामग्री तैयार करने में लग रही है, तो यह सामाजिक पतन का स्पष्ट संकेत है। आज कोई यह नहीं पूछता कि हमारी शिक्षा और पारिवारिक व्यवस्था इतनी असफल क्यों हो गई कि युवा अपनी पहचान सिर्फ कैमरे में खोजने लगा है।

आभासी दुनिया से जुड़ी इस संस्कृति ने न केवल युवाओं की ऊर्जा को भटकाया है, बल्कि समाज की नैतिकता को भी चोट पहुंचाई है। सड़क दुर्घटनाओं के दौरान मदद करने के बजाय लोग अब मोबाइल निकाल कर वीडियो बनाते हैं, क्योंकि इस तरह की सामग्री के प्रसार का लोभ मानवता से बड़ा हो गया है। अब मानवीय संवेदनाओं की जगह प्रसिद्धि का आकर्षण साफ दिखाई देता है। बच्चों के साथ माता-पिता के संवाद और मित्रता का स्थान अब स्क्रीन ने ले लिया है। यही कारण है कि मोबाइल बच्चों का शिक्षक, मित्र और आदर्श बनता जा रहा है। दुखद यह है कि इस बदलती मानसिकता के बीच परिवार, शिक्षक और समाज मौन हैं। समाचार माध्यम भी सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित होने वाली सामग्री को खबर के रूप में परोसते हैं, जिससे युवाओं के बीच इस तरह की सामग्री बनाने की होड़ और तेज हो जाती है।

वीडियो के जरिए 'रील' की फलती-फूलती संस्कृति सिर्फ सामाजिक समस्या नहीं, बल्कि आर्थिक तंत्र का हिस्सा भी है। लोग सोशल मीडिया पर सामग्री डाल कर पैसा कमाना चाहते हैं। इसलिए वे वही सामग्री आगे बढ़ाते हैं, जो अधिक लोगों को आकर्षित करे, चाहे वह कितना भी सतही, हिंसक या अपमानजनक या अभद्र क्यों न हो। युवाओं को शायद ही इस बात का एहसास होता है कि वे डिजिटल उत्पाद बनते जा रहे हैं। उनका समय, ध्यान और भावनाएं डेटा तथा विज्ञापन के रूप में बिक रहे हैं। युवा सोचते हैं कि वे रचनाकार हैं, जबकि वास्तव में वे एक उपभोक्ता हैं, जिन्हें बार-बार स्क्रीन पर आने के लिए आकर्षित किया जा रहा है।

सोशल मीडिया पर 'रील' का जुनून केवल व्यक्ति का बाहरी व्यवहार नहीं बदलता, बल्कि उसके भीतर की दुनिया को भी विकृत कर देता है। अब सफलता की दर प्रसिद्धि और समर्थकों की संख्या से मापी जाने लगी है। यही तत्त्व दोस्ती, प्रेम और आत्मविश्वास का पैमाना बन गए हैं। मनोचिकित्सक मानते हैं कि 'डोपामिन हिट' यानी 'रील' को पसंद करने वालों की संख्या से मिलने वाली क्षणिक खुशी अब डिजिटल नशे का रूप ले चुकी है। युवा इस भ्रम को हकीकत मानने लगे हैं कि सोशल मीडिया पर सराहना ही उनकी असली पहचान है। इस प्रवृत्ति के कारण वे वास्तविक जीवन से कटने लगे हैं, पढ़ाई और अपने कार्य में उदासीन हो गए हैं तथा मानसिक अस्थिरता का शिकार होने लगे हैं। युवाओं को यह समझना होगा कि असली पहचान स्क्रीन पर नहीं, वास्तविक जीवन में है। जितना वे अपनी प्रतिभा और संवेदनशीलता को वास्तविक समाज में लगाएंगे, उतना ही उनका अस्तित्व अर्थपूर्ण बनेगा। जरूरत है आज की युवा पीढ़ी को सही दिशा देने की, ताकि कैमरे के सामने सिर्फ दिखावे के बजाय विचार, संवेदना और परिवर्तन की सच्ची तस्वीर बने।

लोकतंत्र का पाठ

नीलम सिंह

विश्वविद्यालय शिक्षा का वह केंद्र है जहां असंख्य सपने पलते और सच होते हैं। स्कूल से निकलकर विद्यार्थी अपने सपनों की नई दुनिया साथ लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश करते है। उनके साथ उनके परिवार और समाज के सपने भी जुड़े होते हैं। विश्वविद्यालय जितना प्रतिष्ठित हो, महाविद्यालय की रैंकिंग जितनी अच्छी हो, सपने उतने ही बड़े दिखाई देते हैं। चाहे एक शिक्षक के रूप में सोचा जाए या अभिभावक के रूप में, ऐसा लगता है कि विश्वविद्यालय केवल शिक्षा प्राप्त करने का स्थान नहीं होता है, बल्कि यह युवाओं के व्यक्तित्व निर्माण का भी केंद्र होता है। इस व्यक्तित्व निर्माण की प्रकिया का एक पहलू चुनाव प्रक्रिया भी है। विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव तथा महाविद्यालयों में छात्र संघों के चुनाव के माध्यम से विद्यार्थी राजनीति की व्यावहारिक जमीन का ककहरा सीखते हैं। इस सीखने की प्रक्रिया का एक अन्य पहलू शिक्षक संघों के चुनाव भी हैं, जिसमें विद्यार्थी आमतौर पर दर्शक और प्रभावित पक्ष के रूप में होते हैं। पूरी चुनाव प्रक्रिया लगभग एक महीने चलती है और इस एक महीने सभी कालेजों की शिक्षा-दीक्षा कमोबेश प्रभावित होती है।

दुनिया मेरे आगे

> **आज जब रोजगार की चुनौतियां दिनोंदिन बढ़ती जा रही हैं, केवल राजनीतिक नारेबाजी से बच्चों को रोजगार नहीं मिलने वाला। इनकी पढ़ाई शिक्षकों के लिए भी प्राथमिकता होनी चाहिए और विद्यार्थियों को स्वयं भी इस विषय में थोड़ा संयम रखना चाहिए। उन्हें इस बात के लिए शिक्षित करने की जवाबदेही शिक्षकों की ही है।**

शिक्षकों की राजनीति के अपने दांवपेच होते हैं और चाहे-अनचाहे विद्यार्थी देखकर सीखते हैं कि किन बातों को मुद्दा बनाया जा सकता है। इस प्रक्रिया में कालेज प्रशासन से अध्यापकों की लड़ाई कई बार राजनीतिक लड़ाई में बदल जाती है और असली मुद्दे पृष्ठभूमि में चले जाते हैं। ऐसा किसी एक पक्ष में नहीं होता है। सभी पक्ष किसी न किसी रूप में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए ऐसे वादे कर जाते हैं, जिन्हें खयाली पुलाव कहा जा सकता है। हालांकि सभी इसी समाज और समाज व्यवस्था का अंग हैं। राजनीति में स्वार्थपूर्ति के लिए दोषारोपण, अतिश्योक्ति और चरित्र हनन एक सार्वजनिक तथ्य बन गए हैं। पर समस्या यह है कि राजनीति का ककहरा सीखने वाले विद्यार्थी इन शिक्षक संघों के चुनाव से सीधे-सीधे सीखते हैं। इस प्रकार शिक्षक संघ के चुनाव में फैलता जाल छात्र संघों को भी अपनी गिरफ्त में ले लेता है।

इसका सीधा असर विद्यार्थियों की उपस्थिति और पढ़ाई पर पड़ता है। जो शिक्षक महीने भर शिक्षक संघ के चुनाव में अपनी व्यस्तता की वजह से कक्षाओं से अनुपस्थित रहते हैं, वे विद्यार्थियों को चुनाव छोड़कर कक्षा में उपस्थित रहने की हिदायत कैसे दे सकते हैं। जैसे शिक्षकों की उनके चुनाव से उपस्थिति प्रभावित होती है, वैसे ही छात्र संघों के चुनाव में बच्चे कक्षाओं से बाहर प्रचार-प्रसार में लिप्त रहते हैं। यों चुनाव व्यवस्था शुरू की गई थी विद्यार्थियों में लोकतंत्र के संस्कार डालने के लिए, लेकिन पैसे और राजनीतिक प्रभाव ने छात्र संघों की चुनाव प्रक्रिया को काफी प्रभावित कर दिया है।

यह जगजाहिर हकीकत है कि कई बार विद्यार्थियों के चुनावी प्रदर्शन के कारण कालेज में प्रवेश करना भी मुश्किल हो जाता है और वे सभी विद्यार्थी एवं शिक्षक, जो इससे सीधे तौर पर न भी जुड़े हों, वे भी इससे प्रभावित होते हैं। चुनावी शोर-शराबे और गहमा-गहमी में कभी-कभी विद्यार्थी समूह आपस में भिड़ जाते हैं और पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ता है। कभी-कभी तो विद्यार्थी अपने मत से अलग मत रखने वाले शिक्षकों को निशाना बनाने से नहीं चूकते हैं। चुनाव आयोजित करना कालेज प्रशासन के लिए एक बड़ा मुद्दा रहता है।

इस प्रक्रिया में महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय की शिक्षा-दीक्षा कभी शिक्षकों के चुनाव की वजह से तो कभी विद्यार्थियों के चुनाव की वजह से प्रभावित होती रहती है। हालांकि लिंगदोह समिति ने छात्र संघों के चुनाव के नियमन के लिए कई यथोचित सुझाव दिए थे और उनकी सिफारिशें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत होने के बाद सरकारी आदेशों द्वारा लागू भी की गई, लेकिन राजनीतिक यथार्थ के धरातल पर अभी भी बहुत पारदर्शिता की आवश्यकता है। खासतौर पर चुनावों के कारण एक से दो माह के शैक्षिक वातावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए इसकी जरूरत ज्यादा महसूस होती है। एक वर्ष में एक से दो महीने का समय कम नहीं होता।

आज जब रोजगार की चुनौतियां दिनोंदिन बढ़ती जा रही हैं, केवल राजनीतिक नारेबाजी से युवाओं को रोजगार नहीं मिलने वाला। इनकी पढ़ाई शिक्षकों के लिए भी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और विद्यार्थियों को स्वयं भी इस विषय में थोड़ा संयम रखना चाहिए। उन्हें इस बात के लिए शिक्षित करने की जवाबदेही भी शिक्षकों की ही है। अगर शिक्षक संघों के चुनाव के मोहरे के तौर पर विद्यार्थियों का उपयोग होगा या शिक्षक अपने आचरण से छात्रों में संस्कार नहीं जगा सके तो सिर्फ गिरावट का रोना रोने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।

कुल मिलाकर छात्र संघों के चुनाव, जो छात्रों में राजनीतिक और लोकतांत्रिक संस्कार भरने का उद्देश्य लेकर शुरू हुए थे, उनके सकारात्मक पहलुओं पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। हमारे मौलिक अधिकार और कर्तव्यों में जिस प्रकार संतुलन की अपेक्षा की जाती है, इसी प्रकार विद्यार्थियों के हित-अहित के व्यापक संदर्भ में चुनावों के नियमन की भी आवश्यकता है। इस संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन, महाविद्यालय और शिक्षक संघ तीन ऐसे महत्त्वपूर्ण पक्ष हैं, जो एक दूसरे के पूरक हैं। छात्र संघों के चुनाव में किस प्रकार ऐसे सुधार लाए जाएं कि छात्रों में लोकतांत्रिक संस्कार भी बने और उनकी पढ़ाई-लिखाई का भी नुकसान न हो, इस पर गहन विचार की आवश्यकता है। अन्यथा अगर पहली सीढ़ी पर ही हिंसा और धन की राजनीति कार्य करने लगी तो न केवल छात्र राजनीति, बल्कि देश की राजनीतिक व्यवस्था पर भी इसके दूरगामी प्रभाव होंगे।

लापरवाही की हद

'जवाबदेही के बजाय' (संपादकीय, 13 अक्तूबर) पढ़ा। पश्चिम बंगाल में गिरती कानून व्यवस्था चिंता का विषय है। राज्य के दुर्गापुर में एक मेडिकल कालेज की छात्रा से सामूहिक बलात्कार की घटना पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के बजाय कहा कि लड़कियां देर रात बाहर न निकलें। उनका यह बयान अपराधियों के मनोबल को बढ़ाने वाला है। पश्चिम बंगाल के शैक्षणिक संस्थानों में इस तरह की घटनाएं चिंता बढ़ा रही हैं। हर बार बंगाल पुलिस की भूमिका पर सवाल उठता है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कालेज में महिला चिकित्सक से बलात्कार और हत्या की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। देशभर में उपजे आक्रोश की वजह से उस मामले की जांच सीबीआइ को सौंपनी पड़ी। यह अफसोस की बात है कि राज्य में महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद महिलाओं के खिलाफ अपराध में बढ़ोतरी हो रही हैं। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा की संस्कृति फल-फूल रही है।

– हिमांशु शेखर, गयाजी

सिद्धांत बनाम राजनीति

गठबंधन की राजनीति में सीटों का बंटवारा और टिकट वितरण में जिस तरह की राजनीति उभर कर सामने आ रही है। अंदाजा लगाना कोई मुश्किल नहीं कि जिस किसी भी दल या गठबंधन की सरकार बनेगी, उसके लिए सुशासन कायम करना टेढ़ी खीर साबित होगी। सवाल है कि इस परिदृश्य में सुधार कैसे होगा? जब हमारी राजनीति सिद्धांतों पर आधारित होगी। उसमें विचारधारा का महत्त्वपूर्ण स्थान होगा। सत्ता सेवा का पर्याय बनेगी, तभी कुछ तस्वीर बदलेगी। आज के दौर में यह कैसे होगा। इस पर दलों को विचार करना होगा। दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीति का भी व्यवसायीकरण हो रहा है और सत्ता इसे साधने का उपक्रम भर है। यही कारण है टिकट वितरण और सीट बंटवारे में रूठने-मनाने का खेल चलता है। एक समय था, जब स्वाधीनता आंदोलन में संघर्ष और सेवा का दौर था। तब इस कदर होड़ नहीं थी। त्याग करने वालों की कमी नहीं थी। आज तो लगता है कि सब कुछ बदल गया है।

– मुकेश कुमार मनन, पटना

महंगाई की रफ्तार

सोना और चांदी इस समय रेकार्ड ऊंचाई पर पहुंच गए हैं, लेकिन इस उछाल के पीछे सामान्य मांग नहीं, बल्कि चांदी में हुए 'शार्ट स्क्वीज' को मुख्य कारण माना जा रहा है। इसे वित्तीय जगत में उस स्थिति को कहते हैं, जब कुछ निवेशक यह अनुमान लगा कर किसी वस्तु या शेयर को पहले ही बेच देते हैं कि आगे उसकी कीमत गिरेगी। मगर जब स्थिति पलट जाती है और कीमत तेजी से बढ़ने लगती है, तो वे अपने घाटे से बचने के लिए हड़बड़ी में उसे वापस खरीदने लगते हैं। इससे मांग अचानक बढ़ जाती है और कीमतें और अधिक ऊंची चली जाती हैं। चांदी के बाजार में ठीक यही स्थिति बनी। विश्लेषकों का कहना है कि पिछले कुछ हफ्ते से चांदी की कीमतों में गिरावट की उम्मीद में कई बड़े निवेशकों ने बिक्री की थी, परंतु औद्योगिक मांग, निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी और अन्य गतिविधियों ने स्थिति पलट दी। नतीजा चांदी की कीमतें तेजी से ऊपर गईं और सोना भी उसके साथ रेकार्ड स्तर पर पहुंच गया।

– विभूति बुपक्या, खाचरौद, मप्र

मिलावट बदस्तूर

हाल ही में मध्यप्रदेश और राजस्थान में मिलावट, निम्न गुणवत्ता और नकली दवाओं के मामले सामने आए। अब जैसे ही त्योहारों का समय शुरू हुआ, खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई से मिलावटी मावा-खोया इत्यादि बरामद होने लगे हैं। खबर है कि गोरखपुर से भी लगभग एक हजार किलो नकली खोया बरामद हुआ। हालांकि हर वर्ष खाद्य सुरक्षा विभाग त्योहारी मौसम में सक्रिय होता है, परंतु मिलावट का खेल बदस्तूर जारी रहता है। ध्यान देने की बात है कि यह कार्रवाई पहले नहीं होती। यह गंभीर चिंता का विषय है कि आखिर क्या कारण है कि मिलावटखोरों को कानून का कोई भय नहीं है। जब तक मिलावट रोकने के लिए और सख्त कानून नहीं बनाया जाता, तब तक इस पर अंकुश नहीं लगेगा। कानून इतना कठोर हो कि एक बार गिरफ्त में आने के बाद अपराधी भविष्य में मिलावट के विषय में सोच भी न सके।

– मनोज पुरुषार्थी, मेरठ

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

बिहार में नामांकन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दी हरी झंडी

अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने की अनुमति

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 16 अक्तूबर।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बिहार में नामांकन के बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने की अनुमति दे दी है। चुनाव आयोग ने एसआइआर 2025 को निष्पक्ष बताया और याचिकाकर्ता एडीआर पर प्रक्रिया बाधित करने का आरोप लगाया। आयोग ने कहा कि फर्जी हलफनामों से अदालत को गुमराह किया जा रहा है।

मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जायमाल्या बागची की पीठ से गुरुवार को आयोग ने कहा कि बुर्कानशीन महिला मतदाताओं के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। पीठ अब इस मामले पर चार नवंबर को सुनवाई करेगी।

सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने कहा कि पहले और दूसरे चरण के नामांकन के बाद ही अंतिम मतदाता सूची वेबसाइट पर डाली जाएगी। कोर्ट ने इस पर सहमति जता दी। इससे पहले चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में

चुनाव आयोग ने एडीआर और योगेंद्र यादव पर एसआइआर को बाधित करने का आरोप लगाया। आयोग ने कहा कि झूठे हलफनामों से कोर्ट को गुमराह किया गया। जांच रपट में दावा है कि कई हलफनामे फर्जी या धोखे से लिए गए। सभी याचिकाएं निरर्थक हैं, इसे खारिज की जाए।

151 पन्नों का हलफनामा दाखिल किया। चुनाव आयोग ने कहा कि एसआइआर 2025 निष्पक्ष तरीके से पूरा किया गया। आयोग ने एडीआर और योगेंद्र यादव पर एसआइआर को बाधित करने का आरोप लगाया। आयोग ने कहा कि झूठे हलफनामों से कोर्ट को गुमराह किया गया। जांच रपट में दावा है कि कई हलफनामे फर्जी या धोखे से लिए गए। सभी याचिकाएं निरर्थक हैं, इसे खारिज की जाए।

आयोग ने कहा कि दाखिल हलफनामे पर हम अलग से जवाब देंगे और उन्होंने जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय मांगा है और उन्हें यह समय प्रदान किया गया है। सुनवाई के दौरान वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि मैं बस अपने द्वारा दिए गए हलफनामे का जिक्र करना चाहता हूं। हमने उस मतदाता के सभी विवरणों का सत्यापन करके हलफनामा दाखिल कर दिया है।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि इसका मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ता। वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि उन्हें मेरे हस्तक्षेप पर जवाब दाखिल करना था। हम डेटा पर काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि हम अलग से जवाब दाखिल करेंगे। भूषण ने कहा कि जहां तक बिहार का सवाल है, अब जांच करना मुश्किल होगा।

आयोग ने कहा कि हम सब कुछ वेबसाइट पर डालते हैं

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर (ब्यूरो)।

चुनाव आयोग ने कहा कि हम सबकुछ वेबसाइट पर डालते हैं। अभी लोग जुड़ रहे हैं। इस प्रक्रिया के खत्म होने पर ही वेबसाइट पर डाला जाएगा। चुनाव आयोग ने कहा कि वोटर सब जानते हैं, संतुष्ट हैं लेकिन एडीआर को विश्लेषण के लिए सब तुरंत चाहिए। पहले फेज की प्रक्रिया 17 अक्तूबर और 20 अक्तूबर को दूसरे चरण की प्रक्रिया पूरी होगी। तब सूची वेबसाइट पर जारी की जाएगी।

पीठ ने कहा कि उम्मीद है कि चुनाव आयोग बिहार की अंतिम मतदाता सूची में टाइपिंग और अन्य गलतियों को सुधारेगा। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने कहा कि 30 सितंबर को उनके द्वारा प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची को लेकर अभी तक एक भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई है।

बिहार में भाजपा के मोदी, योगी व शाह समेत 40 प्रमुख प्रचारक

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 16 अक्तूबर।

बिहार के पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया जल्द ही पूर्ण होगी। इस प्रक्रिया के साथ ही चुनावी प्रचार में भी तेजी आएगी। बिहार चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत चालीस बड़े चेहरों को इस बार के चुनाव प्रचार में उतारने का निर्णय लिया है। ये 40 नेता बिहार में पहले चरण के मतदान के लिए बतौर प्रमुख प्रचारक उतरेंगे और भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे।

भाजपा ने चुनाव के लिए प्रमुख प्रचारकों की सूची तैयार की। इसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत पूर्वांचल के सितारे भी हैं शामिल।

पहले चरण के तहत कुल 121 सीटों के लिए चुनाव कराए जाने हैं। इस चरण के लिए भाजपा व सहयोगी दल पहले ही अपने उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं। नामांकन प्रक्रिया खत्म होते ही सबसे इन सीटों पर प्रचार में तेजी आएगी। भाजपा ने इस चरण के प्रचार के लिए अपने प्रमुख नेताओं समेत ऐसे चेहरों को भी जगह दी है, जो कि बिहार में अपनी अलग पहचान रखते हैं। इसमें कला व संगीत जगत चेहरे भी हैं। इनमें भोजपुरी गायक, अभिनेता व सांसद मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल (निरहुआ) शामिल हैं। बिहार में इसी बीच छठ के त्योहार की भी धूम रहने वाले है, जो कि इस प्रचार में साफ नजर आएगा। इन नेताओं को इस सूची में शामिल करके पार्टी ने यह तैयारी कर ली है।

इस सूची में सबसे अलग नजर आने वाले नामों में दिल्ली की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का नाम भी शामिल हैं। प्रमुख प्रचारकों की सूची भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, शिवराज चौहान, धर्मेंद्र प्रधान, गिरिराज सिंह, हिमंत बिस्व सरमा, केशव प्रसाद मौर्य, रेणु देवी, नित्यानंद राय, राधा मोहन सिंह, अश्विनी कुमार चौबे, नंद किशोर यादव समेत अन्य नामी चेहरों को शामिल किया गया है।

जद (एकी) की दूसरी सूची में 44 नाम घोषित

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 16 अक्तूबर।

बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रमुख घटक जनता दल (एकीकृत) ने बुधवार को 44 उम्मीदवारों की दूसरी और अंतिम सूची जारी की। उसने एक दिन पहले 57 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। इसके साथ ही पार्टी ने अपने कोटे की सभी 101 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं।

उम्मीदवारों में आधे से अधिक प्रत्याशी अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) और अति पिछड़े वर्ग (ईबीसी) से हैं। पार्टी ने चार मुस्लिम प्रत्याशी भी उतारे हैं। जद (एकी) ने इस बार केवल 13 महिलाओं को टिकट दिया है, जो कुल उम्मीदवारों का 15 फीसद से भी कम है।

नीतीश ने फिर जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश की है। पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग सभी को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया है।

राजग के घटक दल के रूप में जद (एकी) 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जद (एकी) ने अपने प्रत्याशियों का जातिगत वर्गीकरण भी सार्वजनिक किया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पार्टी का मुख्य ध्यान पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग ही बना हुआ है।

कुल 101 उम्मीदवारों में 37 ओबीसी और 22 ईबीसी वर्ग से हैं। इसके अलावा 22 उम्मीदवार सवर्ण समुदाय से हैं, जबकि चार मुस्लिम प्रत्याशियों को सूची में भी जगह दी गई है। पार्टी को लेकर ऐसी धारणा बन रही थी कि भाजपा के साथ लंबे गठबंधन और वक्फ जैसे संवेदनशील मुद्दों पर स्वतंत्र रुख न ले पाने के कारण जद (एकी) अब अल्पसंख्यक मतदाताओं से दूरी बना रही है।

जद (एकी) ने अपनी दूसरी सूची में चार मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देकर अपनी 'संतुलित राजनीति' का संदेश देने का प्रयास किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली पार्टी ने अररिया से शगुफ्ता अजीम, जोकीहाट से मंजर आलम, अमौर से सबा जफर और चैनपुर से जमा खान को उम्मीदवार बनाया है।

खान 2020 विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) से बिहार में इकलौते विधायक बने थे और बाद में उन्होंने जद (एकी) का दामन थाम लिया। वर्तमान में पह अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं।

मिलन पटना में गुरुवार को नामांकन के दौरान बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार नितिन नवीन के साथ सांसद अनुराग ठाकुर।

जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील पर अवमानना कार्यवाही की मंजूरी

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर (ब्यूरो)।

अटार्नी जनरल (एजी) ने भारत के प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई पर जूता फेंकने का प्रयास करने वाले वकील के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने की सहमति दे दी है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में सूचित किया गया।

सालिसिटर जनरल तुषार मेहता और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के प्रमुख एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जे बागची की पीठ से अनुरोध किया कि प्रधान न्यायाधीश पर जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर के खिलाफ अवमानना मामले की सुनवाई की जाए।

पीठ ने कहा कि भाषण और अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार दूसरों की गरिमा की कीमत पर नहीं हो सकता है।

सिंह ने कहा कि छह अक्तूबर को हुई इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर अनगिनत सामग्री प्रसारित हुई है, जो संस्थागत अखंडता और गरिमा को ठेस पहुंचा रही है। मेहता और सिंह ने अदालत से सोशल मीडिया पर ऐसी सामग्री पोस्ट करने पर रोक से संबंधी आदेश पारित करने का अनुरोध करते हुए कहा कि हर तरह की अपमानजनक टिप्पणियां की जा रही हैं। पीठ ने कहा कि भाषण और अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार दूसरों की गरिमा की कीमत पर नहीं हो सकता है। इसने सोशल मीडिया की अनियमित प्रकृति के दुष्प्रभावों की ओर इशारा किया और कहा, 'हम सामग्री के उत्पाद और उपभोक्ता दोनों हैं'। प्रधान न्यायाधीश पर जूता फेंकने के प्रयास की यह अभूतपूर्व घटना छह अक्तूबर को हुई।

राजग बिहार चुनाव नीतीश के नेतृत्व में लड़ेगा, मुख्यमंत्री का फैसला बाद में : शाह

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर (ब्यूरो)।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के सहयोगी दल बिहार विधानसभा चुनाव जद (एकी)अध्यक्ष नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। उन्होंने साथ ही कहा कि अगली सरकार का नेतृत्व कौन करेगा, इसका फैसला चुनाव के बाद निर्वाचित विधायकों द्वारा लिया जाएगा।

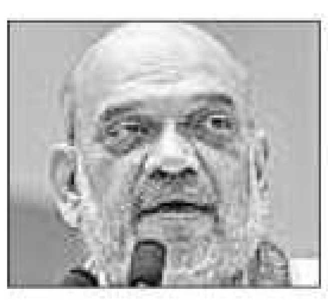

शाह ने नीतीश कुमार को भारतीय राजनीति का एक प्रमुख समाजवादी नेता बताते हुए कहा कि जनता दल (एकी) अध्यक्ष की राजनीति हमेशा कांग्रेस विरोधी रही है और वह जेपी आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे और उन्होंने आपातकाल के दौरान कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा के लिए दो चरणों में 6 नवंबर और 11 नवंबर को मतदान होगा और मतगणना 14 नवंबर को होगी। शाह ने दावा किया कि आगामी 14 नवंबर को जब परिणाम आएंगे, तो राजग सभी पुराने रेकार्ड तोड़ देगा।

गृह मंत्री ने कहा कि मैं यह तय करने वाला नहीं हूं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं। फिलहाल हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव के बाद सभी सहयोगी दल बैठकर अपने नेता का चयन करेंगे। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद स्वयं नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया था कि भाजपा की सीटें अधिक होने के कारण मुख्यमंत्री भी उसका ही होना चाहिए।

उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता सासाराम से लड़ेंगी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 16 अक्तूबर।

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के घटक राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने चार उम्मीदवारों की सूची गुरुवार को जारी की। पार्टी ने बताया कि वह छह विधानसभा सीटों बाजपट्टी (सीतामढ़ी), मधुबनी, पारू (मुजफ्फरपुर), उजियारपुर (समस्तीपुर), सासाराम (रोहतास) और दिनारा (रोहतास) से चुनाव लड़ेगी।

रालोमो द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, पार्टी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता सासाराम से चुनाव लड़ेंगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता माधव आनंद को मधुबनी, प्रशांत कुमार पंकज को उजियारपुर और आलोक कुमार सिंह को दिनारा से उम्मीदवार बनाया गया है। राजग के घटक दलों के बीच हुए सीट बंटवारे

के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और जनता दल (एकी) को 101-101 सीटें, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को 29 सीटें दी गई हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) और रालोमो को छह-छह सीटें मिली हैं। भाजपा और जद (एकी) दोनों ही अपने सभी 101-101 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी हैं।

अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी रालोजपा, 25 उम्मीदवारों की घोषणा : विपक्षी गठबंधन में जगह नहीं मिलने के बाद पशुपति पारस के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी(रालोजपा) ने 25 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी की इस सूची में जद(एकी) की पूर्व विधायक पूनम यादव का नाम शामिल हैं जो खगड़िया से चुनावी समर में उतरेंगी। वह इससे पहले चार बार विधायक रह चुकी हैं, लेकिन जद(एकी) से टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने रालोजपा का दामन थाम लिया है।

छपरा से राजद के प्रत्याशी होंगे खेसारी लाल : बिहार विधानसभा चुनाव में उतरने की भोजपुरी कलाकार खेसारी लाल यादव की तैयारी है। लंबे समय से जारी अटकलों के बीच खेसारी लाल यादव ने राजद के टिकट पर छपरा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है। पहले उन्होंने कहा था कि फिल्मी करिअर की वजह से अपनी पत्नी चंदा देवी को विधानसभा चुनाव में उतारना चाहते हैं। लेकिन, चंदा देवी के इनकार के बाद खेसारी लाल यादव ने खुद चुनावी समर में उतरने का फैसला लिया है। सीट बंटवारा से पहले ही राजद अपने 48 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर चुका है और नामांकन की प्रक्रिया भी जारी है। इससे पहले भोजपुरी सिनेमा के कलाकार पवन सिंह ने इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था।

पेज 1 का बाकी

मोदी ने विश्वास दिलाया नहीं खरीदेंगे रूस से तेल, सरकार ने कहा झूठ

अमेरिका अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के युद्ध के लिए धन मुहैया कराने के रूप में देखता है। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात से खुशी नहीं हुई कि भारत तेल खरीद रहा है। जायसवाल ने कहा कि भारत द्विपक्षीय ऊर्जा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए ट्रंप प्रशासन के साथ बातचीत कर रहा है। उन्होंने कहा, 'जहां तक अमेरिका का सवाल है, हम कई वर्षों से अपनी ऊर्जा खरीद का विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं।

पिछले एक दशक में इसमें लगातार प्रगति हुई है।' उन्होंने कहा, 'भारत तेल और गैस का महत्वपूर्ण आयातक है। अस्थिर ऊर्जा परिदृश्य में भारतीय उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना हमारी निरंतर प्राथमिकता रही है।' वाशिंगटन लगातार यह कहता रहा है कि भारत रूसी कच्चे तेल की खरीद के जरिए पुतिन को युद्ध के वित्तपोषण में मदद कर रहा है। ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर शुल्क को दोगुना करके 50 प्रतिशत कर देने के बाद नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच संबंधों में गंभीर तनाव आ गया। भारत ने अमेरिकी कार्रवाई को अनुचित और अविवेकपूर्ण बताया। अमेरिका के नामित राजदूत सर्जियो गोर ने पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद कहा था कि अमेरिका भारत के साथ अपने संबंधों की कद्र करता है।

नामांकन के चंद घंटे बाकी, महागठबंधन में रार बरकरार

वामपंथी दलों जैसे सहयोगियों को शामिल करने की जरूरत का हवाला दिया। दूसरी ओर, राहुल गांधी और खरगे का जोर इस बात पर है कि बिहार में मतदाता अधिकार यात्रा के बाद कांग्रेस में उत्साह है और वह लगभग 60 सीटें जीत सकती है। वर्ष 2020 में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 19 सीटों पर जीत हासिल की थी।

कांग्रेस के एक सूत्र ने कहा, 'दोनों पार्टियां कहलगांव, वैशाली और जाले सीटों पर दावा कर रही हैं।' वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में भागलपुर जिले की कहलगांव सीट पर कांग्रेस ने राजद के साथ गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा था। वहां से भाजपा के पवन कुमार यादव जीते, जबकि कांग्रेस के शुभानंद मुकेश 42,893 मतों से हार गए। इस बार, राजद ने कहलगांव सीट से एक यादव उम्मीदवार को टिकट देने का वादा किया था। कांग्रेस को आपत्ति है कि इस बारे में राजद ने सलाह-मशविरा नहीं किया। इसके बाद तेजस्वी ने कहलगांव से अपने विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करने का फैसला किया। रैली में तेजस्वी के साथ राजद के चुने हुए उम्मीदवार रजनीश यादव भी थे, जो झारखंड के मंत्री संजय यादव के बेटे हैं।

वैशाली जिले की वैशाली सीट पर भी कांग्रेस ने 2020 में चुनाव लड़ा था। यहां, वह अपने उम्मीदवार संजीव सिंह को दोहराना चाहती है, जो 2020 में जद (एकी) के सिद्धार्थ पटेल से 7,413 वोटों के मामूली अंतर से हार गए थे। कांग्रेस इस बात पर जोर दे रही है कि उसे कम से कम वे सीटें जरूर मिलें, जो उसने 2020 में जीते थे या जहां वह दूसरे स्थान पर रही थी।

दरभंगा जिले की जाले सीट से कांग्रेस मोहम्मद नौशाद आलम को मैदान में उतारना चाहती है। अगस्त में मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाली रैली का आयोजन उन्हीं के द्वारा किया गया था। इस मुद्दे पर भाजपा द्वारा हंगामा मचाने के बाद, कांग्रेस आलम को टिकट देकर एक संदेश देना चाहती है।

हालांकि, राजद नेतृत्व का मानना है कि यह कदम उल्टा साबित हो सकता है और राज्य भर में राजग को फायदा पहुंचा सकता है। इन तीन सीटों के अलावा, सहयोगी दलों द्वारा लड़ी जाने वाली कुल सीटों की संख्या को लेकर भी मतभेद जारी है। सहनी 20 सीटों के प्रस्ताव से नाराज हैं, जबकि वह उससे दोगुनी सीटें चाहते हैं। लेकिन वीआइपी को ज्यादा सीटें मिलने से वामपंथियों में नाराजगी हो सकती है। फिलहाल, भाकपा (माले) को भी 20 सीटों की पेशकश की जा रही है। उसने पिछली बार 12 सीटें जीती थीं। महागठबंधन के अन्य सहयोगियों में से दो-दो सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा और पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को मिलने की उम्मीद है। अभी भी समझौता लंबित रहने के बीच, कांग्रेस ने बुधवार रात 13 उम्मीदवारों के नाम एक्स पर जारी कर सबको चौंका दिया, जिनमें कुटुम्बा सीट से प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम भी शामिल थे। महागठबंधन की सीटों के बटवारे पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि सहमति बनने के बाद ही चिह्न दिए जा रहे हैं। गठबंधन में सबको अपनी बात रखने का मौका दिया गया है। प्रक्रिया में समय लग रहा है। वहीं, विकासशील इंसान पार्टी (वीआइपी) के प्रवक्ता सुनील सिंह ने कहा कि सीट बंटवारे को लेकर कुछ जटिलताएं थी। इसमें राहुल गांधी ने हस्तक्षेप किया था और भरोसा दिलाया कि आपसी सहमति से इसका समाधान निकाला जाएगा।

आयोग ने बुर्काधारी महिलाओं की पहचान के कदम का बचाव किया

पहनकर आने वाली महिला मतदाताओं की पहचान के लिए एक सम्मानजनक तरीका अपनाने का आदेश दिया था। यह आदेश 21 अक्तूबर 1994 को जारी हुआ था। आदेश में कहा गया था कि महिला मतदाताओं की गोपनीयता के प्रति संवेदनशीलता की रक्षा के लिए मतदान केंद्र में पर्दानशीं महिलाओं की पहचान के लिए अलग घेरा बनाया जाना चाहिए। वर्ष 1994 में निर्वाचन आयोग ने रीति-रिवाजों और परंपराओं के कारण महिला मतदाताओं के कम मतदान पर चिंता व्यक्त करते हुए यह आदेश जारी किया था।

निर्वाचन आयोग ने कहा है कि बिहार में मतदान केंद्रों पर बुर्का या घूंघट वाली महिला मतदाताओं की गरिमापूर्ण पहचान के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। पिछले सप्ताह एक बयान में निर्वाचन आयोग ने कहा कि पर्दानशीं महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित

बिहार में 243 विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव दो चरणों में छह और 11 नवंबर को होंगे, जबकि मतगणना 14 नवंबर को होगी जबकि मतगणना 14 नवंबर को होगी।।

करने के लिए महिला मतदान अधिकारियों या परिचारिकाओं की उपस्थिति में उनकी गरिमापूर्ण पहचान के लिए उनके निर्देशों के अनुसार मतदान केंद्रों पर विशेष व्यवस्था की जाएगी तथा उनकी निजता सुनिश्चित की जाएगी।

बिहार विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए छह अक्तूबर को संवाददाता सम्मेलन में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बुर्का पहनकर आने वाली मतदाताओं की पहचान सत्यापित करने में मदद के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर मौजूद रहेंगी। घूंघट और बुर्के वाली महिलाओं के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में कुमार ने कहा था कि मतदान केंद्रों के अंदर पहचान के सत्यापन के बारे में निर्वाचन आयोग के स्पष्ट दिशानिर्देश हैं और उनका सख्ती से पालन किया जाएगा। आयोग ने हाल में कहा था कि 90,712 आंगनबाड़ी सेविकाओं को चुनाव ड्यूटी पर तैनात किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की बिहार इकाई के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने हाल में आयोग से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि बुर्का पहनकर मतदान केंद्रों पर आने वाली महिलाओं के चेहरों का मिलान मतदाता पहचान पत्रों से किया जाए। बिहार में 243 विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव दो चरणों में छह और 11 नवंबर को होंगे, जबकि मतगणना 14 नवंबर को होगी। बुर्का पहनकर मतदान केंद्रों पर आने वाली महिलाओं के चेहरों का मिलान मतदाता पहचान पत्रों से किया जाए।

पंजाब पुलिस के डीआइजी हरचरण सिंह भुल्लर गिरफ्तार

किया है, जोकि भुल्लर का सहयोगी बताया जा रहा है। सीबीआइ ने जब भुल्लर के कार्यालय और आवास पर तलाशी ली तो लगभग पांच करोड़ रुपए नकद जब्त किए। नोट गिनने के लिए कई मशीनें मंगवाई गई। इसके अलावा 1.5 किलोग्राम वजन के आभूषण, संपत्ति के दस्तावेज, दो लग्जरी वाहन (मर्सिडीज और आडी) की चाबियां, 22 लग्जरी घड़ियां, लाकर की चाबियां, 40 लीटर आयातित शराब, कुछ हथियार व गोला-बारूद भी जब्त किया। गिरफ्तार किए गए बिचौलिए के परिसर से 21 लाख रुपए की अतिरिक्त नकदी जब्त की गई।

2009 बैच के आइपीएस अधिकारी हरचरण सिंह भुल्लर पर आरोप है कि उन्होंने मंडी गोबिंदगढ़ के एक कबाड़ कारोबारी आकाश बट्टा के खिलाफ दर्ज 2023 की एफआइआर को 'निपटाने' के लिए अपने बिचौलिए कृष्णु के माध्यम से मासिक रिश्वत के अलावा आठ लाख रुपए मांगे थे। बदले में, यह सुनिश्चित किया जाना था कि कबाड़ कारोबारी के व्यवसाय के खिलाफ आगे कोई बलपूर्वक या प्रतिकूल पुलिस कार्रवाई न की जाए।

जानकारी पाकर सीबीआइ ने जाल बिछाया और चंडीगढ़ के सेक्टर 21 में डीआइजी की ओर से शिकायतकर्ता से आठ लाख रुपए की मांग और स्वीकार करते हुए एक निजी व्यक्ति को रंगे हाथों पकड़ लिया।

एजंसी के एक प्रवक्ता ने कहा कि कार्रवाई के दौरान, डीआइजी को एक काल किया गया, जिस दौरान उसने भुगतान स्वीकार किया और बिचौलिए और शिकायतकर्ता को अपने कार्यालय आने का निर्देश दिया। बाद में सीबीआइ ने भुल्लर मोहाली स्थित उसके कार्यालय से गिरफ्तार किया। साथ ही एक अन्य आरोपी को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया। पटियाला रेंज के डीआइजी के रूप में सेवा देने के बाद भुल्लर को 27 नवंबर, 2024 को रोपड़ रेंज के डीआइजी का पदभार दिया गया था। वे पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) मेहल सिंह भुल्लर के बेटे हैं। उन्होंने 2021 में शिरोमणि अकाली दल (शिअद) नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ नशे से जुड़े मामले की जांच करने वाले एक विशेष जांच दल का भी नेतृत्व किया।

राज्यसभा चुनाव में फर्जीवाड़े से भी जुड़ा मामला :डीआइजी रोपड़ रेंज की गिरफ्तारी उस समय हुई है जब मंगलवार को ही रोपड़ पुलिस और चंडीगढ़ में अपने समकक्षों के बीच नवनीत चतुर्वेदी की गिरफ्तारी को लेकर टकराव हुआ था। जयपुर के रहने वाले चतुर्वेदी ने पंजाब से राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया था। रोपड़ पुलिस ने हाल ही में चतुर्वेदी पर जालसाजी के आरोप में मामला दर्ज किया था। इस मामले में कई आप विधायकों ने दावा किया था कि चतुर्वेदी ने नामांकन पत्रों पर उनके जाली हस्ताक्षर किए हैं। मंगलवार को जब रोपड़ पुलिस ने चतुर्वेदी को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो चंडीगढ़ पुलिस ने उन्हें सौंपने से इनकार कर दिया।

तैयारी • शहर में भूजल स्तर सुधारने की कवायद, एफएमडीए करा रहा सर्वे

शहर में गिरते भूजल स्तर की एजेंसी कर रही जांच, जलस्तर बढ़ाने के होंगे प्रयास

दुर्गेश कुमार झा | फरीदाबाद

15 वर्षों मे 60 फीट नीचे गिरा भूजल स्तर

फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (एफएमडीए) ने शहर में भूजल स्तर सुधारने की कवायद शुरू की है। एक विशेषज्ञ एजेंसी के सहयोग से शहर में गिरते भूजल स्तर की जांच की जा रही है। पता लगाया जा रहा है कि शहर में पेयजल की कमी लगातार क्यों बढ़ रही है। अभी फरीदाबाद को रोज करीब 450 मिलियन लीटर (एमएलडी) पानी की आवश्यकता है। जबकि आपूर्ति लगभग 280 एमएलडी है। इससे शहर को रोज 170 एमएलडी पानी कम मिल रहा है। गर्मी में यह कमी और अधिक हो जाती है। कई कालोनियों में पानी का दबाव घट जाता है। इससे लोगों को मजबूरी में टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ता है। इस सर्वे में यमुना और बुढ़िया नाले के किनारे ऐसे स्थलों की जांच की जा रही है जहां बारिश के पानी को जमीन के भीतर पहुंचाया जा सके। इस परियोजना का उद्देश्य शहर के जलस्तर में सुधार लाकर भविष्य के जलसंकट को कम करना है।

फरीदाबाद में 15 वर्षों में भूजल स्तर औसतन 45 से 60 फीट नीचे चला गया। जबकि कुछ क्षेत्रों में यह गिरावट 100 से 150 फीट तक है। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर यह रफ्तार जारी रही तो आने वाले वर्षों में कई इलाकों में पानी निकालना मुश्किल हो जाएगा।

एफएमडीए द्वारा किए जाने वाले सर्वे में शहर के अंदर और बाहरी हिस्सों में करीब 1750 ट्यूबवेल की जांच कराई जाएगी। इनमें से लगभग 450 ट्यूबवेल को जलापूर्ति के लिए और 1300 के करीब स्थानों को रिचार्ज प्वाइंट के रूप में चिह्नित किया जाएगा। एजेंसी इन स्थानों की भौगोलिक और भूगर्भीय स्थिति का अध्ययन करेगी। जिससे बरसात का पानी जमीन में समा सके और भूजल स्तर में सुधार हो। यमुना और बुढ़िया नाले के आसपास रिचार्ज जोन बनाकर बारिश का जल संरक्षण करने का काम किया जाएगा।

जलस्तर बढ़ने पर मिलेगी बड़ी राहत

एफएमडीए के सर्वे के बाद किए जाने वाले सुधारात्मक कार्य से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इससे पानी की आपूर्ति में सुधार होगा और भूमिगत जल पर निर्भरता कम होगी। विशेषज्ञों का कहना है अगर यह योजना सफल रहती है तो आने वाले तीन वर्षों में फरीदाबाद के कई इलाकों में भूजल स्तर में 5 से 8 फीट तक सुधार देखने को मिल सकता है।

33 तालाबों का किया जा चुका जीर्णोद्धार

अमृत सरोवर योजना के तहत प्रत्येक जिले में 75 तालाबों का निर्माण या पुनरुद्धार किया जाना है। इस योजना के तहत जिले में फरवरी तक 33 तालाबों का पुनरुद्धार किया गया। इन तालाबों का क्षेत्रफल लगभग 1 एकड़ और जलधारण क्षमता लगभग 10 हजार घनमीटर है। इसके अलावा एफएमडीए ने यमुना नदी के किनारे स्थित 50 गांवों में नए तालाबों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा है। यह पहल जल पुनर्भरण और भूजल स्तर को सुधारने के उद्देश्य से की जा रही है। इससे लोगों को काफी लाभ मिलेगा।

फरीदाबाद में पानी की आपूर्ति को बेहतर करने का कार्य किया जा रहा है। फरीदाबाद की जनसंख्या और औद्योगिक विस्तार के चलते जल की मांग हर साल बढ़ रही है। इसे देखते हुए एफएमडीए बड़े स्तर पर काम कर रहा है। सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। आगे की प्रक्रिया भी जल्द पूरी कर ली जाएगी।
-अंकित भारद्वाज, एक्जिक्यूटिव इंजीनियर एफएमडीए

दिवाली केवल दीपों का त्योहार नहीं, बल्कि सद्भाव का भी हैः गोयल

दिवाली पर सरकारी स्कूल के बच्चों को मिठाई बांटते कैबिनेट मंत्री।

भास्कर न्यूज | फरीदाबाद

हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने गुरुवार को 28 सरकारी स्कूलों के हजारों बच्चों के साथ दिवाली मनाई। इस दौरान उन्होंने 15 हजार देशी घी के लड्डू वितरित कर बच्चों को खुशियों की सौगात दी। इस मौके पर गोयल ने कहा कि त्योहारों का असली अर्थ तभी है जब समाज के हर वर्ग के साथ खुशियां बांटी जाएं। बच्चे हमारे भविष्य हैं। उन्होंने कहा दिवाली केवल दीपों का त्योहार नहीं, बल्कि सेवा, सहयोग और सद्भाव का प्रतीक है। उन्होंने शिक्षकों से भी अपील की है कि वे बच्चों में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और समाजसेवा की भावना को बढ़ावा दें। कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने स्वच्छ दिवाली, हरित दिवाली का संकल्प भी लिया।

यमुना नदी की सफाई शुरू, छठ पर दो लाख से अधिक श्रद्धालु जुटेंगे

एडीसी सतबीर मान की बैठक, अपशिष्ट को नहीं बहाने की हिदायत

भास्कर न्यूज | फरीदाबाद

दिल्ली से सटे बसंतपुर, ददसिया आदि इलाके में यमुना किनारे दो लाख से अधिक श्रद्धालु इस बार छठ महापर्व मनाएंगे। जिला प्रशासन ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। गुरुवार को हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने निर्देश पर एडीसी ने अधिकारियों को समय रहते यमुना की सफाई करने का आदेश दिया। साथ ही यमुना को प्रदूषण मुक्त रखने का निर्देश भी दिया। 25 अक्टूबर को नहाय खाय के साथ छठ महापर्व शुरू हो रहा है। 26 अक्टूबर को खरना, 27 अक्टूबर को शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्य और 28 अक्टूबर को उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। अनुमान है इस बार दो लाख से अधिक श्रद्धालु छठ महापर्व मनाने आएंगे। गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी जिला उपायुक्तों के साथ बैठक कर निर्देश दिए कि किसी भी स्थिति में अनुपचारित जल या औद्योगिक अपशिष्ट यमुना नदी में न छोड़ा जाए। यमुना नदी के किनारे स्थापित सभी एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) पूर्ण क्षमता से चालू रखे जाएं। जिससे नदी का जल स्वच्छ एवं प्रदूषणमुक्त बना रहे। छठ महोत्सव से पहले यमुना नदी की जल गुणवत्ता में सुधार लाने को कहा गया। इसके बाद एडीसी सतबीर मान ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि यमुना नदी के किनारे स्थित सभी एसटीपी की तकनीकी जांच की जाए। यदि किसी इकाई में खराबी या अवरोध पाया जाए तो उसे प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त किया जाए।

फरीदाबाद. यमुना नदी किनारे बड़ी संख्या में लोग छठ पर्व मनाते हैं।

उन्होंने कहा छठ पूजा के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु यमुना तट के किनारे बने घाटों पर स्नान और पूजा-अर्चना के लिए पहुंचते हैं। इसलिए यमुना नदी के जल की गुणवत्ता मानक स्तर पर बनाए रखना बहुत जरूरी है।

आपसी समन्वय बनाने का दिया निर्देशः एडीसी ने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए, ताकि किसी प्रकार का अनुपचारित जल या अपशिष्ट नदी में न जाने पाए। उन्होंने कहा सभी घाटों की नियमित निगरानी की जाए। सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आवश्यक संसाधन जैसे प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा, स्वच्छता और पेयजल आपूर्ति की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। यमुना किनारे छठ महापर्व को लेकर सौ से अधिक अस्थाई घाट बनाए जाते हैं। यमुना किनारे बसे बसंतपुर, इस्माइलपुर, पंचशील एन्क्लेव, दीपावली एन्क्लेव, शिव एन्क्लेव पार्ट एक दो, तीन, अजय नगर पार्ट-एक, दो, तीन, अटल चौक, खड्डा कॉलोनी आदि के लोग छठ पर्व मनाने पहुंचते हैं।

किराना स्टोर संचालक से रंगदारी मांगने के मामले में आरोपी गिरफ्तार

भास्कर न्यूज | फरीदाबाद

रंगदारी मांगने के मामले में ओल्ड फरीदाबाद थाने की पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस पर पहले से ही 28 मामले दर्ज हैं। ओल्ड फरीदाबाद थाने का यह दुश्चरित्र अपराधी है। इसे कोर्ट में पेश कर तीन दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल के अनुसार ओल्ड निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि उनकी ओल्ड फरीदाबाद की मेन मार्केट में किराने की दुकान है। 15 अक्टूबर को वह दुकान पर बैठे थे। आरोपी ने उनसे मंथली के रूप में 10 हजार रुपए मांगे थे। बाद में आरोपियों ने कैलाश को चाकू मारकर घायल कर दिया।

पार्क में गला रेतकर युवक की हत्या, चार टीमें गठित

मुजेसर के डाबरी पार्क से शव किया बरामद

भास्कर न्यूज | फरीदाबाद

मुजेसर के डाबरी पार्क में बुधवार रात 35 वर्षीय एक युवक की गला रेतकर किसी ने हत्या कर दी। पुलिस ने गुरुवार सुबह उसका शव लहूलुहान हालत में पार्क से बरामद किया। उसकी पहचान नहीं हो पाई है। क्राइम ब्रांच समेत पुलिस की चार टीमें मामले की जांच में जुटी हैं। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज पुलिस खंगाल रही है। जांच के दौरान मृतक के शव के पास शराब की खाली बोतल और गिलास मिले हैं। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि हत्या से पहले मृतक कुछ लोगों के साथ शराब पी रहा होगा। इसी दौरान किसी बात को लेकर हुए विवाद में उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार मृतक की उम्र करीब 35 साल है। उसके सिर में गंभीर चोटें हैं। ऐसे में आशंका है पत्थर या भारी वस्तु से सिर पर वार किया गया होगा।

महिला ने युवक को शराब पीते देखा था: एक महिला ने पुलिस को बताया कि वह कूड़ा उठाने का काम करती है। उसने बुधवार को दिन में करीब एक से डेढ़ बजे के बीच मृतक को वहां शराब पीते देखा था। महिला ने बताया कि वह किसी कंपनी में काम करता था।

सड़क सुरक्षा प्रश्नोत्तरी में 4.39 लाख से अधिक छात्रों ने भाग लिया

भास्कर न्यूज | फरीदाबाद

पुलिस की ओर से जिले में इंटर स्कूल सड़क सुरक्षा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता 2025-26 का आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता जिले के 1581 शिक्षण संस्थानों में एक साथ हुई। इनमें 377 सरकारी स्कूल, 1180 निजी स्कूल व 24 कॉलेज-शैक्षणिक संस्थान शामिल थे। प्रतियोगिता में 439173 छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। यह प्रतियोगिता सुबह 11 से दोपहर 12 बजे तक हुई। प्रत्येक वर्ष विद्यार्थियों की भागीदारी में वृद्धि हो रही है। वर्ष 2024-25 में जिले के 282428 छात्र-छात्राओं ने भाग लिया था। जबकि इस वर्ष यह संख्या बढ़कर 4,39,173 तक पहुंच गई।

शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म, गर्भपात के दौरान मौत, दो गिरफ्तार

आरोपी अनिल व दीपक को जेल भेजा, महिला डॉक्टर की तलाश

भास्कर न्यूज | फरीदाबाद

एक युवक ने शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म किया। इससे वह गर्भवती हो गई। इसके बाद गर्भपात कराने के दौरान उसकी तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस प्रवक्ता यशपाल के अनुसार गोच्छी निवासी महिला ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि उनकी बड़ी बेटी के साथ अनिल नामक लड़के ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। जब वह गर्भवती हो गई तो उसका गर्भपात करा दिया। इसके बाद बेटी की तबीयत खराब हो गई। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद मुजेसर थाने में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। संजय कालोनी पुलिस चौकी की टीम ने अनिल (27) निवासी पर्वतीया कालोनी व दीपक (36) निवासी नंगला इंक्लेव को गिरफ्तार कर लिया।

पूछताछ में सामने आया कि आरोपी अनिल की करीब दो माह पहले पीड़िता से मुलाकात हुई थी। इसने पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जब वह गर्भवती हो गई तो आरोपी उसे एक मेडिकल स्टोर संचालक दीपक के पास ले गया। दीपक ने 35 हजार रुपए लेकर 27 सितंबर को निदान अस्पताल में पीड़िता का गर्भपात करा दिया। जांच में पाया गया कि गर्भपात के बाद पीड़िता की तबीयत खराब हो गई। इससे उसे 28 सितंबर को सफदरजंग अस्पताल में दाखिल कराया गया।

आज से फरीदाबाद से अयोध्या तक सीधी बस

फरीदाबाद | फरीदाबाद से अयोध्या के लिए नई बस सेवा 17 से शुरू हो रही है। रोडवेज की जीएम शिखा ने बताया कि एनआईटी के मंगल सेन बस अड्डे से यह बस सुबह 4.15 बजे रवाना होगी। इस बस सेवा का मार्ग एनआईटी बस अड्डा से बल्लभगढ़, पलवल, आगरा, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या निर्धारित किया गया है। एनआईटी से सुबह 16:15 बजे, बल्लभगढ़ से 17:00 बजे, पलवल से 17:30 बजे, आगरा से 21:30 बजे, कानपुर से 3:30 बजे, लखनऊ 5:00 बजे और अयोध्या 8:00 बजे पहुंचेगी। बल्लभगढ़ से आगरा का किराया 234, बल्लभगढ़ से इटावा 427, बल्लभगढ़ से कानपुर 650 और बल्लभगढ़ से अयोध्या 983 रुपए है। इसी प्रकार अयोध्या से वापसी प्रस्थान 17:00 बजे, लखनऊ 20:00 बजे, कानपुर 21:30 बजे, आगरा 03:00 बजे और बल्लभगढ़ 08:45 बजे निर्धारित किया गया है। वापसी यात्रा का किराया अयोध्या से लखनऊ 225, अयोध्या से कानपुर 346, अयोध्या से आगरा 758 और अयोध्या से बल्लभगढ़ 983 रुपए है।

दुखद • एक घंटे में हाइड्रा की मदद से रोड़ियों के ढेर से निकाली कैब

रोड़ी से भरा ट्राला कैब पर पलटा, 1 की मौत, 3 जख्मी

भास्कर न्यूज | गुरुग्राम

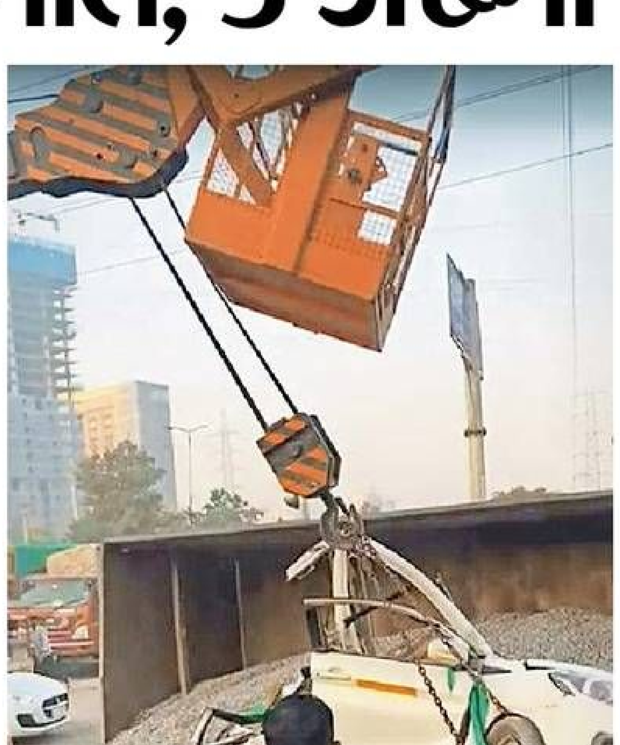

गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर वीरवार की सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। रोड़ी से भरा ट्राला एक कैब पर पलट गया। इस घटना में ड्राइवर सहित तीन लोग कैब में ही दब गए। वहीं, घटना में ट्राले का चालक भी घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद हाइड्रा क्रेन की मदद से कैब को बाहर निकाला और कैब में फंसे लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने एक गार्ड को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक महिला व ड्राइवर दो की हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल पुलिस मौके पर जांच कर रही है।

घटना के कारण गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर जाम लगा एसपीआर रोड से गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की तरफ से एक रोड़ी से भरा ट्राला जा रहा था। जब यह सेंट जेवियर स्कूल चौक के पास पहुंचा तो अचानक अनियंत्रित होकर साइड में चल रही एक कैब पर पलट गया। इस घटना में कैब पूरी तरह से इस ट्रॉले व रोड़ियों के नीचे दब गई और कैब में मौजूद तीन लोग भी इसमें दब गए। आसपास से गुजर रहे लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने हाइड्रा क्रेन को बुलाया।

नगर निगम ने भोंडसी में अवैध निर्माण ध्वस्त किया

भास्कर न्यूज | गुरुग्राम

नगर निगम गुरुग्राम द्वारा गांव भोंडसी क्षेत्र में अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई ड्यूटी मजिस्ट्रेट आरके मोंगिया की निगरानी में की गई, जिसमें जूनियर इंजीनियर प्रदीप और रोहित सहित निगम का फील्ड स्टाफ मौजूद रहा। यह अभियान उन शिकायतों के समाधान के उद्देश्य से चलाया गया जो समाधान शिविर और सीएम विंडो पर स्थानीय निवासियों द्वारा दर्ज कराई गई थीं। इन शिकायतों में अवैध निर्माण और भूमि उपयोग के उल्लंघन से संबंधित मामलों की जानकारी दी गई थी। ड्यूटी मजिस्ट्रेट आरके मोंगिया ने बताया कि यह कार्रवाई प्रशासन की शून्य सहनशीलता नीति के तहत की गई है। उन्होंने कहा कि नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान ही प्रशासन की प्राथमिकता है और इस दिशा में निरंतर अभियान चलाए जाएंगे।

पूर्व डिप्टी स्पीकर पर फ्लैट हड़पने में मदद का आरोप

गहलोत ने सभी आरोप बेबुनियाद बताए

भास्कर न्यूज | गुरुग्राम

महम विधानसभा के पूर्व विधायक बलबीर सिंह उर्फ बाली पहलवान ने प्रदेश के पूर्व डिप्टी स्पीकर गोपीचंद गहलोत पर साजबाज कर उसका फ्लैट हड़पवाने का आरोप लगाया है। आरोप है कि एमएलए ग्रुप हाउसिंग समिति के चेयरमैन गोपीचंद चंद गहलोत ने साजबाज करके उनका फर्जी त्यागपत्र दिखाकर यह फ्लैट गुड़गांव लोकसभा से वर्ष 2019 में इनेलो के प्रत्याशी रहे वीरेंद्र राणा के नाम कर दिया। आर्थिक अपराध शाखा-2 (ईओडब्ल्यू-2) की जांच के बाद डीएलएफ सेक्टर-29 थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं, दूसरी ओर इस संबंध में पूर्व डिप्टी स्पीकर गोपीचंद गहलोत ने कहा कि सभी आरोप बेबुनियाद हैं। बाली पहलवान ने पहले भी शिकायत दर्ज कराई थी। लेकिन जांच कमेटी की जांच में जब उनके आरोप सही नहीं पाए गए तो उनकी शिकायत को क्लोज कर दिया गया था।

यह है मामला

महम के मोखरा गांव निवासी बलबीर सिंह उर्फ बाली पहलवान ने बताया कि हरियाणा जन प्रतिनिधि सहकारी ग्रुप हाउसिंग समिति लिमिटेड पंचकुला एट गुरूग्राम में 21 मार्च 2003 में समिति की सदस्यता ग्रहण की थी। सदस्य बनने के बाद समिति में पांच लाख रुपए जमा कराए। 15 फरवरी 2005 में उनके नाम फ्लैट नंबर 507 अलॉट किया गया। जिसके वे समय-समय पर रुपए भरते रहे। उन्होंने कुल 30,50000 रुपए समिति में जमा करवा दिये। बाली पहलवान ने वर्ष 2020 में एक शिकायत दर्ज कराई थी। जिसकी जांच एसीपी डीएलएफ व एसआईटी द्वारा की गई। आर्थिक अपराध शाखा-2 (ईओडब्ल्यू-2) की जांच के बाद डीएलएफ सेक्टर-29 थाना पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी।

18 से 20 तक दी गई ग्रीन पटाखों की अनुमति, गश्ती दल बनाएगा प्रशासन

गुरुग्राम | सुप्रीम कोर्ट के सख्त दिशा-निर्देशों के साथ एनसीआर जिसमें गुरुग्राम जिला भी शामिल है, में दिवाली पर्व के उपलक्ष्य में केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री और चलाने की अनुमति प्रदान की है। डीसी अजय कुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार हरित पटाखों की बिक्री 18 अक्टूबर 2025 से 20 अक्टूबर 2025 तक ही जारी रहेगी। इसकी निगरानी के लिए जिला और खण्ड स्तर पर टीम भी गठित की गई है। पुलिस अधिकारी, जिला प्रशासन के परामर्श से बिक्री के निर्दिष्ट स्थानों पर निगरानी रखने के लिए गश्ती दल गठित करेंगे, जिनमें राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के क्षेत्रीय कार्यालयों से नामित अधिकारी भी शामिल होंगे।

'जन विश्वास–जन विकास' जिला स्तरीय समारोह आज, सीएम संबोधित करेंगे

गुरुग्राम | हरियाणा सरकार के तीसरे कार्यकाल का एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज 'जन विश्वास–जन विकास' समारोह का आयोजन गुरुग्राम स्थित अपैरल हाउस, सेक्टर-44 में किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य तथा वन, पर्यावरण व वन्यजीव मंत्री राव नरबीर सिंह शिरकत करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का लाइव संबोधन भी प्रसारित किया जाएगा। डीसी अजय कुमार के दिशा-निर्देशन तथा एडीसी वत्सल वशिष्ठ के नेतृत्व में आयोजन के सफल क्रियान्वयन को लेकर आयोजन स्थल पर सभी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के पात्र लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए जाएंगे।

हरियाणा मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का दौरा, बच्चों संग समय बिताया

गुरुग्राम | हरियाणा मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) ललित बत्रा ने गुरुवार को गुरुग्राम स्थित खुशबू वेलफेयर सोसाइटी का दौरा किया। यह संस्था बीते तीन दशकों से दिव्यांगजनों के पुनर्वास, प्रशिक्षण और आत्मनिर्भरता के लिए निरंतर कार्य कर रही है। अध्यक्ष ललित बत्रा संस्था के सेक्टर-10 स्थित केंद्र पहुंचे, जहां निदेशक और उनकी टीम ने स्वागत किया। संस्था की ओर से बताया गया कि वर्तमान में 103 नियमित छात्र, 2 ओपीडी लाभार्थी और 5 दीर्घकालिक आवासीय देखभाल प्राप्त करने वाले विशेष बच्चे संस्था से जुड़े हुए हैं। संस्था को पहले ही महात्मा अवॉर्ड्स फॉर सोशल गुड्स 2019 और गौरव सम्मान पुरस्कार 2020 जैसे सम्मान प्राप्त हो चुके हैं।

भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार को एक साल पूरा, ना गड्ढे भरे ना गंदगी साफ हुईः पंकज

गुरुग्राम | हरियाणा में नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में भाजपा सरकार का एक साल पूरा होने पर कांग्रेस के शहरी जिला अध्यक्ष पंकज डावर ने सरकार के कामकाज और प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाए। डावर ने कहा कि हरियाणा में भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार को एक साल पूरा हो गया है, मगर इस एक साल में सरकार ना तो गुरुग्राम के गड्ढे भर पाई और ना ही गंदगी से मुक्ति दिला पाई। अगर कुछ हुआ है तो वह भ्रष्टाचारियों का विकास हुआ है। भ्रष्टाचार का ताजा उदाहरण तो निगम व जीएमडीए के अधिकार क्षेत्र की सड़कें हैं, जहां रोड़ी-तारकोल से बनाई गई सड़क अगले ही दिन उखड़ गई।

एक साल से चकमा दे रही लुटेरी दुल्हन गिरफ्तार

भास्कर न्यूज | गुरुग्राम

राजस्थान में शादी करके लाखों रुपए व जेवरात लूटने की आरोपी दुल्हन को पुलिस ने गुडग़ांव से काबू कर लिया। अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपित दुल्हन काजल एक साल से पुलिस को चकमा दे रही थी। वह गुरुग्राम के सरस्वती इन्क्लेव में छुपकर रह रही थी। जिसे राजस्थान की सीकर पुलिस ने धर दबोचा। इस मामले में सीकर पुलिस काजल के परिजनों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। जानकारी अनुसार यूपी के गोवर्धन निवासी भगत सिंह की मुलाकात मई 2024 में राजस्थान के सीकर निवासी ताराचंद जाट से जयपुर में हुई थी। जहां भगत सिंह ने ताराचंद से उसके बेटे भंवर लाल और शंकर लाल की शादी के लिए अपनी बेटी काजल और तमन्ना से रिश्ता तय करने का प्रस्ताव दिया। शादी के बाद दो दिन तक भगत सिंह का परिवार ताराचंद के साथ रहा। तीसरे दिन अचानक ये लोग बिना किसी को बताए दुल्हनों के गहने, नगदी और कपड़े लेकर गायब हो गए। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया

पुलिस पूछताछ में काजल ने खुलासा किया कि उसके पिता भगत सिंह ने ठगी का एक सुनियोजित नेटवर्क बनाया था। दोनों लड़कियों को कुंवारा बताकर रिश्ता तलाशने का ढोंग किया जाता। ऐसे अमीर परिवार तलाश किए जाते, जहां युवकों की शादी नहीं हो रही होती। काजल और तमन्ना को इस धंधे में मुख्य भूमिका दी गई थी, क्योंकि उनकी शादी के जरिए लोगों का भरोसा जीता जाता था। शादी के दो तीन दिन तो रस्मों रिवाज में निकाल देती थी। इस दौरान वे पति के साथ संबंध भी नहीं बनाती थी।

किशोरी ने फंदा लगा खुदकुशी की, केस

गुरुग्राम | शिवाजी नगर एरिया के गांधी नगर में मानसिक रूप से परेशान एक किशोरी ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर निवासी 14 साल की शौहरत गुरुग्राम के गांधीनगर में अपनी बुआ के यहां पिछले पांच साल से रह रही थी। बताया जा रहा है कि वह मानसिक रूप से परेशान चल रही थी। उसकी बुआ इशरत परवीन घर पर नहीं थी तो पीछे से शौहरत ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। इशरत परवीन जब घर आई तो उसने शौहरत को फंदे से लटके देखा। जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। पुलिस को मौके पर कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। जिससे खुदकुशी की वजह का पता नहीं चल सका।

आंगनवाड़ी वर्कर्स ने दी चेतावनी, अफसरों के घर नहीं होगी रोशनी

भास्कर न्यूज | नूंह

महीनों से वेतन नहीं मिलने से नाराज आंगनवाड़ी वर्कर्स ने लघु सचिवालय में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इन्होंने चेतावनी दी कि जब कर्मचारियों की दिवाली काली मनेगी तो अधिकारियों के घर रोशनी नहीं हो सकेगी। महिला कर्मियों ने गुजारिश की दिवाली से पहले वेतन खाते में डाला जाए ताकि उनके घर भी खुशियां आ सकें। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व आंगनवाड़ी वर्कर्स यूनियन की जिलाध्यक्ष सरोज यादव ने की। बड़ी संख्या में महिला कर्मी एकत्रित होकर लघु सचिवालय पहुंची और महिला एवं बाल विकास विभाग की अधिकारियों तथा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिलाध्यक्ष सरोज यादव समेत आंगनवाड़ी वर्कर विनीता, कुसुम व लक्ष्मी व जमशीदा ने कहा कि हमारी सुनवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। गुस्साई आंगनवाड़ी वर्कर्स ने चेतावनी भी दी कि हमारी दिवाली काली रही तो अफसरों के घर भी दीया नहीं जलने देंगे। सीटीएम हिमांशु चौहान ने ज्ञापन लेकर प्रदर्शनकारी कर्मियों को आश्वासन दिया कि समाधान की दिशा में जल्द प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस संबंध में विभागीय अधिकारियों से भी बात कर पूरी रिपोर्ट लेंगे।

डकैती केस में बंद आरोपी से चरस मिली

भास्कर न्यूज | गुरुग्राम

सोहना क्राइम ब्रांच ने डकैती के मामले में भोंडसी जेल में बंद एक कैदी से अवैध मादक पदार्थ बरामद बरामद किया है। आरोपी लूट के एक मामले में दिल्ली के द्वारका अदालत में पेशी पर गया था। जहां इसके साथी ने उसे अवैध मादक पदार्थ दिया था। पुलिस ने आरोपी से 05.66 ग्राम चरस/सुल्फा बरामद कर उसके खिलाफ भौंडसी थाना में केस दर्ज कराया है। वहीं क्राइम ब्रांच ने आरोपी का प्रोडक्शन वारंट जारी करवाकर गुरुग्राम से उसे नियमानुसार गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर दो दिन के पुलिस हिरासत रिमांड पर लिया है। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि वह गुरुग्राम में डकैती करने के मामले में पिछले 2.5 साल से बंद है। वह लूट के मामले में दिल्ली के द्वारका अदालत में पेशी पर गया था। जहां इसके साथी ने उसे मादक पदार्थ दिया था। जिसका वह जेल में इसका सेवन करता था।

प्रेरणा

सवाल ये नहीं है कि कितना सीखा जा सकता है, सवाल ये है कि कितना भुलाया जा सकता है। - ओशो

संपादकीय

मैन्युफैक्चरिंग और प्रति-व्यक्ति आय पर फोकस हो

सरकार को चुनिंदा आंकड़े देकर खुशफहमी पालने से बचना चाहिए। भारत को दुनिया में सबसे तेज विकास दर वाला देश बताने के पहले यह भी बताना होगा प्रति-व्यक्ति आय या मानव-विकास सूचकांक में हम दुनिया में पिछले अनेक दशकों से वहीं के वहीं हैं। जहां वित्त मंत्रालय का मानना है कि आने वाले एक-डेढ़ दशक तक अगर भारत 8% की विकास दर हासिल कर सके तो 2047 तक विकसित देशों में आ जाएगा, वहीं मॉर्गन स्टेनली की ताजा रिपोर्ट बताती है कि इस विकास दर से कुछ हासिल नहीं होगा। अगले दस वर्षों में 8.5 करोड़ नए युवा जॉब मार्केट में खड़े होंगे और अगर भारत को बेरोजगारी खत्म करनी है तो कम से कम 12.2% की दर से लगातार एक दशक विकास करना होगा। संकेत स्पष्ट हैं। मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी में शेयर पिछले दस वर्षों में बढ़ने की जगह 16.7% से घटकर 15.9% रह गया है। तेज और संतुलित अर्थव्यवस्था तब कही जाती है, जब कृषि क्षेत्र से युवाओं का मैन्युफैक्चरिंग में स्थानापन्न हो सके। लेकिन भारत में उल्टा हो रहा है और युवाओं का मजबूरन कृषि क्षेत्र में लौटना मैन्युफैक्चरिंग की लगातार गिरती स्थिति का परिचायक है। न भूलें कि टैरिफ की मार से भारत के 50 अरब डॉलर के अमेरिकी निर्यात पर भी असर पड़ने जा रहा है। देश में 17.7% युवाओं का बेरोजगार होना एक चिंतनीय आर्थिक परिदृश्य दिखाता है।

जीने की राह

पं. विजयशंकर मेहता

humarehanuman@gmail.com

संतानों को ऐसा रक्षा कवच दें, जो दुर्गुणों से उन्हें बचाए

वातावरण का अपना प्रभाव होता है। माहौल की अपनी भाषा होती है। कहा जाता है कि स्थितियों को पॉजिटिव रखिए। एक सीधा प्रयोग है। गाय से जुड़ी जितनी वस्तुएं हमारे आसपास होंगी, पॉजिटिविटी आएगी। गाय का दूध, घी, गोबर से बने कंडे और जितनी सामग्री है, इनमें नैसर्गिक पॉजिटिविटी है। हमारी संस्कृति में एक तिथि मनाई जाती है- गोवत्स द्वादशी। कहते हैं इसका व्रत राजा उत्तानपाद और उनकी पत्नी सुनीति ने किया था तो उनको संतान के रूप में ध्रुव प्राप्त हुए थे। उत्तानपाद की एक और रानी थीं सुरुचि, जिनके बेटे का नाम था उत्तम। लेकिन ध्रुव अपने सदाचरण से सारी दुनिया में छा गए और उत्तम लगभग बर्बाद हो गए। गोवत्स द्वादशी का यह व्रत संतानों के हित के लिए किया जाता है। संतानें यदि नीति से पाली जाएं तो ध्रुव बन जाएंगी और रुचि से पाली जाएं तो उत्तम की तरह भटक सकती हैं। इसलिए हमारे पारिवारिक जीवन में संतानों को ऐसा रक्षा कवच दें, जो दुर्गुणों से उन्हें बचाए और उस कवच का नाम है– गो की वस्तुएं।

•Facebook:Pt. Vijayshankar Mehta

स्पीक-अप • भारत-अफगानिस्तान मेलजोल से बेचैनी

पाकिस्तान के तमाम मंसूबे एक-एक कर नाकाम हो रहे

कूटनीति

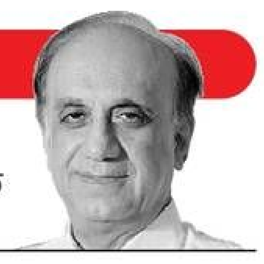

मिन्हाज मर्चेंट

लेखक, प्रकाशक और सम्पादक

mmleditorial@gmail.com

अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की भारत-यात्रा से पाकिस्तान में अफरातफरी मची हुई है। तालिबानी नेता की आठ दिवसीय भारत-यात्रा का एक-एक दिन पाकिस्तान ने बामुश्किल काटा, क्योंकि इसी दौरान अफगानिस्तान से उसकी जंग भी चलती रही। उसने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) प्रमुख नूर वली मेहसूद को मारने के लिए काबुल पर हवाई हमला भी किया, लेकिन इसमें मेहसूद के बजाय उसका बेटा मारा गया। पहले से ही तनावपूर्ण चले आ रहे अफगानिस्तान-पाकिस्तान संबंधों में आंशिक युद्धविराम के बावजूद अनेक चुनौतियां कायम हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डर भारत और अफगानिस्तान के बढ़ते हुए रिश्ते थे और मुत्ताकी की भारत यात्रा ने इसे सही साबित कर दिया। जम्मू-कश्मीर पर भारत की सम्प्रभुता को स्वीकार करके मुत्ताकी ने पाकिस्तान को और आक्रोशित कर दिया है।

अगस्त 2021 में जब अमेरिका के नेतृत्व वाली नाटो सेनाएं अफगानिस्तान को तालिबान के हवाले कर वापस लौटी थीं तो पाकिस्तानी नेताओं ने यह सोचकर जश्न मनाया था कि अब अफगानिस्तान पश्चिमी मोर्चे पर उसका रणनीतिक-बेस होगा। लेकिन चार साल बाद तालिबान शासित अफगानिस्तान सामरिक तौर पर उसका शत्रु बन बैठा है। अफगानी जमीन से आतंकवादी पाकिस्तान को निशाना बना रहे हैं। वास्तव में, पाकिस्तान अब कई मोर्चों पर हमले झेल रहा है। टीटीपी पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर आत्मघाती हमले कर ही रहा है। इधर, बलूचिस्तान में द बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट (बीएलएफ) ने चीन द्वारा बनाए बुनियादी ढांचों पर हमले तेज कर दिए हैं। खैबर-पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में भी स्वायत्तता की मांग को लेकर स्थानीय उग्रवादी समूहों का विद्रोह बढ़ रहा है।

साद हुसैन रिजवी के नेतृत्व वाला तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (टीएलपी) घरेलू मोर्चे पर पाकिस्तान के लिए एक राजनीतिक खतरा है। इस कट्टरपंथी समूह को पाकिस्तानी सेना अपने प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल करती है। इसकी चरमपंथी विचारधारा असीम मुनीर के कट्टर इस्लामवाद से मेल खाती है। लेकिन पाकिस्तानी सेना द्वारा पाले जा रहे लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे समूहों के उलट, टीएलपी अकसर पाकिस्तान के हाइब्रिड सिविल-मिलिट्री नेतृत्व के खिलाफ काम करता है। जब मुनीर और शाहबाज शरीफ क्रिप्टो, तेल और रेयर अर्थ सौदों से ट्रम्प को लुभा रहे थे तो टीएलपी ने ट्रम्प की मध्यस्थता वाले इजराइल-हमास शांति समझौते के विरोध में लाहौर से इस्लामाबाद में अमेरिकी दूतावास तक मार्च शुरू कर दिया था।

यह पाकिस्तान की जांची-परखी रणनीति है कि एक तरफ तो उसका नेतृत्व अमेरिका को खुश करता है, जबकि इससे अनजान होने का दिखावा करते हुए टीएलपी जैसे भाड़े के प्रॉक्सी पाकिस्तान में अमेरिका को धमकाते हैं। उद्देश्य यही है कि अमेरिका भी प्रसन्न रहे और पाकिस्तानी अवाम की हमास समर्थक और इजराइल विरोधी भावनाओं को भी संतुष्ट रखा जाए।

ऑपरेशन सिंदूर में भारत से मिली शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान फिर से अवसर तलाश रहा है। उसने ट्रम्प की खुशामद की। सऊदी अरब से रक्षा संधि की और ट्रम्प के गाजा शांति समझौते का समर्थन किया। पाकिस्तान-सऊदी सैन्य संबंध दशकों पुराने हैं। 2015 में जब सऊदी-यूएई संयुक्त सेना ने यमन में

मुनीर की रणनीति भारत को घेरने की थी- पश्चिम में अफगानिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश, दक्षिण में श्रीलंका और उत्तर में नेपाल। लेकिन बांग्लादेश को छोड़कर सभी तिकड़में विफल हो गईं। उलटे अफगानों से हमारे ताल्लुक बेहतर हुए हैं।

हूती विद्रोहियों पर हमला किया तो सऊदी ने ऑपरेशन का नेतृत्व करने के लिए पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख रहील शरीफ को नियुक्त किया था। दस साल बाद भी यह ऑपरेशन हूती विद्रोहियों को हराने में विफल रहा है।

पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दे के अंतरराष्ट्रीयकरण के मंसूबे विफल हो गए हैं। उलटे, पीओके में बढ़ी हिंसा ने बता दिया है कि वहां के लोगों के मन में गुस्सा भरा है। मुनीर की रणनीति भारत को विरोधी ताकतों से घेरने की थी- पश्चिम में अफगानिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश, दक्षिण में श्रीलंका और उत्तर में नेपाल। लेकिन बांग्लादेश को छोड़कर सभी तिकड़में विफल हो गईं। सम्भवतः बांग्लादेश भी अगले साल वहां होने वाले चुनाव के बाद भारत से रिश्तों के आर्थिक लाभ को समझ जाए। अफगानिस्तान ताजा उदाहरण है। यह बताता है कि पाकिस्तान के क्षेत्रीय दांव भी नहीं चल रहे हैं। इमरान को कैद में रखना मुनीर के लिए राजनीतिक संकट भी बन सकता है, क्योंकि मुनीर ने ही इमरान का जेल जाना सुनिश्चित किया था। मुनीर को डर है कि इमरान की लोकप्रियता पाकिस्तान पर फौज के दबदबे को कमजोर कर सकती है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं।)

विमर्श • हमें मानवता को अधिक महत्व देना चाहिए

देशों में आपसी सहयोग के बिना दुनिया चल नहीं सकेगी

देशकाल

कौशिक बसु

विश्व बैंक के पूर्व चीफ इकोनॉमिस्ट

ये कठिन समय है। एक तरफ असमानता बढ़ रही है, वहीं कई देशों के राजनेता गरीबों को लाभ पहुंचाने वाले कार्यक्रमों और सेवाओं में कटौती कर रहे हैं। साथ ही वे प्रवासियों और शरणार्थियों के खिलाफ भय और क्रोध को भी भड़का रहे हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा, समृद्धि को बढ़ाना और नागरिकों की सुरक्षा के उनके कथित नेक इरादे खुद को और अपने धनी साथियों को समृद्ध बनाने के एजेंडे के लिए एक छद्म आवरण मात्र होते हैं। राजनीति के व्यवहार में आई इस गिरावट के कई कारण हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक अर्थशास्त्र के व्यवहार में आई गिरावट है।

अर्थशास्त्र को अकसर एक वैज्ञानिक प्रणाली बताया जाता है। लेकिन वैज्ञानिक निष्कर्ष भी हमारे मूल्यों और निर्णयों को प्रभावित करते हैं और वैज्ञानिक निष्पक्षता के दावों का इस्तेमाल हमारी नैतिक संवेदनाओं को ठेस पहुंचाने वाले कार्यों को जायज ठहराने के लिए किया जा सकता है। वास्तव में, मुख्यधारा के अर्थशास्त्र- विशेष रूप से लंबे समय से प्रचलित नव-उदारवादी विचारधारा, जो विकास, दक्षता, मुक्त बाजार पर जोर देती है- ने लालच, शोषण और विषमता को न केवल उचित ठहराया है, बल्कि प्रोत्साहित भी किया है।

नोबेल विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के 'कैपेबिलिटी एप्रोच' पर आधारित 2012 के एक अध्ययन में पाया गया था कि शिक्षा लोगों को अधिक केयरिंग और मददगार बनाने में मदद करती है, लेकिन जिस तरह से अर्थशास्त्र पढ़ाया जाता है, यह स्वार्थ को एक सामान्य या वांछनीय नैतिक सिद्धांत के रूप में बढ़ावा दे सकता है। एक अन्य नोबेल विजेता अर्थशास्त्री केनेथ एरो ने कहा था, बाजार तब तक काम नहीं कर सकते, जब तक प्रतिस्पर्धी फर्म और व्यक्ति भी अपने पारस्परिक दायित्वों का सम्मान न करें। दूसरे शब्दों में, वे विश्वास और सहयोग पर निर्भर हैं।

एरो ने मुख्यधारा के अर्थशास्त्र की उस प्रवृत्ति को भी चुनौती दी, जिसमें स्वतंत्रता और समानता को विरोधाभासी माना जाता है। नव-उदारवादी तर्क यह है कि किसी भी मात्रा में असमानता स्वाभाविक है और इसे कम करने का कोई भी हस्तक्षेप स्वतंत्रता को नष्ट करता है। लेकिन कई संदर्भों में स्वतंत्रता और समानता लगभग एक जैसी है। समानता को कमजोर करने वाले कार्य- जैसे हड़ताल या आर्थिक दबाव के अधिक सूक्ष्म रूप- श्रमिकों की स्वतंत्रता को भी काफी सीमित करते हैं। वहीं एक छोटे-से कुलीन वर्ग द्वारा अर्थव्यवस्था का दोहन यह दर्शाता है कि औपचारिक लोकतंत्र और स्वतंत्रता एक छद्म है। अंततः, एरो ने लिखा, जो संस्थाएं घोर असमानताओं को जन्म देती हैं, वे मनुष्यों की समानतापूर्ण गरिमा का अपमान हैं।

दार्शनिक इसाया बर्लिन ने इसका सार प्रस्तुत करते हुए कहा था- भेड़ियों की स्वतंत्रता का अर्थ अकसर भेड़ों की मृत्यु रहा है। यह चेतावनी आज विशेष रूप से दूरदर्शी है, जब न्यस्त स्वार्थों के पास अपने चुने हुए राजनेताओं और उद्देश्यों की ओर आकर्षित करने के लिए अपार संसाधन हैं, साथ ही जनमत को प्रभावित करने के लिए अभूतपूर्व डिजिटल उपकरण भी हैं। जैसा कि एक अन्य नोबेल विजेता अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिग्लिट्ज ने कहा है, एक व्यक्ति, एक वोट के सिद्धांत की जगह एक डॉलर, एक वोट ने ले ली है।

लेकिन आर्थिक स्वार्थ तो समस्या का केवल एक पहलू है। उग्र राष्ट्रवाद भी बढ़ती असमानता में योगदान दे रहा है। एक समय था जब राष्ट्र-राज्य

एक समय था जब राष्ट्र-राज्य आर्थिक जीवन को व्यवस्थित करने के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था थी। प्रगति को बढ़ावा देने में भी राष्ट्रीय गौरव की अहम भूमिका होती थी। लेकिन अब सामूहिक लक्ष्यों पर वैश्विक सहयोग का समय है।

आर्थिक जीवन को व्यवस्थित करने के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था थी। प्रगति को बढ़ावा देने में राष्ट्रीय गौरव की भूमिका होती थी। लेकिन अब सामूहिक लक्ष्यों पर वैश्विक सहयोग का समय है- एक-दूसरे के लिए लाभकारी व्यापार-व्यवस्थाओं से न्यायसंगत और समावेशी जलवायु-कार्रवाई तक। बाजारों की तरह बहुपक्षीय कार्रवाइयां भी परस्पर विश्वास और सहयोग पर निर्भर करती हैं।

आपसी सहयोग में विश्वास को मजबूत करके, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जैसे बहुपक्षीय संगठन दुनिया के देशों को अपने बलबूते हासिल की जा सकने वाली उपलब्धियों से कहीं ज्यादा हासिल करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन इन जैसी संस्थाओं को मजबूत करने के लिए हमें अपनी नैतिक दिशा को फिर से जांचना होगा। केवल स्वार्थ पर ध्यान केंद्रित करने को तर्कसंगत मानने या अपनी करुणा को केवल उन लोगों तक सीमित रखने के बजाय- जो हमारे जैसे दिखते, बोलते या प्रार्थना करते हैं- हमें मानवता को अधिक महत्व देना चाहिए।

(© प्रोजेक्ट सिंडिकेट)

ब्रांड से सबक | MARVEL ENTERPRISES | अमेरिकी एंटरटेनमेंट कंपनी

1996 में मार्वल ने खुद को दिवालिया घोषित किया, अब 2.6 लाख करोड़ तक कमा चुकी हैं इसकी फिल्में

1993 में मार्वल दुनिया की सबसे बड़ी कॉमिक कंपनी थी। स्पाइडर-मैन, एक्स-मैन और फैन्टास्टिक फोर जैसे हीरोज के कॉमिक्स दुकानों में आते और मिनटों में बिक जाते। लेकिन 1995 आते-आते इनकी बिक्री 70% तक गिर गई। कंपनी को करीब 5 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ। इसने खुद को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट में लिखा- मार्वल्स की दुनिया अब बिखर रही है, जैसे कॉमिक्स के पन्नों की तरह हवा में उड़ती जा रही हो। कंपनी के शेयर की कीमत एक डॉलर से भी नीचे पहुंच गई थीं।

कंपनी का बड़ी मात्रा में कॉमिक्स की छपाई करना, मनाफाखोरों का उनका स्टॉक करना और लोगों को मनोरंजन के नए विकल्प मिलना, इस गिरावट के बड़े कारण रहे। घटनाक्रम दिखाता है कि व्यवसाय में समय के साथ बदलाव न हों तो बड़ी कंपनियां भी डूब सकती हैं। हालांकि उस समय के चेयरमैन इसाक पर्लमटर ने कहा था कि 'मार्वल की आत्मा उसके चरित्रों में है और जब तक वे जिंदा हैं, कंपनी मर नहीं सकती।' कंपनी के तत्कालीन सीईओ स्कॉट सास ने अपने कर्मचारियों से कहा, 'यह मार्वल का अंत नहीं, पुनर्जन्म का अवसर है।' इसके बाद कंपनी ने धन जुटाने के लिए पहले किरदारों के राइट्स बेचे फिर खुद फिल्में बनानी शुरू कीं।

वर्तमान स्थिति

मार्वल अब बन चुका है डिज्नी का हिस्सा

29 मार्च 2023 को मार्वल की सभी यूनिट्स को डिज्नी में मिला दिया गया। हालांकि मार्वल स्टूडियोज और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स फिल्मी दुनिया में अभी भी सुपर पावर हैं। इसके तहत 37 फिल्में बन चुकी हैं, जिन्होंने 2.6 लाख करोड़ रु. से अधिक कमाए हैं। एवेंजर्स एंड गेम फिल्म ने दुनियाभर में करीब 25 हजार करोड़ रुपए की कमाई की थी। भारत में इसने करीब 346 करोड़ रु. कमाए थे। अमेरिका में सालाना बिकने वाली कुल कॉमिक्स में करीब 39% हिस्सा मार्वल का होता है।

सबक क्यों- कभी एक डॉलर पहुंच गया था कपंनी का शेयर। मार्वल के तहत बन रही एक-एक फिल्म अब 25 हजार करोड़ तक कमा रही।

37 फिल्में बन चुकी हैं मार्वल स्टूडियोज/मार्वल सिनेमैटिक यूनि. के तहत

39% हिस्सा मार्वल का है अमेरिका में सालाना बिकने वाली कॉमिक्स में

25 हजार करोड़ रुपए के करीब कमाए थे एवेंजर्स एंडगेम फिल्म ने दुनिया में

346 करोड़ रुपए के करीब कमाए थे एवेंजर्स एंडगेम ने भारत में

1939 में छपी मार्वल की यह पहली कॉमिक मार्वल कॉमिक#1 साल 2022 में करीब 21 करोड़ रुपए में बिकी थी

यूं डूबी मार्वल एंटरटेनमेंट कंपनी

1. **अत्यधिक विस्तार, गलत सौदे-** कंपनी ने अत्यधिक विस्तारवादी रणनीति अपनाई। ट्रेडिंग कार्ड्स, खिलौनों से लेकर तेजी से लाइसेंस बांटे, जिससे घाटा हुआ। वहीं सटोरियों ने बाजार को कृत्रिम रूप से बढ़ाया जो बाद में ढह गया।
2. **कॉमिक मार्केट में गिरावट-** 90 के दशक में बच्चों और किशोरों के पास टीवी, वीडियो गेम और फिल्मों के रूप में मनोरंजन के कई विकल्प उपलब्ध हो गए। कॉमिक्स की बिक्री 70% तक गिर गई।
3. **डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट में गड़बड़ी :** 1994 में कंपनी ने वितरण शाखा 'हिरोक्स प्रेस' शुरू की, जिसने पारंपरिक वितरकों से संबंध तोड़ लिए। बिक्री चैनल गड़बड़ा गया। कंपनी की नगदी प्रभावित हुई।
4. **लाइसेंस विवाद, झगड़े-** टॉय बिज और मार्वल एंटरटेनमेंट के बीच स्वामित्व को लेकर मुकदमे चले। इससे कंपनी की प्रतिष्ठा खराब हुई।

इस तरह की वापसी

1. **टॉय बिज के साथ मर्जर-** 1996 में जब कंपनी दिवालिया होने लगी तब मार्वल के दो प्रमुख शेयर धारक इसाक पर्लमटर और एवी अराद आगे गए। एवी टॉय बिज नाम से खिलौना कंपनी चलाते थे। उन्होंने मार्वल और टॉय बिज का मर्जर कराया।
2. **मार्वल स्टूडियो की स्थापना-** 1993 में बनी मार्वल फिल्म्स ने मार्वल के किरदारों के फिल्मी राइट्स बेच दिए थे। 1996 में कंपनी ने मार्वल स्टूडियो बनाकर खुद ही फिल्में बनाने का निर्णय लिया।
3. **वॉल्ट डिज्नी का अधिग्रहण-** डिज्नी ने 2009 में 430 करोड़ डॉलर में मार्वल को खरीद लिया। इससे कंपनी को असाधारण संसाधन, वितरण नेटवर्क और रचनात्मक स्वतंत्रता मिली।
4. **कैरेक्टर फ्रेंचाइजी का विस्तार-** 'एवेंजर्स', 'स्पाइडरमैन' और 'ब्लैक पैंथर' जैसे किरदारों की फ्रेंचाइजिंग ने नए दर्शक जोड़े।

मैगजीन 'मार्वल साइंस स्टोरीज' से लिया था मार्वल नाम

शुरुआत : क्रिएटिव राइटिंग के प्रोफेसर ने रखी थी नींव

1939 में क्रिएटिव राइटिंग के प्रोफेसर मार्टिन जे. गुडमैन ने टाइमली नाम से पब्लिकेशन शुरू किया। इसके तहत उन्होंने ह्यूमन टॉर्च और सब-मरीनर नाम के दो किरदार गढ़े। बाद में 1941 में कैप्टन अमेरिका को लेकर आए। 1950 में इसे एटलस नाम दिया गया। 1961 में पब्लिकेशन के एडिटर इन चीफ स्टैन ली और उनके क्रिएटिव पार्टनर जैक किर्बी ने मार्वल नाम दिया।

गिरावट : पैसा कमाने के लालच में फिसलती चली गई कंपनी

1992, स्पाइडर-मैन, एक्स-मैन जैसी कॉमिक्स के लिए लोग दीवाने हो रहे थे। कंपनी ज्यादा प्रिंट करो, ज्यादा बेचो, दाम बढ़ाओ और मुनाफा कमाओ के मूड में थी। इन कॉमिक को सहेजने वालों ने सैकड़ों कॉपीज खरीद लीं कि ये 'एक दिन करोड़ों की' हो जाएंगी, लेकिन मार्केट में ओवर सप्लाई हो गई। 1993 में कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बिगड़ा और कंपनी फिसल गई।

ऐसे पड़ा नाम : स्टैन ली ने मैगजीन मार्वल साइंस स्टोरीज से प्रेरित होकर मार्वल नाम चुना था, जिसका अर्थ है 'अद्भुत' या चकित करने वाला।

सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी : मार्वल के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी डीसी कॉमिक्स, वॉर्नर ब्रदर्स और ट्वेंटिएथ सेंचुरी फॉक्स हैं।

पीपुल भास्कर | मारिया कोरीना मचाडो | वेनेजुएला की लोकतंत्र समर्थक नेता

राष्ट्रपति को संसद में चुनौती दी, वेनेज़ुएला की आयरन लेडी कही जाती हैं मारिया, गाने का शौक

14 जनवरी 2012, वेनेजुएला के तत्कालीन राष्ट्रपति ह्यूगो सावेज अपने सालाना संबोधन के तहत संसद में सरकार का ब्योरा रख रहे थे। वे 9 घंटे 45 मिनट भाषण दे चुके थे। तभी मारिया मचाडो ने उन्हें 'चोर' बताते हुए कहा कि वे जनता की सम्पत्ति को वापस कर दें। शावेज ने भड़कते हुए कहा 'तुमने मुझे चोर कहा? तुम अकेले हमारा कुछ नहीं कर सकती।' पूरा सदन सन्न रह गया। दरअसल शावेज सरकार ने उस समय सैकड़ों निजी कंपनियों और जमीनों को जनता की सम्पत्ति बताकर जब्त कर लिया था। मारिया वेनेजुएला की पहली ऐसी महिला सांसद बनीं, जिसने संसद के भीतर राष्ट्रपति को खुले मंच पर चुनौती दी थी। लोगों ने उन्हें 'La Dama de Hierro de Venezuela' यानी वेनेजुएला की आयरन लेडी कहना शुरू कर दिया। हालांकि इस विरोध की भारी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। वे सालों छिपकर रहीं। आज भी सार्वजनिक रूप से अधिक सामने नहीं आती हैं। मात्र 25 साल की उम्र में मारिया ने 'अतनेआ' फाउंडेशन की स्थापना की, जो कराकास की झुग्गियों में रहने वाले अनाथ बच्चों की मदद करता है।

मारिया को थिएटर और संगीत पसंद है। यात्रा के दौरान मंच पर होने वाले कार्यक्रमों को देखना पसंद करती हैं। उन्हें गाने का बेहद शौक है। उनकी मीडिया टीम के हवाले से संगीत को उनका 'अधूरा पेशा' तक कहा गया है। खाली समय में बागवानी और किचन गार्डनिंग करती हैं। घर के खाली पड़े हिस्से में खाने-पीने की चीजें खुद उगाती हैं।

चर्चा में क्यों- लोकतंत्र की लड़ाई के लिए हाल ही में उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है।

मारिया कहती हैं मां होना और गलत के विरोध में खड़ा होना दोनों ही जिम्मेदारियां हैं। किसी एक को छोड़ नहीं सकते।

जन्म : 7 अक्टूबर 1967 (58 साल), काराकास, वेनेजुएला

शिक्षा : वेनेजुएला के आईईएसए बिजनेस स्कूल से मास्टर्स

परिवार : तलाकशुदा, तीन बच्चे-आना कोरीना, रिकार्डो और हेनरिके।

सम्पत्ति : करीब 87 करोड़ रु.

(विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स)

शुरुआत

पिता व्यापारी और मां मनोवैज्ञानिक थीं

मारिया का जन्म वेनेजुएला के कराकास में हुआ था। पिता हेनरिक मचाडो जुलोआगा स्टील के व्यापारी थे। मां पारीस्का पेरेज मनोवैज्ञानिक थीं। पारिवारिक माहौल बौद्धिक और अनुशासित था। उनकी स्कूली पढ़ाई एक धार्मिक स्कूल में हुई। बाद में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में डिग्री और फाइनेंस में मास्टर्स किया। वे 4 बहनें हैं, जिनमें मारिया सबसे बड़ी हैं।

विवाह

बिजनेसमैन से शादी की, 2001 में तलाक

मारिया ने 1990 में एक बड़े कारोबारी रिकार्डो सोसा ब्रांगर से शादी की थी। दोनों की मुलाकात वेनेजुएला के एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में हुई थी। रिकार्डो मचाडो की सामाजिक लगन से बेहद प्रभावित थे। हालांकि राजनीतिक तनाव ने पारिवारिक जीवन को प्रभावित किया और अंततः 2001 में दोनों का तलाक हो गया। उनके तीन बच्चे हैं।

करियर

इंजीनियर से विपक्ष की राष्ट्रपति उम्मीदवार तक

बतौर इंजीनियर करियर शुरू किया। 1992 में अनाथ बच्चों के लिए 'अतनेआ' फाउंडेशन बनाया। 2002 में 'सुमेत' फाउंडेशन की स्थापना की, जो पारदर्शी चुनाव का अभियान चलाता है। 2010 में राष्ट्रीय असेंबली का चुनाव जीता। 2013 में वेंते वेनेजुएला पार्टी बनाई। 2023 में विपक्षी राष्ट्रपति का प्राइमरी चुनाव जीता, लेकिन सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया।

रोचक : कॉन्टिगो नाम से रेडियो कार्यक्रम भी चला चुकी हैं मारिया

खास : रेडियो कार्यक्रम भी होस्ट कर चुकी हैं मारिया

- उन्होंने कुछ समय तक 'कॉन्टिगो : कॉन मारिया कोरीना मचाडो' नाम से एक रेडियो कार्यक्रम भी होस्ट किया था।
- वेनेजुएला में मारिया के समर्थक उन्हें लोकतंत्र की मशाल भी कहते हैं।
- पूर्वज वेनेजुएला के महान सेनानायक सिमोन बोलिवार के समकालीन कुलीन परिवार से हैं

उपलब्धि : दुनिया की 100 प्रेरक महिलाओं में शामिल

- येल यूनिवर्सिटी की वर्ल्ड फेलो रह चुकी हैं।
- टाइम मैगजीन ने उन्हें 2025 में दुनिया की 100 प्रेरक महिलाओं में चुना है।
- 2018 में बीबीसी ने उन्हें मोस्ट इंस्पायरिंग वुमन के रूप में चुना था।
- वेनेजुएला में 2010 के संसदीय चुनाव में सर्वाधिक मतों से जीत दर्ज की थी।

दमन : एनजीओ के खिलाफ दर्ज हुए देशद्रोह के मामले

- 2014 में वेनेजुएला की मादुरो सरकार के विरोध में आवाज उठाने पर उन्हें राष्ट्रीय असेंबली मेंबर के पद से हटा दिया गया।
- उनके एनजीओ 'सुमेत' के खिलाफ मादुरो सरकार ने देशद्रोह तक के मामले दर्ज किए।
- 2023 में विपक्षी राष्ट्रपति का प्राइमरी चुनाव जीतने के बाद चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा।

ट्रंप के मनगढ़ंत दावे

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कब क्या कह दें, इसका ठिकाना नहीं। यह एक बार फिर तब प्रमाणित हुआ, जब उन्होंने कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। ट्रंप ने ऐसा आभास कराया, जैसे उनके और भारतीय प्रधानमंत्री के बीच इस सिलसिले में कोई बातचीत हुई है। भारतीय विदेश मंत्रालय की मानें तो दोनों नेताओं के बीच फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं हुई है। इसका मतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का दावा मनगढ़ंत है। यह ठीक है कि वे ऐसे ही दावे करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उन्हें इसका आभास हो तो अच्छा कि इससे उन्हें कुछ हासिल नहीं होता और उलटे बनती बात बिगड़ती है और उनके इरादों के प्रति संशय बढ़ता है। उन्हें यह भी समझना होगा कि बार-बार एक ही बात दोहराने से वह सच नहीं हो जाती। वे एक अर्से से यह माहौल बनाए हुए हैं कि रूस यूक्रेन के खिलाफ इसलिए युद्ध जारी रखने में सक्षम है, क्योंकि भारत उससे तेल खरीद रहा है। उनके कुछ बड़बोले सहयोगी तो यह तक स्थापित कर चुके हैं कि यूक्रेन युद्ध के लिए एक तरह से भारत जिम्मेदार है। यह हास्यास्पद है, क्योंकि रूस से तेल खरीदने में चीन सबसे आगे है। ट्रंप इसका उल्लेख तो करते हैं, लेकिन उसके खिलाफ वैसे कोई कदम नहीं उठाते, जैसे उन्होंने भारत के खिलाफ उठाए और भारतीय आयात पर टैरिफ बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया।

वैसे तो ट्रंप को इससे भी आपत्ति है कि यूरोपीय देश रूस से तेल क्यों खरीद रहे हैं, लेकिन वे उन्हें ऐसा न करने की सलाह देने तक सीमित हैं। ट्रंप यह तो चाहते हैं कि भारत रूस से तेल न खरीदे, पर यह नहीं देखते कि इसके चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी और भारत के लिए अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना कठिन हो जाएगा। इसका कोई औचित्य नहीं कि भारत इसलिए रूस से तेल न खरीदे कि इससे ट्रंप के अहं की तुष्टि हो जाएगी। यह साफ है कि रूस से तेल खरीद पर वे भारत को निशाना बनाए हुए हैं। इसका कारण शायद यह है कि भारत उनके इस मिथ्या दावे पर मुहर लगाने को तैयार नहीं कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध रोका और दोनों देशों को कथित परमाणु युद्ध से बचाया। भारतीय प्रधानमंत्री उनके इस दावे को दो टूक नकार चुके हैं, पर वे इसे बार-बार दोहराने से बाज नहीं आ रहे हैं। हालांकि कुछ समय पहले ट्रंप ने ऐसे संकेत दिए थे कि वे भारत से व्यापार समझौता करने को लेकर गंभीर हैं, लेकिन जब तक यह समझौता हो नहीं जाता, तब तक आश्वस्त नहीं हुआ जा सकता। भारत के लिए यही उचित है कि वह अमेरिकी टैरिफ का सामना करने की अपनी रणनीति पर काम करता रहे। मौजूदा माहौल में ट्रंप पर भरोसा करना ठीक नहीं।

निराशाजनक स्थिति

दिल्ली में ग्रीन पटाखों को सुप्रीम कोर्ट की अनुमति मिल जाने के बाद बाजार में ग्रीन के साथ ही प्रतिबंधित पटाखे बेचा जाना निराशाजनक है। यह देखने में आ रहा है कि ग्रीन पटाखों के बहाने दुकानदार प्रतिबंधित पटाखे भी बेच रहे हैं, जो सर्वथा अनुचित है। इस बीच, ग्रीन पटाखों के लिए कारोबारियों को लाइसेंस मिलने में आ रही परेशानी भी चिंता की बात है। दिल्ली पुलिस ने हालांकि, पटाखा कारोबारियों को लाइसेंस देना शुरू कर दिया है, लेकिन ये शनिवार तक ही मिलेंगे। पटाखा कारोबारियों की ये चिंता अनुचित नहीं है कि इतने कम समय में तमाम औपचारिकताएं पूरी कर उन्हें लाइसेंस कैसे मिल सकेगा।

> दीवाली अच्छी तरह मनाई जानी चाहिए, लेकिन साथ ही प्रदूषण न बढ़ने पाए, इसकी चिंता भी की जानी चाहिए

दिल्ली पुलिस को ऐसी पुख्ता व्यवस्था करनी चाहिए कि पटाखा बेचने के इच्छुक ऐसे सभी विक्रेता, जो नियम और शर्तें पूरी करते हों, उन्हें लाइसेंस मिल जाए, ताकि ग्रीन पटाखों की समुचित उपलब्धता रहे। स्थानीय प्रशासन और दिल्ली पुलिस यह सुनिश्चित कराए कि प्रतिबंधित पटाखे किसी सूरत में नहीं बिकने पाएं। दिल्लीवासियों को भी त्योहार मनाने और पर्यावरण के बीच संतुलन रखना चाहिए। ऐसे में उन्हें भी ग्रीन पटाखे ही चलाने चाहिए। दीवाली मनाने के साथ ही जिम्मेदार नागरिक की तरह दिल्ली के लोगों को प्रदूषण न बढ़ने पाए, इसकी भी चिंता करनी चाहिए। स्थानीय प्रशासन, दिल्ली पुलिस, एमसीडी, आरडब्ल्यूए व दिल्लीवासियों को मिलकर ये दायित्व उठाना होगा।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या दिल्ली-एनसीआर में दीवाली पर ग्रीन क्रैकर्स को अनुमति देने का फैसला सही है?

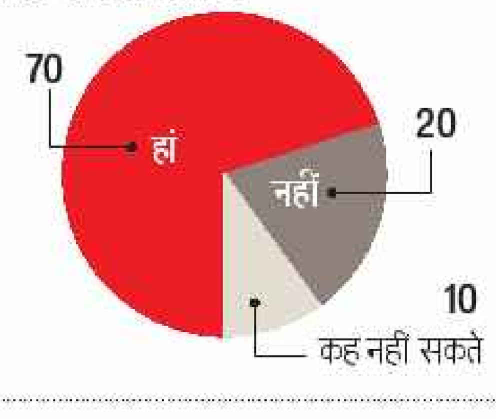

आज का सवाल
क्या मार्च 2026 तक माओवाद के खात्मे का लक्ष्य हासिल होता हुआ दिख रहा है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

समावेशी राजनीति की प्रतिस्पर्धा

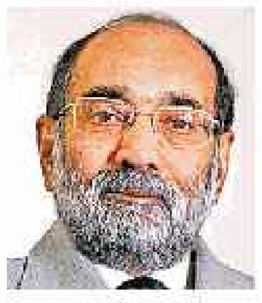

डा. एके वर्मा

कौन राजनीतिक दल समाज के कितने घटकों को अपनी ओर आकर्षित कर पाता है, वही उसकी चुनावी सफलता-असफलता को तय करेगा

बसपा प्रमुख मायावती ने 9 अक्टूबर को कांशीराम के 19वें निर्वाण दिवस पर लखनऊ में महारैली की। उत्तर प्रदेश में 2012 के विधानसभा चुनाव के बाद से बसपा लगातार हाशिए पर पहुंचती गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी को अपना चुनाव क्षेत्र बनाकर 'सबका-साथ, सबका-विकास' मंत्र से दलितों को साथ ले लिया। परिणामस्वरूप प्रदेश की सभी 17 सुरक्षित लोकसभा सीटों पर भाजपा विजयी हुई। इससे भाजपा की दलितों में पैठ गहरी हुई। सरकार एवं संगठन में दलितों को सम्मानजनक स्थान मिला, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा-कांग्रेस गठबंधन ने दलितों में भ्रम फैलाया कि मोदी 'चार सौ पार' करके बाबासाहब आंबेडकर का संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, जिससे दलित भाजपा से छिटक कर सपा के साथ हो लिए। ऐसे में मायावती नहीं चाहेंगी कि दलित सपा के साथ जुड़ा रहे। इसीलिए वे दलितों को एकजुट करके बसपा में लौटाना चाहती हैं। क्या ऐसा हो सकेगा? क्या भाजपा और सपा भी दलितों के विकल्प हैं?

सवाल यह भी है कि मायावती के पास दलित लौटें क्यों? 2012 में अखिलेश से हारने के बाद मायावती ने दलितों को मझधार में छोड़ राष्ट्रीय राजनीति को साधने के लिए दिल्ली का रुख कर लिया। 2007 में मायावती सरकार बनने पर दलितों से ज्यादा ब्राह्मणों और मुसलमानों को मंत्रिपरिषद और पार्टी में महत्वपूर्ण पद मिले। दलित ठगे रह गए। 'अपनी सरकार' बनने से दलित अस्मिता तो अक्षुण्ण रही, पर उसकी राजनीतिक आकांक्षाएं पूरी न हो सकीं। दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी ने जातिवादी-अस्मितावादी बहिर्वेशी-राजनीति को दरकिनार कर 'सबका-साथ, सबका-विकास' की समावेशी राजनीति शुरू की तो दलितों का बड़ा वर्ग खिसक कर भाजपा की ओर चला गया। मायावती ने 2007 में जिस सोशल इंजीनियरिंग से सत्ता प्राप्त की, उसे वे आगे न ले जा सकीं। उनकी सोशल इंजीनियरिंग दलित-ब्राह्मण गठजोड़ न थी, वरन उन्होंने सभी जातियों में बसपा का जनाधार बढ़ाया था। इतने सफल प्रयोग को मायावती संभाल न सकीं?

कभी-कभी मायावती की राजनीतिक परिपक्वता पर संदेह होता है। उन्होंने सामंतवादी मनोवृत्ति से पार्टी चलाई। 2012 चुनावों के पहले उन्होंने बाबूसिंह कुशवाहा और 2017 चुनावों के पहले स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से निकाल दिया। यदि निकालना ही था तो चुनावों में उनका प्रयोग करके निकालना था। 2019 लोकसभा चुनावों में अपने धुर-विरोधी अखिलेश यादव से गठबंधन किया। परिणामस्वरूप विधानसभा चुनाव 2022 में बसपा केवल एक सीट जीत सकी और लोकसभा चुनाव 2024 में उसका खाता नहीं खुला।

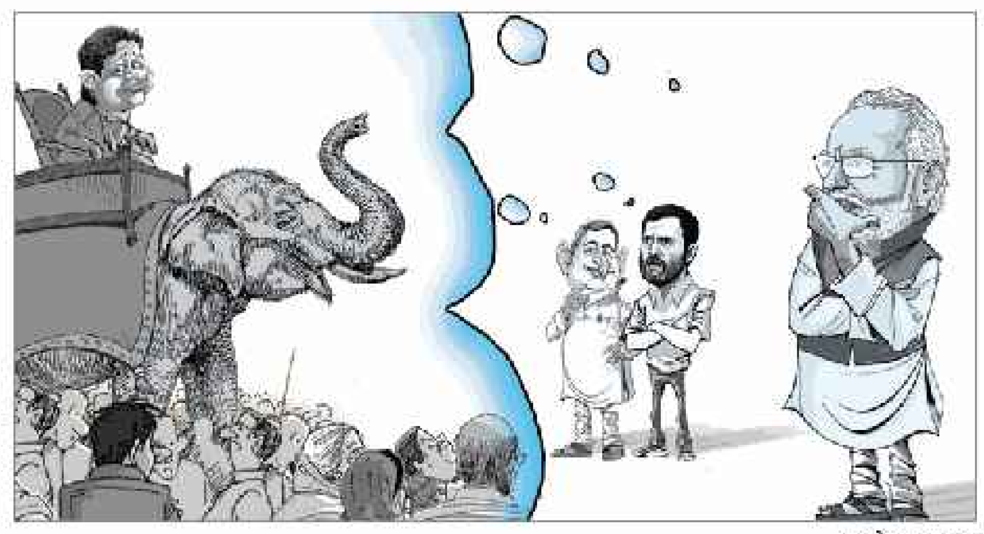

अवधेश राजपूत

मायावती पर आरोप लगे कि भाजपा का परोक्ष समर्थन करने हेतु वे पिछले चुनाव सक्रियता से चुनाव नहीं लड़ीं और अपने उत्तराधिकारी आकाश आनंद को 2024 चुनाव प्रचार के दौरान ही अपदस्थ कर वापस बुला लिया कि वे अभी 'अपरिपक्व' हैं। इससे संदेह हुआ कि आकाश को हटाने के पीछे कहीं वे भाजपा को लाभ तो नहीं पहुंचाना चाहती थीं, क्योंकि आकाश भाजपा के प्रति अति आक्रामक हो रहे थे और दलित अस्मिता की राजनीति कर रहे थे।

मायावती ने 2007 में सोशल इंजीनियरिंग का जो माडल अपनाया, उससे वे 'बहुजन-हिताय, बहुजन-सुखाय' से 'सर्वजन-हिताय, सर्वजन-सुखाय' की समावेशी राजनीति तक पहुंचीं थीं और 'दलित-अस्मिता' की राजनीति पर नहीं लौट सकती थीं। मायावती माडल से भी सशक्त 'सबका-साथ, सबका-विकास' आधारित 'समावेशी माडल' मोदी ने बना लिया था। मायावती को उसकी काट नहीं सूझी। 2024 में राहुल-अखिलेश ने संविधान और आरक्षण पर भ्रम फैलाकर 'पीडीए' (पिछड़ा-दलित-अल्पसंख्यक) आधारित आंशिक समावेशी माडल बनाया, जिसका परिणाम उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनावों में दिखा।

भावी राजनीति में समावेशी माडलों की स्पर्धा देखने को मिलेगी। कौन पार्टी समाज के कितने घटकों को आकर्षित कर पाती है, यही उसकी चुनावी सफलता-असफलता को तय करेगा। हालांकि मोदी ने इसमें नया आयाम जोड़ दिया है। वे जातीय अस्मिता को वर्ग-अस्मिता तक ले गए हैं। ऐसा नहीं कि भाजपा टिकट वितरण या पद आवंटन में जातियों की अनदेखी करेगी, लेकिन उसने सभी जातियों-धर्मों को वर्गों में समेट दिया है जैसे-महिला, युवा, किसान, मजदूर, लाभार्थी और गरीब आदि। फलस्वरूप, भाजपा ने हिंदुत्व और सनातन की छतरी के नीचे सभी धर्मों और जातियों को स्थान दिया है। यह पार्टी के दूरगामी सोच और भावी रणनीति को रेखांकित करता है, जो उसके बढ़ते जनाधार का कारण है।

मायावती की सक्रियता-निष्क्रियता, दोनों ही भाजपा के पक्ष में जाती है। उनकी निष्क्रियता से आरोप लगते कि वे भाजपा को परोक्ष समर्थन दे रही हैं, लेकिन उनकी सक्रियता भी भाजपा के लिए लाभकारी होगी। त्रिकोणीय संघर्ष में बसपा ने 2007 में 30 प्रतिशत पर और सपा ने 2012 में 29 प्रतिशत पर सरकारें बनाईं। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा ने प्रदेश में खराब प्रदर्शन किया, फिर भी उसका जनाधार 41.67 प्रतिशत बना रहा। ऐसे में यदि मायावती डटकर चुनाव लड़ीं, तो वे चुनाव जीतें या नहीं, लेकिन उन जाटव-दलितों को अपनी ओर खींच सकती हैं, जो सपा की ओर चले गए थे। वैसे मायावती के अधिकतर समर्थक जाटव रहे हैं, जबकि वाल्मीकि, पासी, धोबी, कोरी, डोम जैसी गैर-जाटव जातियां प्रायः भाजपा समर्थक रही हैं। फिर 2007 में मायावती को ब्राह्मणों का साथ मिला, जो अब संभव नहीं। जिस प्रकार मोदी-योगी सरकार में दलितों को अनेक लाभ मिले, बाबा साहेब का सम्मान हुआ और उनको राजनीति की मुख्यधारा में लाया गया, उतना उन्हें मायावती की सरकार में भी नसीब नहीं था। अतः दलितों के पास कोई कारण नहीं कि वे मायावती की ओर लौटें। देखना रुचिकर होगा कि क्या मायावती नई पारी दलित-अस्मिता पर शुरू करती हैं या सोशल-इंजीनियरिंग से परिपूर्ण एक नए समावेशी-राजनीतिक-माडल का उद्घोष करती हैं।

(लेखक सेंटर फार सोसायटी एंड पालिटिक्स के निदेशक एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

बना रहे अयोध्या का प्राचीन स्वरूप

मिथिलेशनन्दिनी शरण

अयोध्या के बहुमूल्य विकास-कार्यों में अयोध्या-भाव का अनुपस्थित होना सोच में डालता है

दीवाली पर जगमग होने को तैयार अयोध्या भगवान विष्णु की पहली पुरी है। इसका तात्पर्य प्राचीनतम बसावट से है। यह प्राचीनता सनातन धर्म के मूल्य-मान की आदिम अवधारणाओं को भी सहेजे हुए है। आज की दुनिया में पुरुषार्थ की परिभाषा बदल चुकी है और मोक्ष-कामना हमारे जीवन को अनुशासित नहीं करती तथापि हमारी ज्ञान-परंपरा में मुक्ति एक विशिष्ट विचार है, जो संपूर्ण भारतीय वाङ्मय के केंद्र में विद्यमान है। अयोध्या के होने का अर्थ है हमारी सनातन जीवन दृष्टि का होना। आक्रमणकारी अभ्यागतों तथा औपनिवेशिक दुरभिसंधियों ने अयोध्या को पीढ़ियों तक मलिन किए रखा। अब जब अयोध्या पुनः अपनी अस्मिता और अपनी आध्यात्मिकता को उजागर करने की ओर है तब, इस पड़ाव तक पहुंचने में धर्म-संस्कृति के साथ ही बड़े राजनीतिक बल का विनियोग भी दृष्टि में आता है।

देश के इतिहास-भूगोल और लोक-आस्था के विषय को राजनीतिक दल अपना एजेंडा बनाते ही हैं। अयोध्या भी एक एजेंडा बनकर इस परिणति तक आई है। तटस्थ होकर देखा जा सकता है कि श्रीरामजन्मभूमि ने भाजपा को विपक्ष से सरकार में बदल दिया। भाजपा ने भी उजाड़ अयोध्या को जगमगाते शहर में बदलने में कोई कसर नहीं रखी, पर इस बदलाव के बीच कुछ बिंदु दृष्टिगोचर होते हैं, जो प्रश्नात्मक होते जाते हैं। आधुनिकता में उद्‌भासित होती हुई अयोध्या का मानक क्या हो, यह प्रश्न दिनों-दिन बड़ा होता जाता है। अयोध्या की एक शाश्वत पहचान धर्मनगरी की है। वेद-पुराण-आगम तथा अन्य अनेक साहित्य में यह हिंदू धर्म का प्रधानतम केंद्र है, किंतु सांस्कृतिक समरसता का आवरण ओढ़े राजनीतिक प्रयोग इस पहचान का निर्वाह करने को लेकर कितने सावधान हैं, यह संशयग्रस्त है। अपनी देशव्यापी स्वीकार्यता के कारण अयोध्या राजनीतिक समीकरणों की प्रयोगशाला बनने की दुश्चिंताओं से घिर रही है। यह कदाचित उसके श्रीरामजन्मभूमि वापस पाने का महंगा मूल्य सिद्ध हो। बीते वर्षों में ऐसे कई प्रसंग उभरे हैं, जिन पर ध्यान जाना स्वाभाविक है। अयोध्या की संसदीय सीट पर भाजपा की हार और उसके बाद मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव जीतने की कवायद, दोनों ही अयोध्या के मौलिक चरित्र को मलिन करने के उदाहरण बने। इसी प्रकार अयोध्या के बहुमूल्य विकास-कार्यों में प्रायः अयोध्या-भाव का अनुपस्थित होना सोच में डालता है। अयोध्या अपने मठ-मंदिरों की सेवा-चर्या अथवा उनके संरक्षण-संवर्धन से आगे बढ़कर कोई पक्ष नहीं रखती। इसका दुष्परिणाम यह है कि बदलती और बहुत-कुछ विरूपित होती जाती अयोध्या की पैरवी करता कोई स्वर सुनाई नहीं देता। अधिकांश योजनाएं कंपनियां और ठेकेदार बनाते हैं और शासन उन्हें अनुमति तथा धन देता है। अयोध्या को उसके औचित्य अथवा स्वरूप का कोई संज्ञान नहीं रहता।

आधुनिकता के साथ मौलिकता का भी रहे ध्यान ● फाइल

अयोध्या के संतों के आग्रह पर ब्रिटिश शासन में यहां के कुछ विशिष्ट स्थलों के संरक्षण हेतु लगभग डेढ़ सौ शिलालेख लगाए गए थे। बाहरी परिक्षेत्र को जाने भी दें तो भीतरी अयोध्या में भी उनका सत्यापन-संरक्षण नहीं हो पा रहा है। अयोध्या की पहचान के स्थल पौराणिक अथवा रामायणपरक होने से अधिक संगत होंगे। देश की महान विभूतियों को यहां सम्मान देने का और अधिक सुचिंतित ढंग हो सकता है। कुछ दिन पहले अयोध्या के एक मार्ग का नाम बदलकर दक्षिण के एक प्रतिष्ठित आचार्य के नाम पर किया गया। यह मार्ग काफी पहले से नगर निगम की विधि व्यवस्था द्वारा अयोध्या की संगीत परंपरा के एक विशिष्ट महानुभाव के नाम पर समर्पित था। वे अयोध्या की संगीत परंपरा के गौरव रहे, पर उनके उत्तराधिकारी इस नाम-परिवर्तन को रोकने में अक्षम रहे। यहां प्रश्न किसी एक नाम के होने या न होने तक सीमित नहीं है। यह चिंता अयोध्या के वैश्विक होने में इसकी अपनी स्थानिकता और इसकी मौलिकता के ध्वंस की है।

हाल में अयोध्या के पौराणिक स्थल बृहस्पति कुंड के जीर्णोद्धार के बाद लोकार्पण किया गया। अतिक्रमण तथा रामपथ के चौड़ीकरण से अति संकीर्ण हो चुका यह बृहस्पति कुंड अयोध्या के केंद्रीय भूभाग में अवस्थित महत्वपूर्ण स्थल है, जिसका उल्लेख रुद्रयामल के चौदहवें अध्याय तथा स्कंदपुराण के अयोध्या माहात्म्य में सातवें अध्याय में किया गया है। इस कुंड का जीर्णोद्धार करते हुए यहां दक्षिण भारत के तीन प्रमुख संतों की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। यह स्वागतयोग्य है। इस स्थल की सजावट में द्वार पर दोनों ओर बुद्ध के चेहरे लगाए गए हैं, पर बृहस्पति कुंड की पौराणिक पहचान वाले इस तीर्थ पर देवगुरु बृहस्पति की प्रतिमा ही नहीं लगाई गई।

कोई भी नया निर्माण पुरातात्विक अनुसंधान का विषय बन जाता है। यही संसार की सच्चाई है। अयोध्या को सजाते-संवारते हुए इस विचार की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए कि आने वाली पीढ़ियां जब अयोध्या को खोजती हुई आएंगी तो वे यहां रामायण के संदर्भ पा सकेंगी या फिर उन्हें आज की चुनावी परिस्थितियों के दबाव में गढ़े गए आभासी निर्माणों के साक्ष्य प्राप्त होंगे। जिनका शास्त्रों से परिचय है, वे जानते हैं कि अयोध्या अपनी प्राचीन अवस्थिति से ही समन्वयमूलक है। इसके सैकड़ों तीर्थ, ऐतिहासिक स्थल तथा कथाएं संपूर्ण भारत की एकात्मता के उदाहरण हैं। इस मोक्षदायिनी पुरी का पुनरुद्धार इसकी मौलिकता, ऐतिहासिकता तथा आध्यात्मिकता के हनन की शर्त पर नहीं होना चाहिए।

(लेखक श्रीहनुमन्निवास अयोध्या के महंत हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

महासुखी

मनुष्य जीवन एक शाश्वत यात्रा है, जहां सुख और दुख, आशा और निराशा तथा अनुकूलता और प्रतिकूलता की धूप-छांव आती-जाती रहती है। इस यात्रा में वही यात्री सुखी होता है, जो हर उतार-चढ़ाव को सहजता से स्वीकार करता है। जीवन का प्रत्येक क्षण एक विधान और एक अनुपम उपहार है। इसलिए व्यक्ति को पूर्णनिष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उसके परिणामों पर। जो पुरुषार्थी होता है, वह हर परिस्थिति में मन को शांत रखकर जीवन की धारा में तैरना सीख लेता है। ऐसे व्यक्ति को न तो सफलता का अहंकार होता है और न असफलता का विषाद। वह हर स्थिति में शांत और स्थिर रहता है, क्योंकि उसकी प्रसन्नता बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं, बल्कि भीतर के परम संतोष पर आश्रित रहती है। यही सुखी जीवन का सच्चा दर्शन और प्रबंधन है।

व्यक्ति के दुखी होने का मूल कारण निराशा का गहरा अंधकार और आशा की मृगतृष्णा है। संसार में वही प्राणी दुखी है, जो अकर्मण्य होकर निराशा के कुएं में डूबता है। वह अपनी वर्तमान स्थिति को स्वीकार नहीं कर पाता और हमेशा एक काल्पनिक भविष्य की आशा के सहारे जीता है। यह आशा ही उसके लिए पराधीनता बन जाती है। वह मृगतृष्णा की भांति सुख की लालसा में दौड़ता रहता है और अंततः थककर हताश हो जाता है। सुख की लालसा ही उसे थका देती है, क्योंकि जीवन सुख का सागर नहीं, बल्कि सुख-दुख का संगम है। जो इस सत्य को नहीं समझ पाता, वह जीवन भर असंतुष्ट और दुखी ही रहता है।

मनुष्य के सामाजिक जीवन का मूल्यांकन उसके धन, पद, बल और वैभव से कदापि नहीं किया जा सकता है। यदि ऐसा होता तो महलों और हवेलियों को हमेशा पूजा जाता, क्योंकि वे भौतिक समृद्धि के प्रतीक हैं, लेकिन सच्ची श्रेष्ठता और पवित्रता उन विचारों में निवास करती है, जो निष्काम, शुद्ध और निर्मल होते हैं।

आचार्य नारायण दास

पाठकनामा

pathaknama@nda .jagran.com

संतुलित निर्णय

'वायु प्रदूषण की चिंता' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय पढ़ा। दीपावली प्रकाश और आनंद का पर्व है, पर हर वर्ष यह वायु प्रदूषण की चिंता भी लेकर आता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की सीमित बिक्री और उपयोग की अनुमति एक संतुलित निर्णय है। यह फैसला उद्योगों और व्यापारियों के हितों की रक्षा करते हुए पर्यावरण की सुरक्षा का भी ध्यान रखता है। ग्रीन पटाखे परंपरागत पटाखों की तुलना में कम हानिकारक होते हैं, पर निगरानी तंत्र इतना प्रभावी होना चाहिए कि वास्तव में वही पटाखे बाजार में उपलब्ध हों। दीपावली पर पटाखे चलाना लोगों की भावनाओं से जुड़ा है, इसलिए पूर्ण प्रतिबंध व्यावहारिक नहीं है। हालांकि यह भी आवश्यक है कि लोग त्योहार की खुशी के साथ पर्यावरण और स्वास्थ्य की चिंता को न भूलें। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए हमें जिम्मेदारी के साथ सीमित मात्रा में ग्रीन पटाखों का उपयोग करना चाहिए और स्वच्छ, सुरक्षित दीपावली मनाने का संकल्प लेना चाहिए। यही उत्सव का सही अर्थ और संतुलन है।

sureshgoyal8@gmail.com

त्योहारों पर हो खास व्यवस्था

दीवाली और छठ महापर्व आते ही पूर्वांचल (पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड) के लोग बड़ी संख्या में बड़े शहरों (मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, लुधियाना) आदि से अपने घर त्योहारों में पहुंचते हैं। अपने परिवार तथा गांव के लोगों के साथ दीवाली और छठ महापर्व मनाने बड़े स्तर पर शहरों से गांव लौटते हैं। ऐसे में प्रशासन को चाहिए बड़े पैमाने पर ट्रेनों का परिचालन करें। क्योंकि ट्रेन ही सबसे सहज और सस्ता है। हालांकि प्रशासन ने ट्रेनों की व्यवस्था की है, जिसकी संख्या यात्रियों के तुलना में अभी भी काफी कम है। ट्रेनों की प्राप्त संख्या न होने के कारण काफी लोग घर पहुंचने के लिए मजबूरी में बसों का भी सहारा लेते हैं। जिनके किराए तीन से चार हजार रुपये हो जाते हैं। अगर ट्रेनों की संख्या और बढ़ती है, तो लोग सस्ता और सहजता से घर पहुंचेंगे।

विजय किशोर तिवारी, नई दिल्ली

गठबंधन की पेचीदगी

बिहार की सियासत एक बार फिर गठबंधन की पेचीदगियों में उलझी हुई है। चुनाव करीब हैं और सहयोगी दलों के बीच खींचतान, रूठना-मनाना और शक्ति प्रदर्शन का दौर तेज हो गया है। इस बार मैदान में एनडीए और महागठबंधन के साथ-साथ प्रशांत किशोर भी है, जिसने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। हालांकि मुख्य लड़ाई अभी भी एनडीए और महागठबंधन के बीच ही मानी जा रही है। मगर सीट बंटवारे को लेकर गहरा असंतोष दिखाई दे रहा है। एनडीए ने पहले सीटों का ऐलान कर बढ़त लेने की कोशिश की, वहीं महागठबंधन में आरजेडी द्वारा सिंबल बांटने की जल्दबाजी और फिर उसे वापस लेना, तथा सीपीआइ द्वारा महागठबंधन की सहमति से पहले उम्मीदवारों की सूची जारी कर देना। यह सारा असमंजस आरजेडी और कांग्रेस के बीच शक्ति-संघर्ष का नतीजा है।

विभूति बुपक्या, ला स्टूडेंट, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली

ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में कुछ शर्तों के साथ दीवाली पर ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति देकर दिल्ली वासियों को गदगद कर दिया है। ग्रीन पटाखे सामान्य पटाखों से अलग होते हैं, क्योंकि इनमें बेरियम नाइट्रेट जैसी जहरीली चीजें कम या बिल्कुल नहीं होतीं। ये 30-40 प्रतिशत कम प्रदूषण फैलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें मंजूरी दी है, ताकि दीवाली मनाने वाले खुश रहें, लेकिन हवा साफ रहे। ग्रीन पटाखे कम समय जलते हैं, इसलिए कम राख और धूल बनाते हैं। ग्रीन पटाखे कई तरह के होते हैं। कुछ पटाखों में अरोमा इस्तेमाल होता है। इनसे खुशबू निकलती है। यानी बारूद की बदबू नहीं आती है। ऐसे भी पटाखे मार्केट में आ सकते हैं, जिनमें जलने के बाद पानी के कण पैदा होते हैं। कुछ ग्रीन पटाखों में कम एल्यूमीनियम का इस्तेमाल किया जाता है। दिल्ली-एनसीआर जैसे इलाकों में सिर्फ यही पटाखे बेचने और जलाने की इजाजत है। वर्ष 2019 से दिल्ली में सभी पटाखों पर बैन है। सामान्य पटाखे प्रदूषण के बड़े कारण हैं। इनमें बेरियम नाइट्रेट जैसे रसायन होते हैं, जो हवा में जहर घोलते हैं। ये पटाखे 160 डेसिबल तक शोर पैदा करते हैं, जो कान और हृदय के लिए हानिकारक है। साथ ही, ये ज्यादा धुआं छोड़ते हैं, जो दिल्ली जैसे शहरों में स्मॉग बढ़ाता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि ग्रीन पटाखे 'ग्रीनवाशिंग' नहीं, बल्कि असली सुधार हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर इस्तेमाल से भी समस्या हो सकती है। ग्रीन पटाखे सिर्फ प्रमाणित विक्रेताओं से मिलते हैं।

युगल किशोर राही, ग्रेटर नोएडा

पोस्ट

डूरंड रेखा पर पाकिस्तान के साथ वास्तविक लड़ाई के साथ-साथ नैरेटिव के मामले में भी अफगानिस्तान ने शानदार प्रदर्शन किया है। इससे सीख लेने की जरूरत है। भारत के लिए भी आवश्यक हो गया है कि एक एकीकृत सूचना केंद्र की स्थापना पर ध्यान दिया जाए।
केजेएस ढिल्लों@TinyDhillon

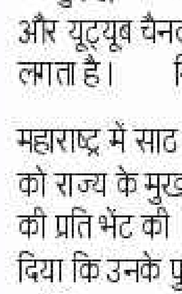

अमेरिका के विदेश नीति टिप्पणीकार एश्ले टेलिस चीनी जासूस हैं या नहीं, यह बात तो ट्रायल शुरू होने के बाद पता चलेगी। हालांकि भारत में मीडिया से लेकर तमाम एनजीओ में ऐसे लोग भरे हुए हैं, जो बीजिंग के लिए काम करते हैं। कुछ पोर्टल और यूट्यूब चैनलों का कंटेंट देखकर ही यह जाहिर होने लगता है। मिन्हाज मर्चेंट@MinhazMerchant

महाराष्ट्र में साठ से अधिक माओवादी नेताओं और कैडर को राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संविधान की प्रति भेंट की। उनके कंधों पर हाथ रखा और वचन दिया कि उनके पुनर्वास के लिए सरकार हरसंभव मदद करेगी। यह भारतीय संविधान और राष्ट्र की जीत नहीं, राष्ट्र में निहित समावेश, करुणा और उदारता की भावना का प्रतीक है। दिलीप मंडल@Profdilipmandal

जनपथ

मां काली के देश में महिषासुर का वास,
लेकिन ममता को नहीं होता यह अहसास।
होता यह अहसास तो ना कहतीं यह बातें,
हैं नारी के हेतु सुरक्षित ना अब रातें!
यदि अक्षम हैं आप कीजिए कुर्सी खाली,
करें न्याय इस बार नहीं तो खुद मां काली!!
- ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित, संपादक (दिल्ली एनसीआर)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No 50755/90 समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। वर्ष 36 अंक 92

****

सेंसेक्स	सराफा	सोना	चांदी	डालर($)
83,467.66 ↑862.23	दिल्ली के भाव	₹ 1,31,600 (10 ग्राम) ↓₹ 200	₹1,84,000 (1 किलो) ↑₹2,000	₹ 87.96 ↓₹ 0.12

एक नजर में

क्विक कामर्स कंपनी जेप्टो ने 45 करोड़ डालर जुटाए

नई दिल्ली: क्विक कामर्स प्लेटफार्म की प्रमुख कंपनी जेप्टो ने गुरुवार को बताया कि उसने कैलिफोर्निया पब्लिक एम्प्लाइज रिटायरमेंट सिस्टम के नेतृत्व में सात अरब डालर के मूल्यांकन पर 45 करोड़ डालर (3,757.5 करोड़ रुपये) जुटाए हैं। यह फंडिंग पिछले साल नवंबर में आई 35 करोड़ डालर के फंडिंग राउंड के लगभग एक साल बाद आई है। कंपनी के सीईओ और सह संस्थापक आदित पलिचा ने बताया, 'अब हमारे पास बैंक में लगभग 90 करोड़ डालर की शुद्ध नकदी है। (प्रेट्र)

इन्फोसिस का शुद्ध लाभ 13 प्रतिशत बढ़ा

नई दिल्ली: सूचना-प्रौद्योगिकी कंपनी इन्फोसिस का सितंबर तिमाही में शुद्ध लाभ 13.2 प्रतिशत बढ़कर 7,364 करोड़ रुपये हो गया। एक साल पहले 6,506 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया था। परिचालन से राजस्व 8.6 प्रतिशत बढ़कर 44,490 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले 40,986 करोड़ रुपये था। साल-दर-साल और तिमाही आधार पर परिचालन मार्जिन में गिरावट दर्ज की गई और यह 21 प्रतिशत पर आ गया। तिमाही में कर्मचारियों की संख्या 8,203 बढ़ाकर 3,31,991 कर दी, जो जून 2025 तिमाही में 3,23,788 थी। (प्रेट्र)

16 हजार कर्मचारियों की छंटनी करेगी नेस्ले

न्यूयार्क: नेस्ले वैश्विक स्तर पर 16,000 लोगों की छंटनी करेगी। अगले दो सालों में नौकरियों में कटौती की जाएगी। कंपनी ने कहा कि वह विभिन्न देशों में 12,000 व्हाइट-कालर पदों (आफिस में बैठकर काम करने वाले) को समाप्त करेगी। इन नौकरियों को समाप्त करने से अगले साल के अंत तक कंपनी को 1 अरब स्विस फ्रैंक (1.25 अरब डालर) की वार्षिक बचत होने की उम्मीद है। कंपनी अपने विनिर्माण और सप्लाई चेन में चल रही उत्पादकता पहलों के तहत 4,000 नौकरियों में कटौती करेगी। (एपी)

विकसित देश भारत से बढ़ाना चाहते हैं व्यापार

वाणिज्य मंत्री बोले-पिछले तीन सालों में हमने आर्थिक रूप से संपन्न कई देशों से किए व्यापार समझौते

- न्यूजीलैंड, चिली, पेरू जैसे कई देशों के साथ चल रही वार्ता, ईयू के साथ बातचीत लगभग पूरी
- अमेरिका के साथ समझौते से जुड़े मुद्दे पर बातचीत के लिए भारतीय दल अभी वाशिंगटन में

पीयूष गोयल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : दुनिया के सभी प्रमुख देश भारत के साथ व्यापार बढ़ाना चाहते हैं। आस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) जैसे विकसित देशों के बाद यूरोप के चार देशों के समूह ईएफटीए (यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ) के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू हो चुका है। अब जल्द ही यूरोपीय यूनियन (ईयू) के साथ भारत का व्यापार समझौता होने जा रहा है। ब्रिटेन के साथ भारत का व्यापार समझौता हो चुका है, जो अगले साल मार्च-अप्रैल से अमल में आ जाएगा। वाणिज्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक ईयू के साथ व्यापार समझौते की वार्ता लगभग पूरी हो चुकी है। एफ्टा देशों में स्विट्जरलैंड, नार्वे, आइसलैंड और लेस्टेंस्टाइन शामिल हैं।

गुरुवार को नई दिल्ली में एक उद्योग संगठन के कार्यक्रम के बाद वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि पिछले तीन सालों में हमने कई विकसित देशों के साथ व्यापार समझौता किए हैं और अभी अमेरिका, ईयू, न्यूजीलैंड, पेरू, चिली और ओमान के साथ व्यापार समझौते को लेकर वार्ता में काफी तेजी है। यह साफ दर्शाता है कि भारत सिर्फ व्यापार के लिए ही नहीं, निवेश के लिए प्रमुख स्थान बनता जा रहा है। यूरोपीय यूनियन के साथ भी व्यापार वार्ता इस साल होने की पूरी उम्मीद है। ओमान के साथ वार्ता पूरी हो चुकी है। अब दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर होना बाकी है। उसके बाद यह अमल में आएगा। पेरू के साथ नौवें चरण की वार्ता आगामी नवंबर में होने जा रही है तो चिली के साथ व्यापार समझौते पर तीसरे चरण की बातचीत इस माह के आखिर में होगी। ब्राजील के साथ भी व्यापार बढ़ाने को लेकर गंभीर बातचीत चल रही है और दोनों ही देश एक-दूसरे के बाजार में बड़ी संभावना देख रहे हैं।

हम मजबूत आर्थिक बुनियाद बनाना चाहते हैं: पीयूष गोयल

नई दिल्ली, एएनआइ: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि भारत कम से कम अगले 20 वर्षों तक सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहना चाहता है। भारत-ब्राजील व्यापार वार्ता में बोलते हुए गोयल ने कहा, 'हमारा प्रयास मजबूत आर्थिक बुनियाद बनाने का रहा है, चाहे वह मुद्रास्फीति का कम रखना हो, वृद्धि को लगातार मजबूत करना हो और चाहे यह सुनिश्चित करना हो कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत रहे। 700 अरब डालर के भंडार के साथ हम उन शीर्ष पांच देशों में शामिल हैं, जिनके पास सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार है।

ट्रेड डील से सेवा निर्यात को भी मिलेगा बढ़ावा

अमेरिका के साथ व्यापार समझौते से जुड़े मुद्दे पर बातचीत के लिए भारत का दल अभी अमेरिका में है। अब तक दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता को लेकर पांच चरण की वार्ता हो चुकी है और इस साल नवंबर में व्यापार समझौते के पहले चरण को पूरा कर लिया जाएगा। विदेश व्यापार जानकारों का कहना है कि इन देशों के साथ व्यापार समझौता होने से वस्तु निर्यात के साथ सेवा निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा और इन देशों में भारतीय प्रोफेशनल्स को भी अपना कारोबार करने का अवसर मिलेगा। निर्यात को बढ़ाने के लिए भारत ने अफ्रीका के कई देशों में भी निर्यात करना शुरू कर दिया है। तभी अमेरिका होने वाले निर्यात में इस साल अगस्त की तुलना में सितंबर के निर्यात में 20 प्रतिशत की गिरावट के बावजूद भारत के निर्यात में छह प्रतिशत की बढ़ोतरी रही।

वैश्विक विकास में काफी योगदान दे रहा है भारत : आइएमएफ

वाशिंगटन, आइएएनएस: अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जार्जीवा ने गुरुवार को कहा कि भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था में 'बेहद महत्वपूर्ण सुधार' किए हैं और देश वैश्विक विकास में काफी योगदान दे रहा है। वाशिंगटन में आइएमएफ-विश्व बैंक की वार्षिक बैठक के दौरान एक प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए, जार्जीवा ने कई क्षेत्रों में भारत के सुधार प्रयासों का जिक्र किया। उन्होंने कहा, "भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और वह आज इस मुकाम पर इसलिए है क्योंकि उसने कई महत्वपूर्ण सुधार (कर सुधार, बुनियादी ढांचे में निवेश, डिजिटल बुनियादी ढांचा) किए हैं। आइएमएफ ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में भारत के विकास अनुमान को 0.2 प्रतिशत अंकों की वृद्धि के साथ 6.6 प्रतिशत कर दिया था।

यूआरएल को सुरक्षित रखना होगा अनिवार्य

11 बैंकों में कामर्शियल काल के लिए ग्राहकों से डिजिटल अनुमति लेने का पायलट प्रोजेक्ट है जारी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : साइबर फ्राड को रोकने के लिए आने वाले समय में यूआरएल (यूनिफार्म रिसोर्स लोकेटर) और ओवर द टाप (ओटीटी) लिंक की व्हाइटलिस्टिंग को अनिवार्य किया जा सकता है। यूआरएल की व्हाइटलिस्टिंग के बाद किसी लिंक को मंजूरी प्राप्त सूची के लोग ही खोल सकते हैं, बाकी के लोग उस लिंक को नहीं खोल पाएंगे। जिन्हें उसकी मंजूरी नहीं होगी, उनके क्लिक करने पर अपने आप लिंक खुलने से इन्कार कर देगा। इसे अनिवार्य करने से कई महत्वपूर्ण लिंक को विदेश में बैठे हैकर खोल नहीं पाएंगे।

गुरुवार को साइबर फ्राड और स्पैम काल की रोकथाम के लिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की तरफ से नियामकों की संयुक्त समिति की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें यूआरएल और ओटीटी लिंक की व्हाइटलिस्टिंग को अनिवार्य करने पर गंभीरता से विचार किया गया। बैठक में स्पैम काल को रोकने के लिए काल से पहले ग्राहकों से डिजिटल मंजूरी लेने के फैसले पर अमल की प्रगति की समीक्षा की गई। स्पैम काल को रोकने के लिए इन दिनों डिजिटल कंसेंट एक्विजिशन को लेकर पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। इसके तहत कामर्शियल काल करने के लिए ग्राहकों से मंजूरी लेने का काम किया जा रहा है। 11 बैंकों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में डिजिटल मंजूरी का काम चल रहा है।

मंजूरी के बाद ही आपके पास आ सकेंगे कामर्शियल काल

जुलाई में समिति की बैठक में ग्राहकों से डिजिटल मंजूरी लेने का फैसला किया गया था। फैसले को लागू करने के बाद सिर्फ उन्हीं व्यक्ति के पास कामर्शियल काल आएंगे, जिन्होंने इसकी मंजूरी दी है। बैठक में उन सभी संस्थाओं के नाम को ट्राई और टेलीकाम कंपनियों की वेबसाइट पर जारी करने की बात की गई जिन्हें स्पैम या बिना इजाजत के कामर्शियल काल करने के कारण काली सूची में डाला गया है। समिति के सदस्यों ने कहा कि इन संस्थाओं को सार्वजनिक करने से स्पैम काल पर लगाम लगाने में और मदद मिलेगी।

बिजनेस से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

भारत में 85 प्रतिशत डिजिटल भुगतान यूपीआइ के जरिये : आरबीआइ

नई दिल्ली, प्रेट्र: आरबीआइ गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि भारत में 85 प्रतिशत डिजिटल भुगतान यूपीआइ के माध्यम से होते हैं और देश समावेशी और सुरक्षित डिजिटल सार्वजनिक मंच के मामले में अध्ययन का विषय बन सकता है।

उन्होंने मंगलवार को वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की वार्षिक बैठकों के दौरान आरबीआइ द्वारा आयोजित 'डिजिटल सार्वजनिक मंच' (डीपीपी) के माध्यम से आर्थिक मजबूती बनाने पर उच्च-स्तरीय बातचीत' में यह कहा। उन्होंने कहा कि 'वसुधैव कुटुम्बकम' की सच्ची भावना के अनुरूप, भारत डिजिटल बदलाव में तेजी लाने के लिए ऐसे मंच के इर्द-गिर्द अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, 'भारत समावेशी और सुरक्षित डीपीपी के मामले में एक उदाहरण है।

सेंसेक्स 862 अंक उछला निफ्टी चार माह के शीर्ष पर

261.75 अंक बढ़कर 25,585.30 पर पहुंचा एनएसई का मानक सूचकांक

83,467.66 पर बंद हुआ तीस शेयरों पर आधारित बीएसई का मानक सूचकांक

- 0.47% चढ़ा स्मालकैप सूचकांक
- 0.29% बढ़ा मिडकैप सूचकांक
- 2,377 शेयर लाभ में रहे
- 1,810 शेयरों में गिरावट रही
- 147 शेयर के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ

मुंबई, प्रेट्र: वैश्विक शेयर बाजारों में तेजी और अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद से निवेशकों की चौतरफा खरीदारी से स्थानीय शेयर बाजार में तेजी का सिलसिला गुरुवार को भी जा रहा। तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 862.23 अंक यानी 1.04 प्रतिशत चढ़कर 83,467.66 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान, एक समय यह 1,010.05 अंक तक चढ़ गया था। पचास शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 261.75 अंक यानी 1.03 प्रतिशत बढ़कर 25,585.30 अंक पर पहुंच गया।

सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में कोटक महिंद्रा बैंक में सबसे ज्यादा 2.67 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई। इसके अलावा टाइटन, एक्सिस बैंक, अदाणी पोर्ट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स और एचडीएफसी बैंक प्रमुख रूप से लाभ में रहीं। दूसरी तरफ, इटर्नल और इन्फोसिस नुकसान में रहीं। लेमन मार्केट्स डेस्क के शोध विश्लेषक गौरव गर्ग ने कहा, 'भारतीय शेयर बाजारों में गुरुवार को बढ़त जारी रही। सेंसेक्स लगभग 1,000 तक चढ़ा और निफ्टी चार महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। बैंक शेयरों में मजबूती और मजबूत वैश्विक संकेतों से यह बढ़त हासिल हुई।' उन्होंने कहा, 'अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद और आइएमएफ द्वारा भारत की वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ाए जाने से बाजार धारणा मजबूत हुई।'

> सकारात्मक वैश्विक संकेतों और भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता को लेकर नई उम्मीद बंधने से उत्साहित घरेलू शेयर बाजारों ने बढ़त को जारी रखा। वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही में मांग में सुधार की उम्मीद, एफआइआइ निवेश के शुरुआती संकेत, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नरम नीतिगत टिप्पणियों और डालर सूचकांक में नरमी से बाजार धारणा को और बल मिला। - **विनोद नायर**, रिसर्च हेड, जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड

रुपया 12 पैसे बढ़कर 87.96 प्रति डालर पर

मुंबई, प्रेट्र: रुपया गुरुवार को डालर के मुकाबले 12 पैसे बढ़कर 87.96 पर बंद हुआ। अमेरिकी मुद्रा के कमजोर होने और निवेशकों में जोखिम की भावना के फिर से उभरने से यह तेजी आई। कारोबारियों ने कहा कि आरबीआइ के संभावित हस्तक्षेप और घरेलू शेयर बाजारों में मजबूत रुख ने निवेशकों को उत्साहित किया। विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में, रुपया डालर के मुकाबले 88 के स्तर से नीचे 87.76 पर खुला और कारोबार के दौरान 87.68 प्रति डालर के उच्चतम स्तर को छू गया। घरेलू मुद्रा अंततः डालर के मुकाबले 87.96 पर बंद हुई, जो पिछले बंद भाव से 12 पैसे की वृद्धि है। बुधवार को रुपया 73 पैसे की तेजी के साथ 88.08 प्रति डालर पर बंद हुआ था, जो चार महीनों में एकदिन की सबसे बड़ी तेजी थी।

प्रोपेलीन ग्लाइकाल खरीद का बिल श्रीसन फार्मा से गायब

- मध्य प्रदेश पुलिस ने केमिकल एनालिस्ट को तीन दिनों के रिमांड पर लिया
- प्रोपेलीन ग्लाइकाल की आपूर्ति करने वाले को बनाया जा सकता है आरोपित

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल : मध्य प्रदेश के तीन जिलों में 24 बच्चों की जान लेने वाले 'कोल्ड्रिफ' कफ सीरप में उद्योगों में उपयोग होने वाला प्रोपेलीन ग्लाइकाल मिलाए जाने की जांच चल रही है। इस मामले में श्रीसन फार्मा कंपनी की केमिकल एनालिस्ट के. माहेश्वरी को तमिलनाडु से गिरफ्तार किया गया है। एसआइटी जांच में सामने आया है कि कफ सीरप बनाने में उपयोग होने वाले प्रोपेलीन ग्लाइकाल का बिल कंपनी से गायब है। जांच इसी पर निर्भर है कि इस केमिकल के आपूर्तिकर्ता को औषधीय उपयोग वाले प्रोपेलीन ग्लाइकाल का आर्डर दिया गया था या औद्योगिक उपयोग वाले का। यदि आपूर्तिकर्ता ने औद्योगिक उपयोग वाला प्रोपेलीन ग्लाइकाल दिया तो उसे भी आरोपित किया जा सकता है।

एसआइटी के. माहेश्वरी को लेकर बुधवार को छिंदवाड़ा के परासिया पहुंची। यहां उसे न्यायालय में प्रस्तुत कर तीन दिनों के रिमांड पर लिया गया। पुलिस माहेश्वरी से यह जानने का प्रयास करेगी कि कंपनी में गुणवत्ता जांच में क्या लापरवाही हुई और असली जिम्मेदार कौन है। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के नियमों की कहां अनदेखी की गई है। सूत्रों के अनुसार, एसआइटी ने माहेश्वरी से कोल्ड्रिफ कफ सीरप की गुणवत्ता जांच रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन वह नहीं दी गई। संदेह है कि सीरप की टेस्टिंग कराई ही नहीं गई थी। उल्लेखनीय है कि कफ सीरप में डायथिलीन ग्लाइकाल (डीइजी) की मात्रा 48.6 प्रतिशत पाई गई थी, जबकि इसकी मान्य सीमा 0.1 प्रतिशत है। डीइजी के कारण ही बच्चों की जान गई। इस मामले में अब तक कफ सीरप लिखने वाले डा. प्रवीण सोनी, कंपनी के मालिक जी. रंगनाथन और के. माहेश्वरी सहित पांच आरोपितों की गिरफ्तारी हो चुकी है।

एजी ने दी सीजेआइ पर जूता फेंकने का प्रयास करने वाले वकील पर अवमानना कार्यवाही शुरू करने पर सहमति

- एससीबीए अध्यक्ष व सालिसिटर जनरल ने मामला सूचीबद्ध करने का किया अनुरोध
- दूसरों की गरिमा की कीमत पर नहीं कर सकते अभिव्यक्ति के अधिकार का प्रयोग : शीर्ष कोर्ट

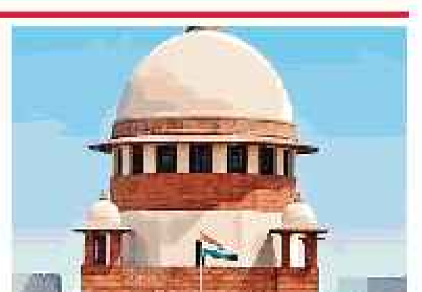

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: अटार्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) बीआर गवई पर जूता फेंकने का प्रयास करने वाले वकील राकेश किशोर के विरुद्ध आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने पर सहमति दे दी है। गुरुवार को सालिसिटर जनरल तुषार मेहता और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के अध्यक्ष विकास सिंह ने सीजेआइ के बाद सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का जिक्र करते हुए यह जानकारी दी। साथ ही आरोपित वकील राकेश किशोर के विरुद्ध आपराधिक अवमानना का मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। इस दौरान पीठ ने कहा कि अभिव्यक्ति के अधिकार का इस्तेमाल दूसरों की गरिमा और शुचिता की कीमत पर नहीं किया जा सकता।

गत छह अक्टूबर को वकील राकेश किशोर ने प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ में उन पर जूता फेंकने का प्रयास किया था। हालांकि प्रधान न्यायाधीश ने घटना से प्रभावित हुए बगैर इसे नजरअंदाज कर दिया था और शांत भाव से कोर्ट की सुनवाई जारी रखी थी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस घटना की कड़ी निंदा की थी और राकेश किशोर के विरुद्ध आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने पर अटार्नी जनरल आर. वेंकटरमणी से सहमति मांगी थी। किसी के विरुद्ध आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए अटार्नी जनरल या सालिसिटर जनरल की सहमति जरूरी होती है।

हालांकि कोर्ट अवमानना मामले को तत्काल सुनवाई पर लगाने का इच्छुक नहीं दिखा। पीठ ने कहा, देखते हैं कि अगले सप्ताह तक कुछ इसमें बचता है या नहीं। पीठ ने यह भी सवाल किया कि क्या इस मुद्दे को आगे बढ़ाना ठीक होगा, जबकि प्रधान न्यायाधीश ने स्वयं उन्हें माफ कर दिया है। सिंह ने कहा, लेकिन जिस तरह से यह घटना इंटरनेट मीडिया पर प्रचारित हो रही है उससे संस्था का नुकसान हो रहा है। जस्टिस जोयमाल्या बागची ने कहा, लेकिन इस घटना को फिर से उठाने से प्रचार चाहने वालों को और अवसर नहीं मिलेगा? हालांकि बाद में कोर्ट ने दीपावली की छुट्टियों के बाद कोर्ट खुलने पर मामले को सूचीबद्ध करने पर सहमति दी।

इस दौरान जब विकास सिंह ने बताया कि राकेश किशोर ने खेद व्यक्त नहीं किया है और साक्षात्कार दे रहे हैं, जो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहे हैं और शीर्ष अदालत की संस्थागत शुचिता को प्रभावित कर रहे हैं, तो पीठ ने कहा, 'हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन इस अधिकार का इस्तेमाल दूसरों की गरिमा और शुचिता की कीमत पर नहीं किया जा सकता।'

विकास सिंह ने कहा, 'इस घटना को लेकर इंटरनेट मीडिया पर हंगामा मच गया है। वह लगातार साक्षात्कार दे रहे हैं और यह अब भी जारी है। कृपया इंटरनेट मीडिया को ऐसी सामग्री प्रसारित करने से रोकें। मैं जान डो आदेश की तर्ज पर आदेश का अनुरोध कर रहा हूं।' जान डो आदेश, अदालत द्वारा पारित एक प्रकार का कानूनी आदेश होता है जो किसी व्यक्ति या संस्था को किसी अज्ञात पक्ष या पक्षों के विरुद्ध कार्रवाई करने की अनुमति देता है। इससे पहले मेहता ने कहा कि इंटरनेट मीडिया मंच एल्गोरिदम पर काम करते हैं और इस प्रकार की घटनाएं व टिप्पणियां ऐसे उत्पाद हैं जिनसे अंततः पैसा कमाया जाता है। जस्टिस सूर्यकांत ने इंटरनेट मीडिया की अनियंत्रित प्रकृति को रेखांकित करते हुए कहा कि उनके लिए, 'हम उत्पाद भी हैं और उपभोक्ता भी।'

गोहत्या में फर्जी तरीके से फंसाने के मामलों की आ रही बाढ़ : कोर्ट

- इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कहा- उत्तर प्रदेश में गोवंशी का परिवहन अपराध नहीं
- प्रमुख सचिव-डीजीपी से गोहत्या अधिनियम के दुरुपयोग पर जवाब देने को लेकर मांगा शपथ-पत्र

विधि संवाददाता, लखनऊ : इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने दोहराया है कि उत्तर प्रदेश में गोवंशी पशुओं का परिवहन अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। न्यायालय के सामने ऐसे मुकदमों की बाढ़ आ रही, जिसमें लोगों को गोहत्या अधिनियम में फर्जी तरीके से फंसाया जा रहा है। कोर्ट ने प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और डीजीपी राजीव कृष्ण से शपथ-पत्र मांगा है कि गोहत्या अधिनियम के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या किया गया है? सात नवंबर तक शपथ-पत्र नहीं आता है तो दोनों अधिकारी कोर्ट में स्वयं प्रस्तुत होकर उत्तर दें। कोर्ट ने उक्त दोनों शीर्ष अधिकारियों से पूछा है कि क्यों नहीं ऐसे मामलों में सरकार पर भारी जुर्माना लगाया जाए। इसके अतिरिक्त न्यायालय ने गोवंशी पशुओं के मामलों में भीड़ हिंसा व कुछ लोगों-संगठनों की अति सक्रियता पर लगाम लगाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में भी उत्तर मांगा है।

यह आदेश जस्टिस अब्दुल मोईन व जस्टिस एके चौधरी की पीठ ने प्रतापगढ़ के वाहन मालिक राहुल यादव की याचिका पर पारित किया। कोर्ट ने कहा कि इन दिनों उसके सामने गोहत्या अधिनियम में फर्जी फंसाए जाने के बहुत मामले आ रहे हैं, जिनमें याची का काफी पैसा और कोर्ट का बहुमूल्य समय बर्बाद हो जाता है। कोर्ट ने कहा कि प्रदेश में गोवंशी पशुओं का मात्र परिवहन करना अपराध नहीं है। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए पाया कि याची को पुलिस केवल इसलिए परेशान कर रही थी, क्योंकि गाड़ी उसके नाम पंजीकृत थी। गाड़ी उसका ड्राइवर चला रहा था और उस पर नौ गोवंशी पशु लादकर अमेठी से प्रतापगढ़ ले जाए जा रहे थे। कोर्ट ने पाया कि सभी नौ गोवंशी पशुओं को कोई चोट नहीं थी और ना ही उनका वध ही हुआ था, ऐसे में याची को गोहत्या अधिनियम में फंसना गलत है।

नारायण-सुधा मूर्ति का जाति सर्वे में भाग लेने से इन्कार

- मूर्ति ने लिखा, हम किसी पिछड़ी जाति से नहीं हैं, जानकारी देने से किया इन्कार
- उपमुख्यमंत्री ने कहा, किसी को भी जानकारी देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते

नारायण और सुधा मूर्ति

बेंगलुरु, प्रेट्र : इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति और उनकी पत्नी सुधा मूर्ति ने कर्नाटक में चल रहे सामाजिक और शैक्षणिक सर्वेक्षण, जिसे जाति सर्वेक्षण कहा जाता है, में भाग लेने से इन्कार कर दिया है। उनका कहना है कि वे किसी भी पिछड़ी जाति से संबंधित नहीं हैं। कुछ दिन पहले जब सर्वे करने वाले उनके यहां पहुंचे तो दोनों ने कथित तौर पर उनसे कहा, "हम सर्वेक्षण में शामिल नहीं होना चाहते।" इस बीच, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से जब सुधा मूर्ति के बयान के बारे में पूछा गया कि वह जाति जनगणना के लिए जानकारी नहीं देंगी, तो उन्होंने कहा, "हम किसी को भी मजबूर नहीं कर सकते।"

सुधा मूर्ति ने सामाजिक और शैक्षणिक सर्वेक्षण 2025 के लिए कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा जारी एक प्रोफार्मा में जानकारी देने से इन्कार करने के लिए एक स्व-घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। प्रोफार्मा में लिखा है, "निजी कारणों से मैं कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा किए जा रहे जाति सर्वे में जानकारी देने से इन्कार कर रही हूं।" सुधा मूर्ति ने कन्नड़ में लिखा, 'हम किसी भी पिछड़े समुदाय से नहीं हैं। इसलिए, हम ऐसे समूहों के लिए सरकार द्वारा किए गए सर्वेक्षण में भाग नहीं लेंगे।

सरकारी स्कूल में एआइ और रोबोटिक लैब खोल रही भविष्य की राह

जागरण विशेष

रानीखेत में प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थी कर रहे एआइ का उपयोग, ड्रोन उड़ाने में बन रहे हैं माहिर

दीप सिंह बोरा • जागरण

प्राथमिक विद्यालय में बच्चे रोबोट चलाने व ड्रोन उड़ाने में हो रहे दक्ष • जागरण

> ये नवाचार शिक्षा में तकनीक को सरल, सुलभ व बाल मैत्रीपूर्ण बनाने के लिए हैं। मेरा प्रयास है कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण व रोचक शिक्षा मिले। इसीलिए हम तकनीकी व गैरतकनीकी दोनों माध्यमों का प्रयोग करते आ रहे हैं।
> - **भाष्कर जोशी**, प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय मटीलाधूरा

अल्मोड़ा: पहाड़ के मुश्किल जीवन के बीच रानीखेत में मटीलाधुरा स्थित प्राथमिक विद्यालय नवाचार के जरिए शिक्षा जगत में नई क्रांति का सूत्रपात कर रहा है। यह प्राथमिक शिक्षा के लिए अनुकरणीय उदाहरण बना है। यहां की नवाचारी शिक्षा दुर्गम गांवों से आने वाले बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की राह खोल रही है। छोटी कक्षाओं के विद्यार्थी ड्रोन उड़ाने में दक्ष बनने के साथ ही कृत्रिम बुद्धिमता (एआइ) और रोबोटिक्स का ककहरा भी सीख रहे हैं। नए-नए शिक्षण एप का विकास शिक्षा के स्तर को भी बढ़ा रहा है।

उत्तराखंड में प्राथमिक स्तर पर पहली एआइ व रोबोटिक्स प्रयोगशाला तैयार करने वाले स्कूल के प्रधानाध्यापक भाष्कर जोशी ने विद्यार्थियों के लिए उपयोगी कई एप विकसित किए हैं। चैटबाट का उपयोग तो पढ़ाई में हो ही रहा था अब 'नो इंटरनेट क्विज' नाम से एप भी विकसित किया गया है।

भाष्कर जोशी बताते हैं कि कोरोनाकाल में धौलादेवी ब्लाक में तैनाती के दौरान बच्चों को पढ़ाने के लिए आनलाइन एजुकेशन एप विकसित किया। इसके बाद वह लगातार नए-नए प्रयोग करते रहे। पिछले वर्ष प्राथमिक स्तर पर उत्तराखंड की पहली आर्टीफिशियल इंटेलीजेंस आधारित लैब तैयार कर बच्चों को एआइ की पढ़ाई शुरू कराई। यहां गांवों के बच्चे अब ड्रोन भी उड़ाने लगे हैं।

एआइ चैटबाट विद्यार्थी ही नहीं शिक्षकों के लिए भी उपयोगी: नवाचार के तहत ग्रामीण प्रतिभाओं को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी व करियर संवारने के उद्देश्य से प्रधानाध्यापक भाष्कर ने एआइ चैटबाट विकसित किया है। यह विद्यार्थियों के लिए बेहद उपयोगी है। लिंक को क्लिक करने पर एआइ चैटबाट विद्यार्थी से जानकारी लेता है। वह सामान्य रुचि आधारित दस से 12 प्रश्न पूछता है। जवाब न देने पर भी विद्यार्थी का आकलन करता है। मटीलाधुरा के तारा सिंह बिष्ट बताते हैं कि इस नवाचारी शिक्षा के प्रयास से विद्यालय के बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ी है। वहीं निदेशक माध्यमिक शिक्षा मुकुल सती ने बताया कि इतने दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्र में यह प्रयास अनुकरणीय है।

देश-दुनिया का सामान्य ज्ञान: भास्कर ने अब जो 'नो इंटरनेट क्विज' एंड्रायड लर्निंग मोबाइल एप विकसित किया है, उसके जरिये नौनिहाल देश-प्रदेश व दुनिया से जुड़ी सामान्य प्रश्नोत्तरी में निपुण बन सकेंगे। इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर फिर बिना इंटरनेट कनेक्शन के बिना भी चलाया जा सकेगा। एप के जरिये बच्चे स्वयं प्रश्नोत्तरी हल कर इसकी जांच भी कर सकते हैं। साथ ही पीडीएफ से प्रश्न निकाल इसे साझा भी कर सकेंगे। अल्मोड़ा के मुख्य शिक्षा अधिकारी अतरेश सयाना ने बताया कि प्राथमिक शिक्षा के लिए एआइ का उपयोग सराहनीय प्रयास है।

अतिरिक्त सामग्री पढ़ने के लिए स्कैन करें।

****

37 प्रत्याशी पिछड़ा वर्ग से दिए हैं जदयू ने अपनी दोनों सूची में, अतिपिछड़ा वर्ग व सामान्य श्रेणी के प्रत्याशियों की संख्या 22-22 रखी है।

'बिहार एसआइआर अभियान सटीक, झूठे आरोप लगा रहे दल'

- आयोग ने शीर्ष कोर्ट में कहा-अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद से एक भी मतदाता ने नाम हटाने के खिलाफ अपील दायर नहीं की

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान को सटीक बताते हुए गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि याचिकाकर्ता राजनीतिक दल और एनजीओ केवल झूठे आरोप लगाने में लगे हैं ताकि इस प्रक्रिया को बदनाम किया जा सके। आयोग ने शीर्ष कोर्ट को बताया कि अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद से किसी भी मतदाता द्वारा नाम हटाने के खिलाफ एक भी अपील दायर नहीं की गई है।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से चुनाव आयोग पर अंतिम मतदाता सूची से हटाए गए नामों का ब्योरा प्रकाशित न किए जाने का आरोप लगाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी को समझता है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जायमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि नाम जोड़ने और हटाने के बाद आयोग इसे प्रकाशित करने के लिए बाध्य है। इस मामले में याचिकाकर्ता एडीआर के वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट में कहा कि चुनाव आयोग ने जिन लोगों को अंतिम मतदाता सूची से हटाया है, उनका ब्योरा सार्वजनिक नहीं किया है और न ही इसके कारण बताए हैं। आयोग का कहना है कि उसने सभी को नोटिस और आदेश दिए हैं, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें नोटिस नहीं मिला। भूषण ने कोर्ट से अनुरोध किया कि जिनका नाम जनवरी की समीक्षा मतदाता सूची में था लेकिन प्रारूप सूची में हटा दिया गया, उनका ब्योरा भी आयोग सार्वजनिक करे। इसके बाद जिनका नाम प्रारूप सूची में था लेकिन अंतिम मतदाता सूची से हटा दिया गया, उसका ब्योरा भी सार्वजनिक किया जाए। चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए यह आवश्यक है।

चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि इस संबंध में कोर्ट को आदेश देने की आवश्यकता नहीं है, आंकड़े प्रकाशित किए जाएंगे और पहले भी किए गए हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी जानता है, नाम जोड़ने और हटाने के बाद, उसे इसे प्रकाशित करने के लिए बाध्य होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि वह चुनाव आयोग से अपेक्षा करता है कि एसआइआर के बाद तैयार की गई अंतिम मतदाता सूची में टाइपिंग संबंधी त्रुटियों और अन्य गलतियों को एक जिम्मेदार प्राधिकारी के रूप में देखेगा और सुधारात्मक उपाय लेकर आएगा। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई चार नवंबर को तय की है।

पोर्टल पर अपलोड हुए बंगाल के 3.48 करोड़ मतदाताओं के नाम

राज्य ब्यूरो, जागरण • कोलकाता: बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) की प्रक्रिया शुरू होने से पहले चुनाव आयोग के वेब पोर्टल पर 3.48 करोड़ मतदाताओं के नाम अपलोड किए जा चुके हैं। बंगाल में 2002 में हुए एसआइआर के आंकड़ों से मिलान करके लोगों के नाम वेब पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं। यह राज्य के कुल मतदाताओं का 44.7 प्रतिशत है। 2025 की मतदाता सूची के अनुसार बंगाल में कुल मतदाता 7.62 करोड़ है। 2002 से 2025 के दौरान बंगाल में मतदाताओं की संख्या में 66 प्रतिशत की असामान्य वृद्धि देखी गई है। आयोग एसआइआर के तहत मतदाता सूची में मृत मतदाताओं को चिन्हित करने पर विशेष रूप से जोर देगा।

एसआइआर का काम देशभर में दो चरणों में होगा पूरा, जल्द की जाएगी घोषणा

- महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में नगर निकाय चुनाव और अन्य कारणों से दूसरे चरण में होगा
- दोनों चरणों का काम अगले सात से आठ महीनों में पूरा करने का लक्ष्य

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआइआर) का काम अब देशभर में एक साथ नहीं, बल्कि दो चरणों में होगा। पहले चरण में यह उन राज्यों में होगा, जहां विधानसभा के चुनाव अगले साल यानी 2026 में होने हैं। इनमें तमिलनाडु, बंगाल, केरल, असम और पुडुचेरी शामिल होंगे। पहले चरण में इसके साथ कुछ और राज्यों में भी इसे कराया जा सकता है। जबकि, दूसरे चरण में महाराष्ट्र सहित उन राज्यों में इसे कराया जाएगा, जहां नगरीय निकाय चुनाव सहित मौसम आदि से जुड़ी चुनौती है। हालांकि, दोनों चरणों का एलान एक साथ ही होगा। जो हफ्तेभर में कभी भी हो सकता है।

एसआइआर के दोनों ही चरणों के बीच यह अंतर करीब चार महीने का होगा। वैसे भी आयोग ने जो संकेत दिए हैं, उनमें एक चरण को अधिकतम चार महीने में पूरा कर लिया जाएगा। आयोग से जुड़े उच्च पदस्थ सूत्रों की मानें तो जून 2026 तक देशभर में मतदाता सूची के एसआइआर का काम पूरा कर लिया जाएगा। आयोग ने इस बीच सभी राज्यों के साथ एसआइआर से जुड़ी तैयारियों को एक बार फिर परखा है। जिसमें बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं।

आयोग से जुड़े सूत्रों के अनुसार, बंगाल, तमिलनाडु सहित जिन पांच राज्यों में अगले साल चुनाव हैं, वहां एसआइआर के काम को फरवरी 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। चुनाव आयोग ने देशभर में मतदाता सूची के एसआइआर का एलान बिहार में एसआइआर कराने के एलान के साथ ही कर दिया था। देश के अधिकांश राज्यों में इससे पहले एसआइआर 2003 व 2004 में ही हुआ था। यानी 22 वर्षों के बाद यह फिर से देशभर में होने जा रहा है।

एक नजर में

जदयू ने 44 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की

पटना: जदयू ने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी। दोनों सूची में 37 प्रत्याशी पिछड़ा वर्ग से दिए हैं। अतिपिछड़ा वर्ग व सामान्य श्रेणी के प्रत्याशियों की संख्या 22-22 है। अनुसूचित जाति से 15, अल्पसंख्यक समाज से चार, अनुसूचित जनजाति से एक प्रत्याशी को टिकट मिला है। मालूम हो कि पार्टी ने बुधवार को 57 प्रत्याशियों की सूची जारी की थी। इस तरह जदयू ने सीट शेयरिंग के तहत अपने खाते में आई सभी 101 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। दूसरी सूची में 17 विधानसभा क्षेत्रों में जदयू ने अपने प्रत्याशी बदल दिए हैं। (राब्यू)

राजद के स्टार प्रचारकों की सूची में लालू परिवार से पांच

पटना: राजद के लिए इस बार करो या मरो की स्थिति है। ऐसे में उसने भी अपने 40 स्टार प्रचारक चुन-चुन कर तय किए हैं। इनमें कई नाम पुराने हैं, तो कुछ नए चेहरे भी। 2015 से उसके स्टार प्रचारकों में सम्मिलित रहे तेजप्रताप यादव का नाम इसमें नहीं होना स्वाभाविक है, क्योंकि वे नई पार्टी के कर्ता-धर्ता बन गए हैं। मीसा भारती और रोहिणी आचार्य को जोड़ते हुए इस सूची में लालू परिवार से पांच स्टार प्रचारक हैं। क्रम में शिवचंद्र राम का नाम लालू-राबड़ी के बाद तीसरे स्थान पर आना अनुसूचित जाति के वोटों को अपने पक्ष में करना है। तेजस्वी यादव पांचवें नंबर पर हैं और प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल उनके नीचे। (राब्यू)

महागठबंधन पर योगी का हमला, कहा- ये अब विकास बनाम बुर्के का नैरेटिव लाए हैं

उप्र के सीएम ने दानापुर की रैली में कहा- बिहार में अब अपहरण उद्योग नहीं चलता

जागरण टीम, पटना : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महागठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि ये अब विकास बनाम बुर्के का नैरेटिव लेकर आए हैं। जब बिहार विकास की चर्चा कर रहा है तो कांग्रेस-राजद बुर्के की बहस को बढ़ा रहे हैं। दुनिया में हर जगह मतदान के लिए पहचान व चेहरा दिखाना पड़ता है, लेकिन राजद-कांग्रेस फर्जी पोलिंग के लिए इसका विरोध कर रहे हैं। वह गुरुवार को पटना के दानापुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रामकृपाल यादव व सहरसा से डा. आलोक रंजन की आयोजित नामांकन सभा को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि जिस कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोंटा था, उसी की झोली में राजद ने खुद को गिरवी रख दिया है। वे जेपी के सपनों पर पानी फेर रहे हैं और लूट, भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए कांग्रेस की झोली में चले गए हैं। कांग्रेस-राजद के एजेंडे में गरीब कल्याण नहीं, परिवार कल्याण है। योगी माफिया व अपराधियों के खिलाफ भी खूब गरजे। कहा, अपहरण उद्योग में लिप्त राजद के पार्टनर की यूपी में दुर्गति कर दी गई है। जैसे यूपी में माफिया से जमीन वापस लेकर गरीबों का आवास बन रहा है, वैसा ही बिहार में भी होगा।

- भाजपा प्रत्याशी संजय गुप्ता के नामांकन के मौके पर मप्र के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी पहुंचे
- सम्राट चौधरी व कुमार प्रणय के नामांकन में पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

योगी आदित्यनाथ • फाइल फोटो

बिहार में डबल इंजन सरकार ही सर्वांगीण विकास की गारंटी: मोहन यादव

पटना के कुम्हरार विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी संजय गुप्ता के नामांकन के मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि बिहार में फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और बिहार में भी वही विकास माडल लागू होगा। एनडीए की डबल इंजन सरकार ही बिहार के सर्वांगीण विकास की गारंटी है। उन्होंने कहा कि जनता जानती है कि स्थिर और विकासमुखी सरकार कौन दे सकता है। नामांकन के दौरान कुम्हरार के विधायक अरुण कुमार सिन्हा ने टिकट कटने के बाद पार्टी के निर्णय को शिरोधार्य किया और नामांकन में न केवल भाजपा प्रत्याशी संजय गुप्ता के साथ रहे, बल्कि उनके प्रस्तावक भी बने।

'बुर्के वाली महिलाओं की पहचान का फैसला नया नहीं'

- चुनाव आयुक्त शेषन के समय से लागू है यह व्यवस्था
- सपा सहित कई राजनीतिक दल इस पर खड़े कर रहे सवाल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान बुर्के या फिर पर्दे में मतदान केंद्रों पर आने वाली महिलाओं की पहचान सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर आंगनबाड़ी सेविकाओं की तैनाती के चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल कर रहे राजनीतिक दलों को आयोग ने कड़ा जवाब दिया है। साथ ही कहा कि यह कोई नई व्यवस्था नहीं है बल्कि 1994 में टीएन शेषन के समय से लागू है। चुनाव आयोग इसका देश भर में सख्ती से पालन कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

आयोग ने इस दौरान चुनाव आयुक्त टीएन शेषन के कार्यकाल के दौरान बुर्के और पर्दे में रहने वाली महिलाओं की पहचान को लेकर 21 अक्टूबर, 1994 में जारी आदेश भी साझा किया है। इसमें साफ कहा है कि मतदान केंद्र में आने वाले ऐसी महिलाओं की पहचान सुनिश्चित करने और सहायता के लिए मतदान केंद्रों पर महिला अधिकारी की अनिवार्य रूप से तैनाती की जाए। आयोग ने यह स्थिति तब स्पष्ट की है जब सपा सहित कुछ राजनीतिक दलों की ओर से इस फैसले पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं।

गृह मंत्री शाह ने कहा- एनडीए विधानमंडल दल ही तय करेगा कौन होगा मुख्यमंत्री

गृहमंत्री अमित शाह • फाइल फोटो

- कहा- नीतीश इस देश के बड़े समाजवादी नेता, बिहार में उनके नेतृत्व में एनडीए लड़ रहा चुनाव
- पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की देर रात तक ली बैठक, चुनाव तैयारियों की समीक्षा की

राज्य ब्यूरो, जागरण, पटना : बिहार में विधानसभा चुनाव प्रचार के साथ ही एनडीए के चुनावी समीकरण को साधने गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को तीन दिवसीय बिहार दौरे पर पटना पहुंचे। पटना पहुंचने के उपरांत शाम में एक टीवी चैनल के फोरम में सम्मिलित हुए। शाह ने कार्यक्रम में नीतीश कुमार को चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनाने को लेकर पूछे गए प्रश्न पर कहा कि मैं कौन होता हूं, किसी को मुख्यमंत्री बनाने वाला। एनडीए में इतने सारे दल हैं। चुनाव उपरांत एनडीए विधानमंडल दल तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। शाह ने कहा कि भाजपा गठबंधन एवं उसके सहयोगियों का सम्मान करती है और अंतिम निर्णय चुनाव के परिणाम पर आधारित होगा।

उन्होंने स्पष्ट किया कि एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है। इस प्रश्न पर कि क्या कम सीटें आने पर भी नीतीश मुख्यमंत्री बनेंगे? शाह का उत्तर था- आज भी भाजपा की सीटें अधिक हैं। यह सच है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में कम सीटें आने के कारण नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनने से इन्कार कर दिया था। लेकिन, प्रधानमंत्री मोदी के आग्रह पर वे राजी हुए। उन्होंने नीतीश की प्रशंसा की। कहा कि वे देश के बड़े समाजवादी नेता हैं। वह कभी कांग्रेस में नहीं रहे। कांग्रेस के साथ उनका संश्रय अधिकतम ढाई साल का रहा। क्या बिहार में भाजपा की सरकार बनाने का सपना नहीं है? शाह ने कहा-मैं सपना नहीं देखता हूं। आराम से सोता हूं।

शाह ने भाजपा प्रदेश मुख्यालय में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों एवं चुनाव समिति की अलग-अलग बैठक ली। टिकट बंटवारे एवं सीट शेयरिंग के उपरांत भाजपा के साथ ही एनडीए में चल रही गतिविधियों से अवगत हुए।

स्टार प्रचारकों में पीएम मोदी समेत 40 नाम

राज्य ब्यूरो, जागरण • पटना: बिहार में विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए भाजपा ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची घोषित कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का नाम पांच शीर्ष स्टार प्रचारकों में शामिल है। शिवराज सिंह चौहान, बिहार के चुनाव प्रभारी व केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, गिरिराज सिंह एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस को दस शीर्ष स्टार प्रचारकों की सूची में रखा गया है। इसके अतिरिक्त असम के मुख्यमंत्री हिमंत विस्वा सरमा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के अतिरिक्त उप्र के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का नाम शीर्ष 15 स्टार प्रचारकों में है। कई वरिष्ठ नेताओं व केंद्रीय मंत्रियों के साथ भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह, सांसद रवि किशन एवं दिनेश लाल यादव निरहुआ का नाम भी स्टार प्रचारकों में है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी • फाइल फोटो

भाजपा ने 80 विधायकों में से 19 के टिकट काटे

रमण शुक्ला • जागरण

पटना : बिहार की 45 वर्षों की राजनीति में एनडीए में जदयू के साथ 101-101 सीटों की साझेदारी कर पहली बार बराबरी में पहुंची भाजपा ने अबकी बार बड़ा संदेश देने का प्रयास किया है। पार्टी ने संगठनात्मक मंथन एवं जमीनी फीडबैक के आधार पर अपने 19 विधायकों के टिकट काट दिए हैं। पार्टी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि प्रदर्शन एवं जन-स्वीकृति के आधार पर ही उम्मीदवार तय होंगे, चाहे वे कितने ही पुराने या प्रभावशाली नेता क्यों न हों।

भाजपा के जिन विधायकों के टिकट काटे हैं, उनमें कई ऐसे नाम भी शामिल हैं, जो लंबे समय से अपने क्षेत्र में सक्रिय थे, लेकिन जनता से उनका जुड़ाव कमजोर हो गया था। संगठन को मिली रिपोर्टों में इन सीटों पर एंटी-इनकंबेंसी का असर दिख रहा था। ऐसे में भाजपा ने चुनाव से पहले ही जोखिम उठाने की बजाय नए चेहरे उतारने का फैसला किया। पार्टी का मानना है कि युवा एवं सक्रिय उम्मीदवार जनता के बीच नया विश्वास जगा सकते हैं। भाजपा नेतृत्व का यह कदम मोदी व अमित शाह की उस नीति से मेल खाता है, जिसमें जीतने वाला उम्मीदवार ही टिकट पाएगा का फार्मूला लागू किया गया है। जिन विधायकों के टिकट काटे गए हैं, उनमें से कुछ ने नाराजगी भी जाहिर की है।

कुछ नेता निर्दलीय चुनाव लड़ने या अन्य दलों से संपर्क साधने की चर्चा में हैं। पार्टी ने संदेश दिया है कि पद, पहचान या पुराना जनाधार अब टिकाऊ नहीं, जन विश्वास ही सबसे बड़ा आधार होगा। भाजपा ने राजपूत समाज के 21, भूमिहार-16, अनुसूचित जाति/जनजाति-12, ब्राह्मण-11, वैश्य-13, अति पिछड़ा से 12 को उम्मीदवार बनाया है।

लोजपा (रा) की सूची में भाजपा से कई नाम

राज्य ब्यूरो, जागरण, पटना: लोजपा (रा) के सभी 29 उम्मीदवारों की सूची जारी हो गई। पार्टी के 14 प्रत्याशियों की सूची पहले जारी हुई थी। गुरुवार को 15 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई। इनमें छह उम्मीदवार भाजपा पृष्ठभूमि के हैं। चेनारी के कांग्रेस विधायक मुरारी गौतम भाजपा में शामिल हुए थे। उन्हें लोजपा (रा) ने चेनारी सुरक्षित क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है। बोचहा सुरक्षित क्षेत्र की पूर्व विधायक बेबी कुमारी भाजपा में थीं।

उपेंद्र को मिलेगी विप की एक सीट, रास में रहेंगे बरकरार

राज्य ब्यूरो, जागरण • पटना: एनडीए में अपनी हैसियत के अनुरूप सीटें न मिलने से राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा नाराज चल रहे थे। बंटवारे में मिली महुआ सीट छिने जाने के बाद उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। बात बढ़ती देख गृह मंत्री अमित शाह मैदान में उतरे और फिर चंद मिनटों में सबठीक हो गया। कुशवाहा मान गए। उन्हें विधान परिषद की एक सीट व दोबारा रास का सदस्य बनाने का आश्वासन मिल गया।

स्वयं कुशवाहा ने आधिकारिक रूप से बयान जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि उनकी पार्टी को विधान परिषद की एक सीट आवंटित होगी। उन्होंने अपने नेताओं को एनडीए उम्मीदवारों के नामांकन में शामिल होने पर लगी रोक हटा ली है।

सहनी को 15 सीटें मिल सकतीं, विप सीट की भी चर्चा

मुकेश सहनी • फाइल फोटो

- वीआइपी के साथ ही महागठबंधन के अन्य दल भी कुछ बोलने से कर रहे परहेज
- दावा- राहुल गांधी ने सहनी को किया फोन, पर तेजस्वी यादव अभी भी मौन

राज्य ब्यूरो, जागरण • पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन की उलटी गिनती के बीच विकासशील इंसान पार्टी (वीआइपी) प्रमुख मुकेश सहनी के बागी तेवर खुलकर सामने आने के बाद उन्हें मनाने का खेल गुरुवार को दिन भर जारी रहा। इस बीच वीआइपी की ओर से दावा किया गया कि राहुल गांधी ने स्वयं सहनी को फोन कर सीटों के लिए आश्वस्त किया है। सूत्रों के हवाले से दावे किए जा रहे हैं कि सहनी की नाराजगी के बाद महागठबंधन की ओर से उन्हें 15 सीटों पर चुनाव लड़ने का आफर मिला है।

विधान परिषद की एक सीट दिए जाने का आश्वासन भी दिया गया है। सूत्रों की माने तो वीआइपी संस्थापक मुकेश साहनी शुक्रवार को गौड़ाबौराम से अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। यह वही सीट है जिस पर पहले से राष्ट्रीय जनता दल ने अपना उम्मीदवार घोषित किया था। अब खबर है कि राजद अपना सिंबल वहां से वापस ले सकता है। सहनी चुनावी प्रक्रिया प्रारंभ होने के पूर्व से ही महागठबंधन के साथ लगातार सक्रिय रहे हैं, परंतु सीट बंटवारे में उनकी काफी अनदेखी की गई। राजद, कांग्रेस और वामदलों तक ने अपने उम्मीदवारों को सिंबल देकर नामांकन की हरी झंडी भी दे दी लेकिन महागठबंधन के प्रमुख सहयोगी वीआइपी की नाव मंझधार में फंसी थी। वीआइपी को कितनी सीटें मिलेंगी, यह तस्वीर साफ नहीं थी। जिसके बाद सहनी के सब्र का बांध टूट पड़ा।

सहनी ने प्रेस कांफ्रेंस बुला ली। इससे महागठबंधन खेमे में हड़कंप मच गई। पटना से लेकर दिल्ली तक से सहनी को मनाने का सिलसिला शुरू हुआ। कांफ्रेंस तीन बार टली और अंत में रद हो गई। सूत्रों ने बताया कि सहनी को 15 सीटें देने की बात सामने आई।

कांग्रेस की पहली सूची जारी, 48 नाम

राज्य ब्यूरो, जागरण • पटना : महागठबंधन में लगातार खींचतान के बाद आखिरकार पहले चरण का नामांकन समाप्त होने के ठीक कुछ घंटे पहले बिहार कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। सूची में 48 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। लगभग 12 विधायकों के टिकट काट नए चेहरों पर दांव लगाया गया है।

पार्टी ने कदवा से पार्टी के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान को उम्मीदवारी सौंपी है। मनिहारी सुरक्षित सीट से मनोहर प्रसाद सिंह को एक बार पार्टी ने फिर टिकट दिया है। कोढ़ा सुरक्षित सीट से पूनम पासवान पर फिर दांव लगाया गया है।

रिकार्डिंग में डीआइजी भुल्लर बिचौलिये से बोले- जितने भी दे रहा है पकड़ ले

जासं, चंडीगढ़: स्क्रैप कारोबारी को राहत देने के बदले रिश्वत मांगने के मामले में बिचौलिये कृष्णु और पंजाब पुलिस में डीआइजी हरचरण सिंह भुल्लर की एक काल रिकार्डिंग सीबीआइ के हाथ लगी है। इसमें डीआइजी भुल्लर बिचौलिये को कहते सुनाई दे रहे हैं कि जितने भी दे रहा है, साथ-साथ पकड़ ले, उसे कह दे कि वह आठ पूरे कर दे। रिकार्डिंग में हर माह रिश्वत मांगने जाने की भी बात सामने आई है। एक रिकार्डिंग में बिचौलिया कृष्णु शिकायतकर्ता से कह रहा है कि अगस्त के नहीं आए, सितंबर के नहीं आए। दोनों को शुक्रवार को सीबीआइ की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा।

...तो गृह विभाग से लेनी पड़ती अनुमति: सीबीआइ को राज्य में कार्रवाई करने के लिए गृह विभाग को बताना पड़ता है। विभाग की मंजूरी मिलने के बाद ही सीबीआइ कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि उसे शक था कि डीआइजी के खिलाफ शायद राज्य सरकार कार्रवाई की अनुमति न दे और कार्रवाई की सूचना लीक हो जाए। यही वजह थी कि डीआइजी को सीबीआइ ने कार्यालय बुलाकर पकड़ा।

भाजपा से जुड़ा है बत्ता का परिवार: शिकायतकर्ता आकाश बत्ता की पत्नी वंदना नगर कौंसिल गोबिंदगढ़ में पार्षद हैं। उन्होंने कांग्रेस से चुनाव जीता था, बाद में वह पति के साथ भाजपा में शामिल हो गईं। आकाश के पास अभी जिम्मेदारी नहीं है।

चंडीगढ़ के सेक्टर-40 स्थित डीआइजी भुल्लर, उनकी कोठी, बरामद सोने के आभूषण व करोड़ों की नकदी • इंटरनेट मीडिया

अन्य बरामदगी

40 लीटर विदेशी शराब, एक डबल बैरल बंदूक, एक पिस्टल, एक रिवाल्वर, एक एयरगन तथा गोलियां

केरल में हिजाब मुद्दे पर डीडीई रिपोर्ट के खिलाफ हाई कोर्ट जाएगा स्कूल

कोच्चि, प्रेट्र : पल्लुरुथी स्थित चर्च द्वारा संचालित पब्लिक स्कूल शिक्षा उप निदेशक (डीडीई) की उस रिपोर्ट के खिलाफ केरल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा, जिसमें संस्थान की ओर से कथित चूक का आरोप लगाया गया है। स्कूल में एक छात्रा के हिजाब पहनकर आने पर विवाद शुरू हुआ था।

सेंट रीटा पब्लिक स्कूल के अभिभावक-शिक्षक संघ के अध्यक्ष जोशी कैथावलप्पिल ने बताया कि डीडीई की रिपोर्ट बिना उचित जांच के प्रस्तुत की गई थी। कहा, "हमने रिपोर्ट के खिलाफ हाई कोर्ट जाने का फैसला किया है। यह स्कूल या पीटीए से ठीक से बात किए बिना तैयार की गई थी।" डीडीई की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि छात्रा को हिजाब पहनने के कारण स्कूल से बाहर निकाल दिया गया, जो उसके शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है।

तेलंगाना में आरक्षण पर हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका खारिज

नई दिल्ली, प्रेट्र: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तेलंगाना सरकार को एक झटका लगा है। सर्वोच्च अदालत ने तेलंगाना सरकार के हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इसमें स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण देने वाले सरकारी आदेश पर रोक लगा दी गई थी। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने कहा, "आप उसी आरक्षण के साथ चुनाव जारी रखें जो पहले से था।" तेलंगाना में कांग्रेस सरकार ने 26 सितंबर को स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए सरकारी आदेश जारी किया था।

महाविकास आघाड़ी में राज ठाकरे को शामिल करने पर सहज नहीं है कांग्रेस

ओमप्रकाश तिवारी • जागरण

मुंबई: महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों से पहले विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी में राज ठाकरे को शामिल किए जाने को लेकर कांग्रेस सहज महसूस नहीं कर रही है। उसे डर है कि राज ठाकरे के साथ जाने से उसे हिंदी भाषी राज्यों में तो नुकसान होगा ही, मुंबई में रहने वाले हिंदी भाषी भी उससे नाराज हो सकते हैं। राज ठाकरे अपनी हिंदी विरोधी नीति के लिए जाने जाते हैं। पिछले कुछ माह से उनकी पार्टी खुलकर मराठी न बोल पाने वालों पर आक्रामकता दिखा रही है। गैर मराठी भाषियों के साथ मारपीट की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। जबकि, इसी बीच शिवसेना (यूबीटी) के नेता उद्धव ठाकरे के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में उद्धव की पार्टी शिवसेना (यूबीटी) एवं राज की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) दोनों को करारी हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में उद्धव ठाकरे अपने चचेरे भाई राज को साथ लेकर स्थानीय निकाय चुनावों में उतरना चाहते हैं। उन्हें उम्मीद है कि दोनों भाइयों के साथ आने से आम मराठी भाषियों में उनके प्रति भरोसा बढ़ेगा और मराठियों के एकजुट वोट उन दोनों को मिलेंगे।

संवाददाता सम्मेलन के दौरान (बाएं से) मनसे प्रमुख राज ठाकरे, कांग्रेस नेता बालासाहेब थोरात व शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे • फाइल फोटो

लेकिन उद्धव की इस मंशा में एक बड़ी दिक्कत कांग्रेस बन रही है। कांग्रेस विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी (मविआ) का एक महत्वपूर्ण घटक है। मविआ में कांग्रेस के होने के कारण ही पिछले लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की पार्टी को मुसलमानों के वोट मिले। अब उद्धव राज को साथ लेकर मराठी मतों को तो एकजुट करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस को छोड़ना भी नहीं चाहते। लेकिन कांग्रेस राज को साथ लेने से कतरा रही है, क्योंकि मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई हिस्सों में हिंदी भाषी मतदाताओं की संख्या अच्छी-खासी है। उनमें जो भाजपा को पसंद नहीं करते, वे कांग्रेस के मतदाता भी हैं।

****

लोकमानस

loksatta@expressindia.com

दीर्घकाळ भेडसावणारा सापळा

‘**नवा ‘हिंदू**’ दर?’ हे संपादकीय (१६ ऑक्टोबर) वाचले. वस्तू आणि सेवा करातील कपातीमुळे सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेला खरेदीचा उत्साह ही आर्थिक चैतन्याची लक्षणे असली तरी त्या उत्साहाला टिकाऊ पाया नाही. अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा खरा पाया उत्पादन आणि कृषी क्षेत्राशी संबंधित आहे पण हक्काचा मतदार या क्षेत्रातून येत नसल्याने त्याकडे सर्वाधिक दुर्लक्ष झाले आहे. २०२२ पासून पहिल्या तिमाहीतील सरासरी अर्थ गती ९.९ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली होती आणि त्या वेगात कृषी क्षेत्राचा वाटा मर्यादितच राहिला. त्या काळात कृषी क्षेत्राचा सकल देशांतर्गत उत्पादनातील हिस्सा सुमारे १८ टक्क्यांवरून घटून १५.५ टक्क्यांपर्यंत आला आहे. वाढीचा दरही कमी झाला आहे. भारत सरकारच्या आकडेवारीनुसार कृषी क्षेत्राने गेल्या पाच वर्षांत सरासरी ४.१८ टक्क्यांची वाढ नोंदवली परंतु २०२३ङ्ग२४ मध्ये ही वाढ केवळ १.४ टक्के इतकीच राहिली. ही मंदी ग्रामीण मागणी कमी करत आहे, जी सेवा क्षेत्राच्या वाढीवर थेट परिणाम करते. अर्थव्यवस्था ‘उत्सवी उसळी’वर नव्हे तर ग्रामीण उत्पादन शक्तीवर उभी असते. म्हणून केवळ जीएसटी कपातीसारख्या तात्पुरत्या उपायांपेक्षा, कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक व संरचनात्मक सुधारणा या ठोस पायाभूत उपक्रमांची गरज आहे. अन्यथा ६.६ टक्क्यांचा हा नव्या ‘हिंदू विकास दराचा’ सापळा आपल्याला दीर्घकाळ भेडसावणार आहे.

■ **परेश बंग,** मूर्तिजापूर (अकोला)

आणखी किती काळ वाट पाहायची?

‘**नवा ‘हिंदू**’ दर?’ हे संपादकीय वाचले. सध्या देशात जो काही जीएसटी उत्सव सुरू आहे त्याकडे डोळस नजरेने पाहिल्यास प्रश्न पडतो, एखाद्या खंडप्राय देशाचे अर्थकारण बदलण्याची ताकद एखाद्या करात असू शकते? मुळात, पाच-सात लाख रुपयांचे वाहन घेणारे पाच- सहा टक्क्यांची करसवलत मिळताच वाहन खरेदीसाठी गर्दी करतील? अर्थव्यवस्था, उद्योग तेजीत आहेत, सणासुदीला लोकांच्या खिशात पैसा खुळखुळत आहे, असे दृश्य दिसते काय? याचेही उत्तर होकारार्थी नाही. शेतकरी कर्जाच्या, विक्रीदराच्या चरकात पिळून निघतोय, उद्योजक ग्राहकांच्या शोधात आहेत, तर तरुण नोकरीच्या शोधात. जीएसटीमधील त्रुटी लक्षात येऊन सुधारण्यास सात वर्षे जावी लागली. प्रत्यक्ष विकासदरवाढीस आणखी किती काळ वाट पाहावी लागेल कुणास ठाऊक.

■ **शैलेश पुरोहित,** मुलुंड (मुंबई)

‘बहिणीं’साठी निधी आहे, शिक्षणासाठी नाही

‘**हजारो शाळांमध्ये** असुविधांचे वर्ग’ हे वृत्त (लोकसत्ता- १६ ऑक्टोबर) वाचले. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने नुकताच ‘यूडायस प्लस २०२४-२५’ हा अहवाल जाहीर केला आहे. त्यात देशभरातील शाळा, त्यातील सुविधा, विद्यार्थी संख्या, शिक्षक संख्या, विद्यार्थी - शिक्षक गुणोत्तराबत आकडेवारी देण्यात आली आहे. तथापि राज्यातील २५ हजार ९५८ शाळांमध्ये अध्यापनासाठी संगणक सुविधा, ३० हजार १६६ शाळांमध्ये इंटरनेट सुविधा, ५ हजार ५६७ शाळांमध्ये वीजच नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तसेच ६ हजार ९६४ शाळांमध्ये मुलींचे, १० हजार १८९ शाळांमध्ये मुलांचे वापरायोग्य स्वच्छतागृह नसल्याचेही दिसून आले आहे. डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत आदी टाळीखाऊ योजनांची ही एकप्रकारे शोकांतिका म्हणावी लागेलच पण आजमितीला राज्यात तब्बल ८ हजार १५२ शाळा एकशिक्षकी आहेत हे वास्तव ज्या राज्यात देशातील पहिली शाळा स्थापन झाली अशा राज्यासाठी अधिक लज्जास्पद आहे. एकीकडे राज्यातील हजारो शाळांमध्ये असुविधांचे हे असे वर्ग तर दुसरीकडे कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा आर्थिक आणि प्रशासकीयदृष्ट्या परवडत नाहीत म्हणून त्यांना टाळे ठोकण्याच्या हालचाली राज्य सरकारच्या पातळीवर होताना दिसतात. सरकारकडे आमदार आजीवन पगार, लाडकी बहीण योजना, ज्येष्ठांसाठी तीर्थदर्शन, पंढरपूर वारी अनुदान योजना, भजनी मंडळांसाठी अनुदान, विमान प्रवासासाठी अनुदान, अनावश्यक महामार्ग आणि अव्यवहारी बुलेट ट्रेन, पुतळे-स्मारके यांसाठी निधी आहे; परंतु शाळांसाठी - आरोग्यासाठी निधी नाही. आरोग्य आणि शिक्षणासाठी राज्य दरवर्षी अनुक्रमे २७ हजार आणि सात हजार कोटी रुपयांची तरतूद करते तिथे राज्य सरकारला फक्त लाडकी बहीण योजनेसाठी दरवर्षी ४६ हजार कोटींची तरतूद करावी लागत आहे. सरकारला अत्यावश्यक आणि अनावश्यक यातील फरक कळेनासा झाला आहे.

■ **बाळकृष्ण शिंदे,** बिबवेवाडी (पुणे)

आयोगाने विश्वासार्हता जपावी

‘**सदोष याद्यांवर** निवडणूक नको!’ आणि ‘मतदार नोंदणीची माहिती कुणाकडे?’ ही वृत्ते (लोकसत्ता- १७ ऑक्टोबर) वाचली. राहुल गांधी निवडणूक आयोगाच्या कार्यप्रणालीवर वारंवार जाहीर टीका करून कामकाजाचे धिंडवडे काढत आहेत. राज्यघटनेच्या रक्षणाचे काम घटनात्मक संस्थांचे आहे. लोकशाहीत घटनात्मक अधिकार असलेल्या संस्थेकडून होणाऱ्या चुका शोधण्यासाठी सर्वसामान्य जनतेला अधिकार मिळतो. बिहार विधानसभा निवडणुकीआधी मतदारांविषयी संभ्रम निर्माण झाला होता. राज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर मोठ्या प्रमाणात आगपाखड झाली.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकी संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर निवडणुका घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. आयोगाला मतदार यादीची पुनर्रचना करून अंतिम मतदार यादी तयार करण्यासाठी अवधी मिळाला असता. मतदार यादीबाबत महापालिका प्रशासन, जिल्हा परिषद आणि आयोग यांच्यात समन्वय नसल्याने प्रमुख राजकीय पक्षांत मतदार यादीबाबत संभ्रम निर्माण झाला असेल तर आयोगाने मतदारांची फसवणूक होणार नाही याची काळजी घ्यावी व आपली विश्वासार्हता जपावी.

■ **ज्ञानेश्वर हेडाऊ,** हडपसर (पुणे)

राजकारणात पराकोटीचा दांभिकपणा

‘**राजकारणापेक्षा समाजमनावरील** सत्ता महत्त्वाची’ हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वक्तव्याचे वृत्त (लोकसत्ता- १६ ऑक्टोबर) वाचले. फडणवीस म्हणतात, राजकीय सत्ता येते आणि जाते, हे माझ्यापेक्षा जास्त कोणीही अनुभवले नाही. मात्र अलीकडे तर वेशांतर करून, पक्ष फोडून, अन्य पक्षांचे नाव, चिन्ह पळवून सत्ता संपादन केल्याचे आरोप होतात. यापैकी काही बाबींची तर त्यांचे मित्रपक्षच साक्ष देतात. अशा प्रकारे प्राप्त केलेली सत्ता समाजमनावरील सत्ता म्हणायची का? राजकारणातील पराकोटीचा दांभिकपणा राज्याला कोठे घेऊन जाणार आहे?

■ **श्रीकांत जाधव,** नाशिक

सिंचन घोटाळ्याचे पुढे काय झाले?

‘**ताई... दादा,** नाथाच कसे दिसतात?’ हा ‘उलटा चष्मा’ (१६ ऑक्टोबर) वाचला. जे आजवर अनेकांना पडले होते, ते प्रश्न त्यात विचारण्यात आले आहेत. ताई भाजपप्रमाणे ‘पारदर्शक’ कारभाराची अपेक्षा करतात म्हणूनच त्या पहारेकऱ्याची भूमिका बजावत असाव्यात. ताई २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी म्हणाल्या होत्या, मला गडकरींना पाडायचे आहे. त्यांनी आम आदमी पक्षाकडून गडकरींच्या विरोधात निवडणूक लढवली, पण त्या पराभूत झाल्या. ७० हजार कोटींचा सिंचन घोटाळा कोणी बाहेर काढला होता, त्या घोटाळ्याचे पुढे काय झाले? सिंचनामध्ये दादांना पवित्र करून महायुतीमध्ये घेण्याचे प्रयोजन काय, असा प्रश्न ताई मुख्यमंत्र्यांना विचारत नाहीत आणि त्याचा पाठपुरावाही करताना दिसत नाहीत. मध्यंतरी ताईंनी पक्ष काढण्याचा मनसुबा माध्यमांसमोर जाहीर केला होता. त्यांनी महानगरपालिका निवडणुका जाहीर होण्याआधीच पक्षाची स्थापना करून निष्कलंक, सुशिक्षित उमेदवार रिंगणात उतरवावेत आणि मतदारांना पारदर्शक व भ्रष्टाचारमुक्त कारभाराची हमी द्यावी.

■ **प्रवीण हिर्लेकर,** डोंगरी (मुंबई)

महापालिकांमध्ये प्रशासकांचा उच्छाद

‘**शहर विकासात** सोन्याच्या खाणी?’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि महापालिकांचे आयुक्त संबंधित पालकमंत्र्यांच्या मर्जीने नेमले जातात. पालकमंत्र्यांची मर्जी सांभाळली की सगळी कामे सोपी होतात. प्रशासकांच्या काळात राज्यातील सर्वच महापालिकांमध्ये जे गैरव्यवहार झाले त्यांची स्वतंत्र चौकशी झाली पाहिजे. एक-दोन अपवाद वगळता बहुतेक महापालिकांमध्ये प्रशासकांनी उच्छाद मांडला आहे. दरवर्षी आपले दालन आणि क्वार्टरवर कोट्यवधींचा खर्च हे अधिकारी करीत आहेत. काही प्रशासक तर घरातील साबणापासून किराणासुद्धा सरकारी पैशाने विकत घेत आहेत. या मनमानीला अंकुश लावला पाहिजे.

■ **धनंजय लांबे,** छत्रपती संभाजीनगर

डफावरचे हात!

कला बहरण्याच्या प्रेरणा काय असतात? व्यक्त होण्याची ऊर्मी. ती जेव्हा सहअनुभूतीच्या पातळीवर येते, तेव्हा समूहमन तयार होते. एके काळी त्यातून होणारी कृती स्वातंत्र्याची प्रेरणा ठरली. त्या बंडही करू शकतात, हे अपेक्षित असेल का शाहिरी परंपरेला? युवक महोत्सवात लोकपरंपरा सादर होते आहे पण लोकपरंपरेचं उद्दिष्ट थिजलं आहे का?

लोक-लौकिक

सुहास सरदेशमुख
suhas.sardeshmukh
@expressindia.com

साधासा शर्ट. शरीर प्रकृतीही तशी किरकोळ म्हणता येईल अशीच. उंचीही जेमतेमच. २३ - २४ वर्षे वयाचा तरुण हस्तांदोलन करत म्हणाला, ‘मी शाहीर शुभम केंद्रे.’ यातील शाहीर शब्दावरचा जोर त्याची ओळख अधोरेखित करणारा. घरात काका पखवाज वाजवायचे. त्यामुळे लहानपणापासून भजन, कीर्तन कानावर पडत शुभम मोठा झाला. संगीत विषय घेऊन पदवीचं शिक्षण घेतलं. ताल घरातील संस्काराचा भाग होता. पुढं लक्षात आलं की, आपल्याला संगीतामध्ये गती आहे. हळूहळू लोकगीतांचा अभ्यास वाढू लागला. महाविद्यालयीन दिवसांमध्ये युवा महोत्सव, राष्ट्र सेवा योजनांच्या शिबिरांमध्ये प्रबोधनपर गाणी म्हणणं वगैरे सारं काही चाललं होतं. पण या काळात लोकगीतांमध्ये होणारे बदल टिपायला हवेत, असं लक्षात आलं आणि या क्षेत्रात अभ्यास करण्याचा निर्णय त्याने घेतला. एका बाजूला हा असा संशोधनात्मक अभ्यास आणि दुसरीकडे त्याने शाहिरीचा मंच उभा केला. पोवाडे, भारुड, लोकगीतं सादर करू लागला. आता त्याच्या संचाला अनेक ठिकाणी मागणी असते. बऱ्यापैकी पैसे मिळत आहेत. शुभम यांचे गुरू आणि समव्यावसायिक अजिंक्य लिंगायत. चार-पाच वर्षांनी मोठा असेल. नुकत्याच झालेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीनिमित्त रायगड येथील कार्यक्रमात अजिंक्यचा पोवाडा अनेकांच्या मोबाइलवर ‘व्हायरल’ झाला होता. तुमान, अंगरखा, शिवरायांचा मावळाच वाटावा अशी टोपी. हातात डफ घेऊन तो जेव्हा छत्रपतींचे पोवड्यातून वर्णन करतो तेव्हा मराठी माणसाला स्फुरण चढल्याशिवाय राहत नाही.

अजिंक्य लिंगायत यांच्या घरी तुकडोजी महाराज यांच्या विचार प्रचाराची परंपरा. मराठी विषयात पदवीचं शिक्षण घेतलं आणि पुढे लक्षात आलं की, सामाजिक काम करायचं असेल तर तेही शिक्षण हवं. मग एमएसडब्लू केलं. आता शासनाच्या योजनांच्या प्रचार प्रसारापासून ते महापुरुषांची महती पुढच्या पिढीपर्यंत पोहचवण्याचं काम हा शाहीर करतो. तिसरी भाषा म्हणून हिंदी अनिवार्य करण्यासाठी समिती नेमल्यानंतर भाषाविषयक दृष्टिकोन सांगणारं एक कवन अजिंक्य सहज म्हणून गेला - ‘मिसळ झाली मुंबई रं दादा.. मिसळ झाली, कर्ता - कर्म सारं इंग्रजी दिसलं, क्रियापदापुरती मराठी असलं, सब मिक्सर बन गयी रं...’ संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ या ज्या शाहिरांनी पुढे नेली, त्यांचं स्मरण ठेवणारी एक पिढी आता नव्या वळणावर पोहचली आहे. स्वातंत्र्य चळवळीत योगदान देणारे, संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत लोकमानस घडविणाऱ्या शाहिरांचं स्मरण वगैरे तसं आता होत नाही. तरीही राज्यात फक्त शाहिरी करणारे दीड- दोन हजार तरुण असतील. यात मुलींचा सहभागही मोठा. यातील कोणी रसायनशास्त्र विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेणारं तर कोणी एखाद्या विषयात पीएचडी मिळविणारं. माध्यम हाताळणीचं तंत्रज्ञान सोपं झालं आणि प्रत्येक जिल्ह्यात परंपरा जपणाऱ्या शाहिरांची संख्या वाढली. मोठ्या शहरात आणि भोवताली प्रत्येक

जिल्ह्यात ४० - ५० जण काम करू लागले आहेत. याचं मूळ त्याच्या अर्थकारणात आहे. आता या कार्यक्रमाची बिदागी लाखाच्या घरात गेली आहे. काही वर्षांपूर्वी वक्तृत्व स्पर्धांच्या बक्षिसांमधून मिळणाऱ्या मानधनावर दैनंदिन खर्च भागवणाऱ्यांची एक पिढी होती. पण भाषणातील नावीन्य आता फारसं उरलं नाही. रीलच्या जमान्यात शिवराळ बोलणाऱ्यांची चलती आहे. राजकीय नेते आता कॅमेऱ्यासमोर थुंकूनही दाखवतात. उक्ती आणि कृतीत पडलेलं अंतर लक्षात घेता भाषण करणाऱ्यांची संख्या कमी झाली. त्यामुळे गर्दीला एका बाजूने वळवायचं असेल तर शाहीर बरे पडतात, हे आता नेत्यांना कळू लागलं आहे. उजव्या बाजूने हिंदुत्ववादी महापुरुष रंगवायचा की जाती-धर्माच्या पलीकडे जाऊन ती प्रतिमा बदलून सांगायची हेही शाहीर अगदी कमर्शिअली सहज करू लागले आहेत. पोवाड्यातून प्रबोधन करताना डावे - उजवे आणि ‘कमर्शिअल’ अशी विभागणी आता पूर्णत्वाकडे वेगाने जात आहे. भूमिका घेणारी मंडळी तशी हाताच्या बोटांवर मोजता येणारी.

शाहीर सिद्राम मुचाटे धुळ्याचे. शाहिरी जगले. एवढी की अनेकदा इंग्रजांनी त्यांना तुरुंगात टाकले. स्वतःच्या मुलीच्या मुत्यूनंतर भेटायला जाऊ शकले नाहीत. त्यांच्या पत्नीने मुलांचा सांभाळ केला. पुढे क्षयरोग होऊन त्यांचा मृत्यू झाला. तेव्हा अंत्यसंस्कारासाठीही वर्गणी काढावी लागली. धुळे, अमळनेर परिसरात त्यांचे कार्यक्रम गाजत होते. १९३०, १९४२ मध्ये त्यांना अटक करण्यात आली. पण शाहिरीतून क्षोभ उभा करण्याची ताकद होती. लिहिणे, सादर करणे यात मुचाटे यांचा हातखंडा होता म्हणे. आता कोणाच्या आठवणीतही नाहीत. संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत योगदान देणारे शाहीर अमर शेख यांना पोलीस नोटीस काढायचे महेबूब हुसेन शेख नावाने. पण पुढे भालजी पेंढारकरांनी त्यांचं नाव बदलून अमर केलं. १९५७ साली प्र. के. अत्रे, एस. एम. जोशी, कॉ. डांगे यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत योगदान देणाऱ्या शाहीर अमर शेख यांनी दिल्लीतील मोर्चात ‘जागा मराठा आमजमाना बदलेगा’ अशी शाहिरी दिल्लीत ऐकवली होती. सांगण्याची ऊर्मी आणि उद्देश याचा मिलाफ करणारी मंडळी तशी कमीच. पण एक काळ होता जेव्हा कोणी तरी भाजीविक्री करायचा, कोणी संगमरवरी दगडावर नाव लिहून द्यायचा, कोणी कोळशाच्या खाणीत काम करायचा, मुंबईत चिक्की विकून शाहिरी लिहून रात्री डफ हाती घेणारे शाहीर महाराष्ट्रभर होते. भीमशाहिरीतून अर्थविचार मांडणाऱ्या या शाहिराने चार हजारांहून अधिक काव्यरचना केल्या.

शाहीर कृष्णराव साबळे यांनी लिहिलेलं ‘गर्जा महाराष्ट्र माझा’ हे गीत आजही आपल्या ओठी येतं. असे प्रयोग आज होत नाहीत, असं नाही. नवं प्रारूप, नवी मांडणी करणारे संभाजी भगत यांच्यासारखे शाहीर तसे कमीच. मांडणीतील प्रामाणिकपणा सादरीकरणात आला की कडुबाई खरात यांच्यासारखी बाबासाहेबांवर कवन करणारी महिला झपकन प्रकाशझोतात येऊन जाते. गुणवर्णनातील प्रमाणिकपणा जसाजसा झिरपत जातो तसतसं सादरीकरणाची मजा वाढते. स्वातंत्र्य चळवळीत आणि पुढे संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत ती अधिक होती. आता लोककलांच्या अभ्यासक्रमांची आणि त्याला प्रवेश घेणाऱ्यांची संख्या वाढते आहे.

पोवाडा म्हणजे काय? - वीरांच्या पराक्रमाचे आणि विद्वानांच्या बुद्धिमत्तेचे, सामर्थ्याचे, गुण आणि कौशल्याचे काव्यात्मक वर्णन ही महाराष्ट्र शब्दकोशातील व्याख्या. प्र अधिक वद् म्हणजे स्तुती असा या शब्दाच्या व्युत्पत्तीचा स्रोत. चांगल्या कामाची स्तुती करण्याचे प्रकार अगदी वैदिक काळापासून सुरू आहेत. गाथा यातून पुढे सुरू झाल्या. महापुरुषांच्या आयुष्यातले महत्त्वाचे प्रसंग, दानशूरता, आदींवर अनेक पोवाडे रचले गेले. इ.स. १०व्या शतकापासून हिंदीत किंवा तत्सम भाषांत अशा गीतांना ‘रासो’ असे म्हटले जात. पृथ्वीराजांचे रासो काव्य म्हणजे त्यांच्यावरचा पोवाडाच. यादव काळात भाट बिरुदगायन करत. पूर्वीच्या काळी पोवाडे रचणे आणि ते सदरेवर म्हणून दाखवणे हे काम गोंधळी करत. पुढे पेशवाईत तमाशाचे स्वतंत्र फड निघाले. त्यातील अनेकांनी मग पुन्हा पोवाडे रचणं सुरू केलं. पोवाड्यांची रचना आणि भाषा तशी ओबडधोबडच. त्यात वीररस ठासून भरलेला. वीर पुरुषांच्या लढाया आणि राजकीय घटना घडामोडींवर रचलेलं काव्य असल्याने एका अर्थाने जेत्याची स्तुती असे या कवनाचे स्वरूप. शिवाजी महाराज ते शाहू महाराज यांच्या कालावधीमध्ये केवळ सात पोवाडे होते. पेशव्यांच्या काळात ही संख्या १५० होती. अफझलखानाचा वध, तानाजी आणि बाजी पासलकर हे तीनच पोवाडे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातील होते. १८१८ मध्ये पेशवाई बुडाली. स्वराज्य गेल्यानंतरची हळहळ व्यक्त करून झाल्यावर इंग्रजी अमलाची छाप जाणवू लागली. इंग्रजी शिस्तीची भुरळ पेशवाईतील प्रभाकर आणि परशुराम या दोन शाहिरांना पडली. त्यांनी चरितार्थ चालविण्यासाठी लुंग्यासुंग्यांवर पोवाडे रचले. तरीही शाहिरांच्या रचना तशा परप्रेरित असतात. आत्मनिष्ठ काव्याचे वैशिष्ट्य पोवाड्यात फारसे डोकावत नाही. समकालीनांच्या भावनांशी समरस होऊन शाहिरांनी विषय मांडल्याने तत्कालीन मराठी जीवनाचे चित्र त्यातून मनात चितारता येऊ शकते. वि. का. राजवाडेंसारखे इतिहासतज्ज्ञ बखरीपेक्षा प्रमाण पोवाड्याच्या रचनांना वरचा दर्जा देत होते.

पोवाडा, फटका, ओवी, गोंधळ, छक्कड, लावणी असे काव्य आणि गद्य दोन्ही प्रकार हाताळणाऱ्या शाहिरांची मुख्य प्रेरणा स्वातंत्र्य ही होती. प्रबोधन कशाचे करायचे, शाहिरी का मांडायची याची जाण नसानसांत भिनली होती. भोवताल वर्णन करण्याची अजब हातोटी होती. तेव्हा शाहिरीला इंग्रजरूपी खलनायक होता. पुढे संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत शाहीर अण्णा भाऊ साठे, अमर शेख यांच्यासह अनेकांनी गावोगावी प्रबोधन केले. तेव्हा ‘कितीही कोंबडे झाका सरकारा, संयुक्त महाराष्ट्र होणार’ असे ठणकावून सांगितले जात होते. मराठवाड्यातही निमाजाच्या विरोधात आवाज उंचावणारी प्रभाकरराव वाईकर यांच्यासारखी मंडळी होती.

प्रबोधनाची चळवळ करणाऱ्या आणि आपली भावना कधी तरलपणे तर कधी थेट प्रश्नाच्या रूपाने मांडणाऱ्यांची मोठी परंपरा महाराष्ट्रात होती ती आजही आहे. शाहू -फुले- आंबेडकर यांच्या विचारांबरोबरच छत्रपती शिवाजी महाराजांवरील पोवाडे आणि रचना ऐकल्या जातात. पण नव्या जमान्यात समाज माध्यमांच्या नव्या बाजारू व्यवस्थेतून समूहमन निर्माण होण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे शाहीर वाढले तरी ते केवळ ‘रिल्स’पर्यंत राहतील. फार तर एखादा तिकीट लावून लोकपरंपरांचा कार्यक्रमही होईल, पण ते त्या पुढे जाणार नाहीत, याची काळजी बाजार घेईलच.

कुतूहल

मलेरियाला नमवणारा रोनाल्ड रॉस

अठराव्या शतकाच्या उत्तरार्धात जगभरात मलेरियाने थैमान घातले होते. अशा परिस्थितीत रोनाल्ड रॉस यांनी डासांच्या माध्यमातून मलेरियाचा प्रसार कसा होतो, हे शोधून काढून मलेरियावरील उपचारांचा मार्ग मोकळा केला.

रोनाल्ड रॉस यांचा जन्म १३ मे १८५७ रोजी भारतात उत्तराखंडातील अल्मोरा येथे झाला. त्यांचे उच्च शिक्षण इंग्लंड येथील रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स येथे झाले. तिथे त्यांनी जिवाणूशास्त्र आणि सार्वजनिक आरोग्य या विषयातील पदवी संपादन केली. भारतात उटीजवळील सिंगूरघाट येथे वैद्यकीय सेवेत कार्यरत असताना त्यांना मलेरिया झाला व त्यांच्या संशोधनाला चालना मिळाली.

सर रोनाल्ड रॉस इन्स्टिट्युट, हैद्राबाद येथील प्रांगणातील रोनॉल्ड रॉस यांचा पुतळा

मलेरियाच्या संशोधनासाठी लागणारे डास पकडण्यासाठी त्यांना किशोरी मोहन बंडोपाध्याय या भारतीय शास्त्रज्ञाची मदत झाली. रोनाल्ड रॉस यांना असे आढळून आले की, करड्या रंगाच्या डासांनी चावल्यामुळे कबुतर, चिमणी अशा पक्ष्यांना मलेरिया होतो, तर तपकिरी रंगाच्या ठिपकेदार पंख असलेल्या डासांमुळे माणसामध्ये मलेरिया होतो, मात्र पक्ष्यांना होत नाही. त्यांनी काही निरोगी चिमण्या एका मच्छरदाणीच्या जाळीत ठेवल्या. या चिमण्यांना डास न चावल्यामुळे मलेरियाची लागण झाली नाही. जुलै १८९८मध्ये त्यांनी डासांचे डोके, प्रामुख्याने मानेचा भाग सूक्ष्मदर्शकाखाली बारकाईने बघितला आणि त्यांना तेथे धाग्यासारखे अनेक परजीवी दिसले. याचेच पुढे स्पोरोझोइटस असे नामकरण केले गेले. मानेच्या वरच्या भागात एका लाळेच्या ग्रंथीत ते सामावलेले होते.

८ जुलै १८९८ रोजी त्यांनी असा सिद्धांत मांडला की, मलेरियाचे परजीवी जंतू हे डासाने पक्ष्याला चावा घेतल्यावर सोंडेतून लाळेवाटे त्या पक्ष्याच्या रक्तात प्रवेश करतात. मलेरियाच्या परजीवी जंतूचे दुहेरी जीवनचक्र (अर्धे डासाच्या रक्तात आणि अर्धे पक्षी/मानवाच्या रक्तात) त्यांनी सर्वप्रथम विशद केले. तेव्हापासून मच्छरदाणीचा वापर सुरू झाला.

१६ ऑगस्ट १८९८ रोजी हुसेन खान या मलेरिया झालेल्या रुग्णाचे रक्त त्यांनी डासांना शोषू दिले. २४ तासांनंतर त्यातील एका डासाच्या शरीर विच्छेदनात काहीच आढळून आले नाही. परंतु पुढे तीन दिवसांनी डासाच्या पोटात १२ मायक्रॉन व्यासाच्या गोलाकार पेशी त्यांना आढळल्या. त्या पेशींचे त्यांनी निरीक्षण केले. त्यांना पुढे ‘उसाइट्स’ असे संबोधले गेले.

रोनाल्ड रॉस यांनी ‘प्रिव्हेन्शन ऑफ मलेरिया’ हा ग्रंथ लिहून जनजागृती केली. यांच्या मलेरियावरील महत्त्वपूर्ण संशोधनाबद्दल त्यांना १९०२ सालचे शरीरशास्त्र व वैद्यक या विभागातले नोबेल पारितोषिक प्रदान करण्यात आले. १९११ साली त्यांना ‘सर’ या किताबाने गौरविण्यात आले. १६ सप्टेंबर १९३२ रोजी त्यांचे निधन झाले.

– डॉ. सुहास कुलकर्णी
मराठी विज्ञान परिषद
ईमेल : office@mavipa.org
संकेतस्थळ : www.mavipa.org

व्यक्तिवेध

मुंबईजवळ ठाण्यात राहणाऱ्या एका पारशी न्यायाधीशाची मुलगी वयाच्या सातव्या वर्षी - १९४७ साली- नृत्यशिक्षण घेण्याचा आग्रह धरते, सुखवस्तू घरात तिचा हट्ट मान्यही होतो आणि कथ्थक, भरतनाट्यम आणि मणिपुरी या तीन शैलींचे रीतसर शिक्षण घेतल्यावर, वयाच्या १५ व्या वर्षी ती नवा हट्ट धरते- स्वतःचे नृत्यपथक चालवेन म्हणते! तो काळ उदयशंकर यांचे नृत्यपथक खरोखरच जागतिक कीर्तीचे झालेले असण्याचा. ‘मी एकटी माझ्या पथकासह नाचणार, सिनेमानट्या नटांशी करतात तसे प्रेमाचे चाळे नाही करणार’ अशी विनवणी वडील अनिच्छेनेच ऐकतात. पण हा प्रवास इथवरच थांबणारा ठरत नाही.

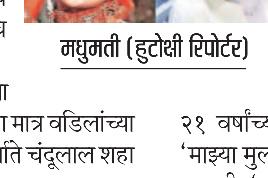

मधुमती (हुटोक्षी रिपोर्टर)

हिंदी चित्रपटसृष्टीतून १९५० च्या दशकाअखेर बोलावणे आले, तेव्हा मात्र वडिलांच्या इच्छेविरुद्ध त्या वागल्या आणि निर्माते चंदूलाल शहा यांच्या ‘जमीन के तारे’ या चित्रपटात त्या झळकल्या- याच चित्रपटाच्या श्रेयनामावलीत दिलेल्या ‘मधुमती’ या टोपणनावाने पुढेही वावरू लागल्या. ‘झनक झनक तोरी बाजे पायलिया’, ‘तेरे नैना तलाश करें जिसे’ किंवा ‘ओ मेरी प्राणसजनी चंपावती आ जा’ या (आज पन्नाशीपार असलेल्यांना सहज आठवू शकणाऱ्या) गाण्यांसह ६० हून अधिक चित्रपटांत त्यांनी नृत्ये केली. पुढे नर्तक पतीसह काढलेल्या नृत्यशिक्षण वर्गांचे काम सांभाळले आणि गोविंदा, चंकी पाण्डे, फराह, तब्बू, अक्षय कुमार या अभिनेत्यांच्या नृत्यगुणांना पैलू पाडले!

वयाच्या ८७ व्या वर्षी, १५ ऑक्टोबर रोजी मधुमती यांचे निधन झाले, त्याआधीच्या काही वर्षांत नव्यानेच बोकाळलेल्या यूट्यूब वाहिन्यांना त्यांनी दिलेल्या मुलाखतींतून विशेषतः त्यांच्या विवाहाचे आणि नंतरच्या आयुष्याचे तपशील उलगडले होते. त्यांचे पती दीपक मनोहर हे मूळचे हरियाणाचे भांगडा नर्तक. अभिनेते सुनील दत्त यांच्या सांगण्यावरून दीपक मुंबईत आले. ‘नया दौर’ (१९५७) मधल्या भांगडा नृत्यात दीपक चमकले आणि साधारण त्याच सुमारास हुटोक्षी यांना भेटले. तेव्हा दीपक विवाहित होते, त्यांची पत्नी नर्तक होती आणि त्यांना चार मुलेही होती. या कुटुंबाशी हुटोक्षी यांचा स्नेह होता. सीमेवरल्या जवानांसाठी १९६२ च्या भारत-चीन युद्धावेळी सुनील दत्त व नर्गीस यांनी स्थापलेले ‘अजंठा कलापथक’ या साऱ्या नर्तकांसह दौऱ्यावर असतानाच दीपक यांच्या पत्नीचे निधन झाले. तेव्हा त्यांच्या मुलांचा सांभाळ करणाऱ्या हुटोक्षींना पाहून नर्गिस यांनी सुचवले- दीपकशी तू लग्न का नाही करत? हुटोक्षी तेव्हा २१ वर्षांच्या. त्यात दीपक यांनी अटच घातली- ‘माझ्या मुलांना सावत्र भावंडे नकोत!’ तीही त्यांनी पाळली. ‘चंपावती आ जा’सारख्या एखाद्या नृत्यात दोघेही आहेत, पण एरवी एकमेकांच्या व्यावसायिक प्रगतीआड न येता हे दाम्पत्य चित्रपट स्वीकारत राहिले. पुढे दीपक यांनी स्वतःची नृत्यशाळा सुरू केली, तिथेही त्या वर्ग घेत. या दाम्पत्याने चाळिशी ओलांडली तोवर या वर्गांतली मुले मधुमती यांना ‘गुरुमाँ’ अशीच हाक मारत. अखेर १९७६ च्या ‘चरस’ या चित्रपटानंतर मधुमती यांनी चित्रपटसंन्यास जाहीर केला आणि ‘अमर अकबर अँथनी’तल्या पाहुण्या भूमिकेचा अपवाद वगळता तो पाळला. चित्रपटसृष्टीत १९५१ पासून प्रवेश केलेल्या हेलन यांचे नाव तोवर कमी कपड्यातली (बहुतेकदा ‘कॅबरे’) नृत्ये करण्यासाठी प्रसिद्ध असले तरी, कमी कपड्यांतल्या नृत्यांमध्येही भारतीय शास्त्रीय नृत्यपद्धतींचा बाज यशस्वीपणे आणण्याचे श्रेय मधुमती यांचेच!

तर्कतीर्थ विचार

आम्ही चालवू हा पुढे वारसा...

तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांनी आपल्या कार्य-कर्तृत्वाने महाराष्ट्रातील साहित्य, भाषा, संस्कृती, ग्रंथव्यवहार, प्रकाशन, वृत्तपत्र / नियतकालिक संचालन-संपादन, कोशनिर्मिती इत्यादी क्षेत्रांतील विविध संस्थांचे पालकत्व सांभाळले. त्या सर्व संस्थांच्या प्रतिकूल काळात तर्कतीर्थांनी आपली राजकीय आणि सामाजिक पत वापरून त्या संस्थांना विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात ऊर्जितावस्था प्राप्त करून दिली. प्राज्ञपाठशाळा मंडळ, महाराष्ट्र साहित्य परिषद, मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालय, सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ सोशल चेंज, इंडियन रेनासान्स इन्स्टिट्यूट, धर्मकोश मंडळ, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ ही त्यातील काही नावे. म्हणूनच कदाचित २७ मे, १९९४ला तर्कतीर्थांचे निधन झाले, तेव्हा सर्व वृत्तपत्रे, नियतकालिके, संस्था यांनी श्रद्धांजली लेख, ठराव, पत्रे पाठवून, लिहून त्यांच्या योगदानाप्रति कृतज्ञता व्यक्त केली.

यात एक दीर्घ टिपण माझ्या हाती लागले. त्याचे हस्ताक्षर, मजकूर, विचार, शैली पाहता ते प्रा. मे. पुं. रेगे यांचे असावे, असा कयास करण्यात भरपूर आधार उपलब्ध होतात. हे टिपण अर्थातच आदरांजली वाहणारे आहे. ते ‘नवभारत’चे संपादकीय, प्राज्ञपाठशाळा मंडळाचा शोकप्रस्ताव वा श्रद्धांजली लेख ठरावा, असा हा मजकूर आहे. त्यात लेखक निर्देश नाही.

प्रा. मे. पुं. रेगे तर्कतीर्थांना ‘शास्त्रीजी’ संबोधत. या टिपणात या शब्दाचा अनेकदा वापर आहे. यात ते म्हणतात, ‘‘शास्त्रीजी खऱ्या अर्थाने भारतीय आणि आधुनिक भारतीय प्रबोधनाचे चालते-बोलते आणि कर्ते प्रतीक होते. त्यांच्याच शब्दात सांगायचे, तर ‘‘मी आधुनिक भारताच्या व महाराष्ट्राच्या सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजकीय आंदोलनाशी एकरूप झालो होतो.’’ जीवनाचे त्यांनी कप्पे पाडले नव्हते, त्याकडे पाहण्याचा त्यांचा समग्रलक्ष्यी (इंटिग्रेटेड) दृष्टिकोन होता. मानवेंद्रनाथ रॉय यांच्याबरोबर ‘इंडियन रेनासान्स इन्स्टिट्यूट’ सन १९४६ला स्थापन करण्यात त्यांचा पुढाकार होता. तर्कतीर्थ या संस्थेचे संस्थापक विश्वस्त होते. या संस्थेच्या उद्देशांचा आयुष्यभर पाठपुरावा करणारे त्यांचे व्यक्तिमत्त्व मशालीसारखे (टॉर्च बेअरर) होते.

ऐतिहासिक व शास्त्रीय दृष्टिकोनातून अभ्यास करीत त्यांनी ‘वैदिक संस्कृतीचा विकास’ हा अमोल ग्रंथ लिहिला. तो इंग्रजीत लिहिला असता, तर जगातील विद्वानांच्या पंक्तीत ते बसले असते. बनारस, कलकत्त्यातील उच्च शिक्षणाने शास्त्रीजींमध्ये शास्त्रीय दृष्टिकोन दृढ होण्यास मदत झाली. शास्त्रीजींनी तत्त्वज्ञानाबरोबर झपाट्याने वाढणाऱ्या वैज्ञानिक ज्ञानावर नजर ठेवली. ‘‘विज्ञान व तंत्रज्ञान यांची इतकी वाढ होऊनही बहुजन समाज बंधनात का राहिला,’’ याचे शास्त्रीजी उत्तर शोधत राहिले. आजचा भारतीय समाज धर्मसत्तेच्या आहारी जात आहे, याची जाणीव त्यांना होती.

शास्त्रीजी हे एक परिपूर्ण मानव होते. राजकारण, समाजकारण, साहित्य, चित्रकला आणि संगीत यांचे रसग्रहण कसे करावे, हे ते शिकले. त्यांची वृत्ती आनंदी जीवन उपभोगण्याची होती. वैदिक ऋषींप्रमाणे त्यांना हे जग सुंदर दिसे. त्यांना हसतमुख, सुजाण, कर्तव्यदक्ष पत्नी सतीकाकूंच्या रूपात लाभली. जगातील रम्य जीवन त्यांनी स्वर्गप्राप्तीचे साधन मानले. आपण ज्या जगात राहतो, तेच शक्य कोटीतील सर्वांत चांगले जीवन त्यांनी मानले.

त्यांनी आपल्यासाठी भरपूर विचारधन ठेवले आहे. याचे सर्व जनतेत वितरण होणे आज जरुरीचे आहे. हे कार्य आपणा सर्वांचे आहे. ज्यांना शक्य आहे, त्यांनी यात भर घालणेही आवश्यक आहे. शास्त्रीजींनी दिलेला हा वारसा आपण पुढे चालविला पाहिजे, ही खरी त्यांना आदरांजली होईल.

वर उल्लेखित टिपणाचा हा सारसंक्षेप म्हणजे हे त्यांच्या एकेकाळच्या विश्वासू सहकाऱ्याने व नंतर वारस, उत्तराधिकारी बनून कार्य केलेल्या तत्त्वज्ञान्याचे तर्कतीर्थसंबंधी विचार होत. तर्कतीर्थांच्या जीवन, कार्य नि विचारांचे हे समालोचन होय. आज तर्कतीर्थांच्या शतकोत्तर रौप्यमहोत्सवी जयंती वर्षी हे वाचणे नि त्याप्रमाणे कृती करणे, हे आपणा सर्वांचे कर्तव्य ठरते. कवी जगदीश खेबूडकरांच्या कवितेतील प्रस्तुत लेख शीर्षकाची ओळ या ज्ञानमहर्षीच्या कल्पवृक्षाखाली आपणास समृद्ध करीत वर्तमान अंधारात एक कवडसा दाखविते. ‘जरी कोणी दुष्ट करू शासन, गुणी सज्जनांचे करू पालन’ या काव्यातील गुरुमंत्रच वर्तमानावर उतारा आहे.

– डॉ. सुनीलकुमार लवटे
drsklawate@gmail.com

More Newspaper and Magazines Telegram Channel join Search https://t.me/Magazines_8890050582 (@Magazines_8890050582)

खैबर खिंडीतला खेळ...

सामरिक व व्यापारी गरजांतून तालिबानशी जुळवून घेण्याच्या नीतीत सावधपणा हवा.

जागतिक राजकारणाच्या पटलावर ज्या झपाट्याने नवे मैत्रीबंध जुळून येत आहेत आणि जुने कोलमडून पडत आहेत, ते पाहता आज नेमके मित्र कोणास मानावे नि शत्रू कोणास समजावे हेच कळेनासे झाले आहे. ज्या अमेरिकेशी संबंध दृढ करण्यासाठी भारताने गेली जवळपास २५ वर्षे प्रयत्न केले नि त्यास अमेरिकेकडूनही प्रतिसाद पुरेपूर मिळाला, त्या अमेरिकेने आज भारताचा शत्रू क्रमांक एक असलेल्या पाकिस्तानशी चुंबाचुंबी आरंभली. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे शत्रूपेक्षा मित्रांचाच छळ करण्यासाठी प्रसिद्ध. त्यांना सौद्यांमध्ये रस आणि प्रक्रियेविषयी तिटकारा. त्यामुळे लोकशाही मार्ग आचरणाऱ्या भारतापेक्षा हुकूमशाही वाटेने जाणारा पाकिस्तान त्यांना अधिक भावतो हे स्वाभाविकच. पण पाच वर्षांपूर्वी सीमा मुद्द्यावरून भारताशी जुने भांडण उकरून काढणाऱ्या चीनला गतवर्षीपासून भारताविषयी अचानक ममत्व वाटू लागले. ट्रम्पयुगात अमेरिकारूपी बेभरवशाच्या शत्रूपेक्षा भारतासारखा भरवशाचा प्रतिस्पर्धी बरा ही चीनची आजची भूमिका. या उलथापालथीत विचित्र संबंधांचा आणखी एक त्रिकोण मूर्तरूप होऊ लागला असून त्याचीही दखल घेणे भाग पडते. अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान यांच्यात गेल्या काही दिवसांपासून धुमश्चक्री सुरू झाली असून ही कटुता मिटण्याची चिन्हे नाहीत. तशात अफगाणिस्तानातील तालिबान राजवटीने भारतासमोर दोस्तीचा हात पुढे केला नि आपण त्यास सकारात्मक प्रतिसाद दिल्यामुळे तिन्ही देशांतील परस्परसंबंधांवर परिणाम संभवतो. तालिबान २.० ला भारताने मान्यता दिलेली नाही. तरी काबूलमधील केंद्राचे रूपांतर दूतावासात करण्यास आपण राजी झालो आहोत. हे जरा गमतीशीरच, पण सामरिक आणि राजकीय अपरिहार्यता कुठवर जाऊ शकते हे दर्शवणारे. अफगाणिस्तान- पाकिस्तान दुश्मनी ताजी असताना, भारत आणि तालिबानशासित अफगाणिस्तानमध्ये दोस्ताना निर्माण होणे या घटनांचा परस्परांशी संबंध नाही असे म्हणता येत नाही. तरीदेखील शत्रूचा शत्रू म्हणून तालिबानला जवळ करणे यात व्यापारी, सामरिक आणि राजनैतिक शहाणपण किती आणि अगतिकता किती, याची मीमांसा यानिमित्ताने आवश्यक.

जगात तालिबानला अधिकृत मान्यता देणारा रशिया हा एकमेव देश आहे. या राजवटीचे अनेक देशांशी संवाद संबंध प्रस्थापित झाले आहेत. परंतु या देशांमध्ये सर्वाधिक लक्षणीय देश म्हणजे भारत. तालिबान १.० आणि तालिबान २.० या दोन्ही राजवटींनी अफगाणिस्तानातील जी सरकारे उलथवली, त्या दोहोंशी भारताचे घनिष्ठ संबंध होते. तालिबान १.० या राजवटीशी भारताने कधीही जुळवून घेतले नाही. ती राजवटही भारताची गणना कट्टर शत्रूंमध्येच करत असे. तालिबानच्या त्या राजवटीने काश्मीरमधील पाकपुरस्कृत फुटीरतावाद, दहशतवादाला जाहीर पाठिंबा दिला होता. तालिबानच्या विरोधात अफगाणिस्तानमध्ये लढलेल्या नॉर्दर्न अलायन्स या टोळीवाल्यांच्या आघाडीला भारताने सक्रिय पाठिंबा दिला होता. काबूलमधील भारतीय दूतावासावर २००९ मध्ये आणि हेरातमधील भारतीय वकिलातीवर २०१४ मध्ये झालेल्या हल्ल्यांमागे तालिबानी हस्तक होते. सबब, २०२१ मध्ये पुन्हा तालिबानच अफगाणिस्तानचे सत्ताधीश झाले, त्या वेळी त्यांच्याशी सुरुवातीपासून आपण अंतर राखून होतो हे अपेक्षितच होते. परंतु मागील खेपेप्रमाणे ही तालिबानी राजवट पाकिस्तानचे मांडलिकत्व पत्करण्यास तयार नाही याची चाहूल सुरुवातीपासूनच लागत होती. तालिबानने ऑगस्ट २०२१ मध्ये काबूलचा कब्जा घेतला, त्या वेळी पाकिस्तानने लगेच तेथे राजनैतिक आणि लष्करी दूत धाडले. जणू नवीन व्यवस्थेवर पाकिस्तानचा वचक आणि वर्चस्व असावे. ही बाब तालिबानी नेतृत्वाला खटकली आणि त्यातून निर्माण झालेली कटुता कधीच शमली नाही. याउलट तालिबान २.० राजवटीने भारताशी तितकी कटुता बाळगली नाही. भारताने २०२२ मध्ये काबूलमध्ये तांत्रिक कचेरीच्या नावाखाली संपर्क व्यवस्था उभी केली. अफगाणिस्तानमध्ये मानवतावादी मदत भारताकडून जात होती. कोविडकाळात आणि अगदी अलीकडे ऑगस्टमध्ये त्या देशात झालेल्या भीषण भूकंपाच्या वेळी ही मदत अफगाणिस्तानातील कित्येकांची जीवनवाहिनी ठरली होती. क्रिकेट, बॉलीवूड किंवा योगा-सॉफ्टवेअर वगैरेंना भारताची सुप्तशक्ती अर्थात सॉफ्ट पॉवर मानणाऱ्यांनी या खऱ्या शक्तीची म्हणावी तशी दखल कधीच घेतली नाही.

> **शहाणपण किती आणि अगतिकता किती, याचे मोजमाप करूनच प्रत्येक पाऊल उचलावे लागेल...**

पण ही वाट निसरडी आहे आणि तिच्यावरून बेफिकीरपणे मार्गक्रमण करताना घात होऊ शकतो. तालिबानी उघडपणे देवबंदी इस्लामवादाचा पुरस्कार करतात, हे एका मर्यादेपलीकडे आपल्याला झेपणारे नाही. देवबंदी विचारधारेत राष्ट्र या संकल्पनेला स्थान नाही. धर्मसत्तेची स्थापना व 'अधर्मी'विरुद्ध लढून त्यांचा निःपात करणे हे मूळ सूत्र. तालिबानच्या अनेक पिढ्या भारतातील दारुल उलूम देवबंद आणि पाकिस्तानातील देवबंदी मदरशांमध्ये शिकल्या. पाकिस्तानातील झिया उल हक आणि आता असीम मुनीरसारख्या लष्करशहांनी जिहादींचा वापर राष्ट्रासाठी करण्याचा प्रयत्न चालवला आणि यातूनच मूळ देवबंदींशी पाकिस्तानचे खटके उडतात. देवबंदी विचारधारा पोथीशरण आहे आणि आधुनिक जगताशी तिला देणेघेणे नाही. त्यामुळेच महिलांविषयी तालिबानी राज्यकर्त्यांचे धोरण मध्ययुगापेक्षाही मागास असते. परंतु याची प्रचीती भारतासारख्या उदारमतवादी, लोकशाही भूमीवर यावी ही आपल्या राज्यकर्त्यांची फजिती ठरते. तालिबानचे परराष्ट्रमंत्री दिल्ली दौऱ्यावर असताना महिला पत्रकारांना निमंत्रणच न मिळणे आणि त्यांच्या अनुपस्थितीत पत्रकार परिषद होणे हे येथील व्यवस्थेचे अपयश. त्याबद्दल तालिबानला दोष देऊन किंवा आमची यात भूमिकाच नव्हती असे म्हणून हात झटकून टाकता येत नाहीत. आपले परराष्ट्र खाते अशी सबब देते, हे गोंधळलेपणाचे आणि अपरिपक्वतेचे लक्षण. अफगाणी पाहुण्यांची ही अशी मेहमान-नवाज़ी करण्याची काहीच गरज नव्हती. असले चाळे खपवून घेतले जातात, कारण आपण खमके नसतो.

पाकिस्तानच्या बरोबरीने आणखी एक उपद्रवी देश दक्षिण आशियात असू नये, या भूमिकेतून आपण अफगाणिस्तानशी स्नेहबंधाची भूमिका घेत असतो. बांगलादेशसारखा जुना मित्रदेश वैरीसम झाल्यानंतर ही गरज अधिकच अधोरेखित होते. अफगाणिस्तानातील तालिबान शासकांशी जुळवून घेण्यामागे ही झाली सामरिक गरज. दुसरी गरज रोकडी व्यापारी. चाबहार हे बंदर आपण इराणमध्ये विकसित करतो आहोत. या बंदरातून मध्य आशियात व्यापारमार्ग सुनिश्चित करण्यासाठी तालिबानची अनुकूलता आवश्यक ठरते. या शर्यतीमध्ये आपल्यासमोर चीनचे खडतर आव्हान आहे. गेल्या जून महिन्यात पाकिस्तान आणि चीनचे परराष्ट्रमंत्री काबूलमध्ये जमले आणि त्यांनी पाकिस्तान-चीन आर्थिक मार्गिका अफगाणिस्तानातून नेण्याविषयी चर्चा केली. एका व्यापारी मार्गाला आव्हान देण्यासाठी दुसरा व्यापारी मार्ग कार्यान्वित होणे अनिवार्य. तो व्हायचा तर तालिबानशी जुळवून घेणे आले. म्हणूनही त्या देशाशी संपर्क, सहकार्य वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान यांच्यात सध्या तीव्र चकमकी झडत आहेत. केवळ त्यावरून आपण सामरिक मार्गाने पाकिस्तानची दोन्ही बाजूंनी कोंडी करू, या भ्रमात मात्र न राहिलेलेच बरे. कारण पाकिस्तानची कोंडी करावी इतके तालिबानचे लष्करी बळ नाही. शिवाय या टापूत चीनचे व्यापारी हितसंबंध गुंतलेले असल्यामुळे दोन्ही देशांतील संघर्ष एका मर्यादेपलीकडे गेले तर चीन मध्यस्थी करेल. तेव्हा हा संघर्ष किती चिघळतो वा निवळतो याची वाट न पाहता भारताने सावधपणे पावले उचलली पाहिजेत. अफगाण भूमीवरून भारतविरोधी कारवाया होऊ न देण्याची हमी तालिबानने दिली, तिचे स्वागत. या हमीचा पाठपुरावा तेथे गुंतवणूक वाढवून करावा लागेल. अफगाणिस्तानकडे खुष्कीचा मार्ग खैबर खिंडीतून जातो. भल्याभल्या महासत्तांची ही खिंड पार करताना फजिती झालेली इतिहासाने पाहिली. त्यात आपले नाव समाविष्ट होऊ नये इतकीच अपेक्षा. खैबर खिंडीतला हा खेळ सावधपणे खेळणेच हितकारक.

लेख

ऊसतोडीची 'उचल' लवकरच कायद्याच्या चौकटीत?

डॉ. निशिकांत चंद्रकांत वारभुवन
ऊसतोड कामगार या विषयाचे अभ्यासक तथा संशोधक. स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड, उप-परिसर, लातूर
nishikant.warbhuwan@gmail.com

> **येत्या हिवाळी अधिवेशनात ऊसतोड मजुरांसाठीच्या कायद्याचे विधेयक विधानसभेत मांडले जाण्याची शक्यता आहे. त्यानिमित्त संख्येने मोठ्या आणि 'उचली'च्या चक्रात पिचणाऱ्या समूहाच्या प्रश्नांचा वेध.**

साखर उद्योग हा महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जातो. मात्र या उद्योगाचा पाया असलेला ऊसतोड मजूर मात्र कायमच दुर्लक्षित राहिला आहे. सरकारकडून ऊसतोड मजुरांसाठी स्वतंत्र कायद्याचा मसुदा तयार करून तो येत्या हिवाळी अधिवेशनात मांडला जाण्याची शक्यता आहे. या कायद्याच्या माध्यमातून ऊसतोड मजुरांना आरोग्य, सुरक्षा आणि सामाजिक संरक्षण प्रदान करण्याबरोबरच ऊस वाहतूकदार, मुकादम व साखर कारखान्यांच्या होणाऱ्या आर्थिक फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करेल, असे दिसते.

ऊसतोड मजुरांचे प्रश्न अत्यंत गुंतागुंतीचे आणि विविध स्वरूपाचे असले तरी त्यांच्या मुळाशी या व्यवसायामध्ये रूढ असलेली 'उचल' हीच प्रमुख समस्या आहे. महाराष्ट्रात ऊसतोडणीचा हंगाम साधारणपणे दसऱ्याच्या सणापासून ते अक्षय तृतीयेपर्यंत असतो. त्याच्या तीन महिने आधीच म्हणजेच श्रावणापासूनच मजुरांना उचल दिली जाते. ती येणाऱ्या हंगामात ऊस तोडून फेडावी लागते. गरिबांना अनेकदा उचल घेण्याशिवाय पर्याय नसतो. सर्वाधिक ऊसतोड मजूर पुरविणाऱ्या बीड जिल्ह्याची 'जिल्हा मध्यवर्ती बँक' बुडणे आणि असंख्य मजुरांना 'उचल' घेऊन कोयता हातात घेण्यास भाग पडणे, हा योगायोग नसून या व्यवस्थेतील विसंगतीचे प्रतीक आहे.

ऊसतोड मजुरांचे अगदी सुरुवातीच्या काळातील हंगामी स्थलांतर हे पाथर्डी, आष्टी, पाटोदा, शिरूर या डोंगराळ व दुष्काळी तालुक्यांमधून पश्चिम महाराष्ट्रातील काही साखर कारखान्यांकडे होत असे. या भागातील निवडक अल्पभूधारक शेतकरी कुटुंबांचा जगण्याचा आणि जनावरे जागविण्याचा ऊसतोड हा केवळ जोडधंदा होता. परंतु अलीकडील काळात राज्यात वाढत असलेले उसाचे क्षेत्र, साखर कारखान्यांची वाढलेली संख्या यामुळे ऊसतोडणी मजुरांची मागणी जास्त आहे. संपूर्ण मराठवाडा, विदर्भातील काही जिल्हे, उत्तर महाराष्ट्रातील मोठा भाग ऊस तोडणीसाठी उचल घेत आहे. मुकादमाकडून घेतलेली उचल फेडण्यासाठी त्यांना अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत, पहाटेपासूनच मेहनत करावी लागते. मजूर जोडप्यांना दिवसभरात सरासरी तीन ते साडेतीन टन ऊसतोड करावी लागते तरीही दिवसाला जास्तीत जास्त ७५० रुपये पदरात पडतात. ऊसतोडणीचा 'सिझन' कमीतकमी १४० दिवस

चालला पाहिजे परंतु असे होत नाही. गत वर्षी तर केवळ ८३ दिवसच 'सिझन' झाला. यामुळे मागील हंगामातील थकबाकी आणि पुढच्या हंगामातील देण्यात येणारी उचल यामुळे मजूर कायमस्वरूपी कर्जाच्या जाळ्यात अडकतात. कोणी रोखीने सर्व उचल फेडून या चक्रातून बाहेर पडू इच्छित असेल, तर मुकादम दरमहा ५ ते १० टक्के व्याज दराने परतफेड करण्यास सांगतात, जे की बहुतांश मजुरांना शक्य होत नाही. परिणामी, ऊसतोडीच्या दुष्टचक्रातून बाहेर पडता येत नाही व वेठबिगारीचे जीवन जगावे लागते. यात कधी मुकादम तर कधी मजूर भरडले जातात. मात्र या सर्व प्रकारात एकट्या मजुराला, मुकादमाला किंवा साखर कारखान्यांना सरसकटपणे दोषी धरता येणार नाही. उलट, ही व्यवस्था सरकारच्या हस्तक्षेपाने आणि स्वतंत्र कायद्याद्वारे सुधारण्याची गरज आहे.

साखर कारखाने दरवर्षी उचलीपोटी कोट्यवधी रुपयांची रक्कम संबंधित ट्रस्टना देतात. हे ट्रस्ट अप्रत्यक्षरीत्या कारखान्यांच्या माध्यमातूनच स्थापन केलेले असतात. पुढे, कारखान्यांकडून मिळालेली रक्कम, या 'ट्रस्ट'द्वारे ट्रक किंवा ट्रॅक्टर वाहतूकदारांना दिली जाते. ते मुकादमांना आणि मुकादम ऊसतोडणी मजुरांना उचलीच्या स्वरूपात पैसे पुरवतात. या प्रक्रियेत प्रत्येक टप्प्यावर तोंडी किंवा लिखित करार केले जातात. पण, ते कायदेशीर दृष्टिकोनातून किती परिपूर्ण आणि न्याय्य असतात याबद्दल शंका आहे. कारण उचलीची परतफेड होत नाही किंवा मजूर कामावर येत नाहीत तेव्हा करारपत्रांचा आधार घेऊन, कायदेशीर कार्यवाही न होता, बेकायदेशीरपणे वसुली केली जाते. धमकी, मारहाण, डांबून ठेवणे, अपहरण इत्यादी बेकायदेशीर बाबी केल्या जातात. या सगळ्यामुळे प्रचलित उचल पद्धत तातडीने कायद्याच्या कक्षेत आणणे गरजेचे आहे.

'आपण मुकादमाकडून उचल घेतली आहे, तर त्याचे पैसे फेडावेच लागतील' अशी नैतिकता बाळगणारे असंख्य ऊसतोड मजूर आहेत. मात्र याच्या उलट, उचल घेऊनही कामावर न येणारे, हंगाम अर्ध्यात सोडून पळून जाणारे किंवा फसवणूक करणारे मजूरही दिसून येतात. त्यांची झळ साखर कारखाना, वाहतूकदार, मुकादम आणि खुद्द प्रामाणिक मजूर या सर्वांनाच बसते. असे मजूर एकाच वेळी दोन-तीन मुकादमांकडून 'उचल' घेतात. परंतु ऊसतोडीसाठी मात्र एकाच मुकादमाबरोबर जावे लागते. परिणामी मजुरांच्या पळवापळवीच्या घटना घडतात. दोन मुकादमांमध्ये संघर्ष होतो. कधीकधी गावपातळीवरील स्थानिक राजकारण, आपापसातील कुरघोड्या यातून मोठा संघर्ष निर्माण होतो. अशा परिस्थितीत मुकादमांकडून साखर कारखान्याला करारानुसार तेवढ्या संख्येने मजूर पुरविले जात नाहीत; परिणामी साखर कारखाने, ऊस वाहतूकदार, मुकादम आणि ऊस उत्पादक शेतकरी यांना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक तोटा सहन करावा लागतो. अशा घटना रोखण्यासाठी मजूर आणि त्यांचे मुकादम यांचे नोंदणीकरण (registration) तसेच ऊसतोडणीचे करार हे 'ऑनलाइन पोर्टल'च्या माध्यमातून संबंधित तालुक्याच्या शासकीय कार्यालयात करणे आवश्यक आहे. ही प्रक्रिया बायोमेट्रिक व आधार-लिंक्ड प्रणालीद्वारे होणे बंधनकारक करावे, जेणेकरून मजूर एकाच मुकादमाशी व एकाच कारखान्याशी करार करू शकतील. या शिवाय बायोमेट्रिक कराराच्या वेळी पती, पत्नी या दोघांचीही एकत्रित उपस्थिती आणि नोंद बंधनकारक करण्यात यावी. कराराच्या वेळी दिली जाणारी उचलीची रक्कम थेट मजुरांच्या बँक खात्यात जमा करणे अनिवार्य असावे. त्यामुळे व्यवहारात पारदर्शकता येईल. उचल कायद्याच्या कक्षेत व सरकारी नियंत्रणाखाली येईल. त्याचप्रमाणे असा करार केवळ ऊसतोड मजूर व मुकादम यांच्यामध्ये मर्यादित न राहता, साखर कारखान्यालाही करारातील आवश्यक पक्षकार (party to the contract) म्हणून समाविष्ट करणे बंधनकारक करण्यात यावे. मजूर-मुकादम-कारखाना या तिन्ही घटकांना एकत्र घेऊन केलेले त्रिपक्षीय करार कायदेशीरदृष्ट्या अधिक परिपूर्ण ठरतील. असे केल्याने कारखान्यांची जबाबदारी अधोरेखित होईल आणि मजुरांचे कायदेशीर, सामाजिक व आर्थिक हक्क अधिक बळकट व सुरक्षित होतील. याशिवाय, प्रायोगिक तत्त्वावर काही कारखान्यांकडून काही मजुरांना पारंपरिक 'उचल' पद्धतीऐवजी दरमहा किंवा दर पंधरवड्याला वेतन रूपात मजुरी देण्याची व्यवस्था निर्माण करावी. हे वेतन विद्यमान मजुरीपेक्षा अधिक असावे किंवा इतर प्रोत्साहनपर लाभ (incentives) द्यावेत, ज्यायोगे उचल पद्धतीला पर्याय निर्माण होतील. उचल आणि उचलीची परतफेड यातून निर्माण झालेले शोषण आणि वेठबिगारी संपुष्टात येईल.

बहुतांश ऊसतोड मजूर हे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, पारंपरिकदृष्ट्या मागासलेल्या आणि शेतमजुरीवर अवलंबून असलेल्या वंचित जातींमधून येतात. त्यामुळे त्यांना जमिनीची मालकी, आर्थिक स्थैर्य किंवा शैक्षणिक संधी मिळत नाहीत. अलीकडील काळात धुळे, नंदुरबार जिल्ह्यांतील सीमावर्ती भागातून येणारा आदिवासी मजूर, ऊसतोडीच्या कामात अगदीच नवखा आहे. त्यांना आर्थिक व्यवहार फारसा समजत नाही. म्हणून अतिशय कमी उचल देऊन त्यांना आणले जाते. या आदिवासींसह सर्वच ऊसतोड मजुरांचे श्रम पुरेशा सोयीसुविधा न देता स्वस्त दरात खरेदी केले जातात. यात वर्गीय विषमता ठळकपणे दिसते. स्त्रियांची स्थिती आणखी बिकट आहे. आर्थिक निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग जवळजवळ शून्य असतो. शिवाय लैंगिक आणि मानसिक छळालाही त्या बळी पडतात. कौटुंबिक हिंसाचार, आरोग्याच्या समस्या, मुलांचे संगोपन, घरगुती जबाबदाऱ्या आणि त्यासोबत ऊसतोडीचे कष्टप्रद काम, याचा अधिकचा ताण स्त्री म्हणून तिच्या वाट्याला येत असतो. अशाप्रकारे जातीय संरचना, वर्गीय विषमता आणि पितृसत्ताक व्यवस्था लक्षात घेऊन धोरणात्मक हस्तक्षेप करणे आवश्यक आहे. त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण, सुरक्षित कामाची हमी, आरोग्य-शिक्षण सुविधा आणि स्त्री-पुरुष समानतेसाठी ठोस कायदेशीर उपाय आवश्यक आहेत. भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकास बहाल केलेला सामाजिक न्याय, श्रमाची प्रतिष्ठा आणि सन्मानाने जगण्याचा अधिकार शाबूत राखणे ही या व्यवसायात मोठ्या संख्येने असणाऱ्या दलित, आदिवासी, भटके, महिला आणि कष्टकरी समुदायाची मूलभूत गरज आहे. अशाप्रकारे ऊसतोड मजुरांसाठी स्वतंत्र कायदा तयार करत असताना अनेक बाबी लक्षात घेतल्या पाहिजेत. त्याची व्याप्ती सर्वसमावेशक असली पाहिजे. त्याकरिता कायदा निर्मितीच्या प्रक्रियेत ऊसतोड मजूर, त्यांच्या संघटना, संशोधक, विचारवंत, सामाजिक कार्यकर्ते, पोलीस प्रशासन आणि स्वयंसेवी संस्थांचा सक्रिय सहभाग असणे अत्यावश्यक आहे.

विश्लेषण

अमेरिका-चीन व्यापार युद्धाचा भडका दुर्मीळ खनिजांमुळे?

संजय जाधव
sanjay.jadhav@expressindia.com

> **चीनने दुर्मीळ खनिजांच्या निर्यातीवरील निर्बंधात आणखी वाढ करण्याचे पाऊल उचलल्यावर ट्रम्प यांनी प्रत्युत्तरादाखल चीनवर अतिरिक्त १०० टक्के आयात शुल्क आकारण्याची घोषणा केली. यामुळे या महासत्तांमध्ये व्यापार युद्धाचा भडका उडण्याची चिन्हे आहेत.**

दुर्मीळ खनिजे म्हणजे काय?

दुर्मीळ खनिजे ही १७ प्रकारच्या मूलद्रव्यांचा समूह आहेत. ही खनिजे नावाप्रमाणे दुर्मीळ नसतात. चांदी, सोने आणि प्लॅटिनमपेक्षा ती मुबलक प्रमाणात आढळून येतात, परंतु त्यांचे उत्खनन करून विलगीकरण करण्याची प्रक्रिया खूप अवघड आणि खर्चीक असते. या खनिजांच्या शुद्धीकरणासाठी आवश्यक असणारे प्रगत तंत्रज्ञान उपलब्ध नसणे हाही खूप मोठा अडसर आहे. या क्षेत्रात चीनची मक्तेदारी आहे. या खनिजांचा वापर प्रामुख्याने मोबाइल, इलेक्ट्रिक वाहने, इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंपासून बॉम्ब व इतर शस्त्रांच्या निर्मितीसाठी केला जातो. अमेरिकेच्या एफ-३५ लढाऊ विमानांपासून पाणबुड्या, लेझर उपग्रह आणि क्षेपणास्त्रांमध्ये त्यांचा वापर केला जातो.

चीनकडून कोणते निर्बंध?

चीनने दुर्मीळ खनिजांचा वापर होणाऱ्या चुंबकांच्या निर्यातीवर आणखी निर्बंध लादले आहेत. चीनमधील दुर्मीळ खनिजांचा अंश अथवा चीनमधील या खनिजांच्या उत्खनन प्रक्रियेवर अवलंबून असलेल्या चुंबकांचा यात समावेश आहे. याचबरोबर चीनमधील निर्माण प्रक्रियेचा वापर करण्यात आलेल्या चुंबकांवरही हे निर्बंध आहेत. सेमीकंडक्टरच्या कच्च्या मालाचा विचार करता त्यात चीनमधील दुर्मीळ खनिजांचा वापर किमान ०.१ टक्का असतो. त्यामुळे त्यावरही हेच निर्बंध असतील. हे निर्बंध १ डिसेंबरपासून लागू होतील. संरक्षणासाठी या खनिजांच्या निर्यातीस पूर्णपणे मनाई करण्यात येणार आहे. दुर्मीळ खनिजांचा समावेश असलेल्या उत्पादनांची निर्यात करण्यासाठी स्थानिक अथवा परदेशी कंपन्यांना आधी चीन सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.

मक्तेदारी कोणाची?

चीनकडून १९९० पासून दुर्मीळ खनिजांच्या जागतिक मागणीपैकी ८५ ते ९५ टक्के मागणी पूर्ण केली जाते. दुर्मीळ खनिजांच्या ७० टक्के उत्खननावर चीनचे नियंत्रण आहे. याच वेळी त्यांचे विलगीकरण आणि प्रक्रियेवर ९० टक्के नियंत्रण आहे. या दुर्मीळ खनिजांपासून चुंबक निर्मितीत ९३ टक्के वाटा एकट्या चीनचा आहे. चीनने १९९० मध्ये दुर्मीळ खनिजांना संरक्षित आणि सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचे घोषित केले. त्यामुळे त्यावरील मक्तेदारीचा वापर चीन आता शस्त्रासारखा करीत आहे. जागतिक पुरवठा नियंत्रित करण्यासह व्यापार तणाव सोडविताना चीनकडून याच दुर्मीळ खनिजांचा वापर केला जात आहे. ट्रम्प यांनी एप्रिलमध्ये चीनवर अतिरिक्त आयात शुल्क आकारल्यानंतर अशाच प्रकारचे निर्बंध लादण्यात आले.

जगावर परिणाम काय?

दुर्मीळ खनिज निर्यातीवरील निर्बंध चीनने वाढविल्याने जागतिक पुरवठा साखळीवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. याचा फटका सर्वच देशांना बसणार आहे. अमेरिका आणि चीनमधील व्यापार तणावाचा परिणाम जगभरातील भांडवली बाजारांवर होत आहे. मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या समभागात मोठी घसरण होत आहे. चीनमधील दुर्मीळ खनिजांवर अवलंबून असलेल्या कंपन्यांची डोकेदुखी यामुळे वाढली आहे. सेमीकंडक्टर उत्पादनात आघाडीवर असलेल्या तैवानलाही याचा फटका बसण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. मात्र, तैवानने याचा इन्कार केला आहे.

व्यापार युद्धाकडे वाटचाल?

अमेरिका आणि चीनने एप्रिलपासून एकमेकांवर अतिरिक्त आयात शुल्काची आकारणी केली होती. त्या वेळी चर्चेतून तोडगा निघून दोन्ही देशांनी थोडी माघार घेतली होती. त्यानंतर अमेरिकेने चीनच्या उत्पादनांवर ३० टक्के अतिरिक्त आयात शुल्क तर चीनने अमेरिकेच्या उत्पादनांवर १० टक्के अतिरिक्त शुल्क आकारणी केली होती. तेव्हापासून दोन्ही देशांमध्ये चर्चेच्या फेऱ्या सुरू आहेत. चीनच्या वाणिज्य मंत्रालयाने अमेरिकेवर टीका केली आहे. अमेरिकेची भूमिका दुटप्पी असल्याचे मंत्रालयाने म्हटले आहे. आम्ही अशा प्रकारच्या गोष्टींना घाबरत नाही, असा संदेशही देण्यात आला आहे. मात्र अमेरिकेकडून अतिरिक्त आयात शुल्काची घोषणा करण्यात आल्याने चीनकडून तशाच प्रकारचे थेट प्रत्युत्तर मिळण्याची शक्यता आहे. यातून अमेरिका आणि चीनमध्ये व्यापार युद्धाचा भडका उडू शकतो.

अन्वयार्थ

प्रदूषणच, पण फक्त फटाक्यांचे नव्हे...

दिवाळीदरम्यान तीन दिवस दिल्ली आणि परिसरात 'ग्रीन' - म्हणजे 'पर्यावरणपूरक' नसले तरी पर्यावरणास कमी अपायकारक म्हणून 'हरित' - फटाक्यांना परवानगी देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीमधल्या प्रदूषणाच्या प्रश्नावर मोठा सुज्ञ मार्ग काढला अशी कोणाची समजूत असेल, तर ते भाबड्यांच्या नंदनवनात राहतात, असे म्हणावे लागेल. अनेक कारणांमुळे होणारे हवेचे प्रदूषण हा मुद्दा दिल्लीतच नाही, तर देशभर सगळीकडेच धोक्याच्या पातळीवर येऊन पोहोचलेला असताना दोनच दिवस आणि संध्याकाळी दोनच तास 'हरित' फटाक्यांच्या आतषबाजीला परवानगी देणे हे पायवाटेने जाऊ पाहणाऱ्यांना महामार्ग खुला करून देण्यासारखेच आहे. असे म्हणण्याचे कारण कोणतीही बंदी मोडण्यात भारतीयांना वाटत आलेले भूषण. कशावरही बंदी आली की छुप्या मार्गाने ती मोडण्याचीच वृत्ती आपल्याकडे दिसून येते. असे असताना सरकारच्या याचिकेवर न्यायालयाने एक पाऊल मागे घेणे ही बाब प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर घातकच. याचे कारण दोन तासांचे चार तास, दोनाचे चार दिवस आणि 'हरित' फटाक्यांच्या मागून नेहमीचे फटाके कधी येतील ते कुणालाच कळणार नाही. मुळात हरित फटाके हे मिथकच म्हणायला हवे. कारण ते आवाज कमी करतात, पण कमी प्रमाणात का होईना, हवेचे प्रदूषण करतातच. त्यामुळे त्यांना मर्यादित वेळेत परवानगी देणे हे काही प्रदूषण कमी करायला हातभार लावणारे नाही. त्यात ऑक्टोबर, नोव्हेंबर महिन्यात म्हणजे साधारण दिवाळीच्या काळात दिल्ली आणि परिसरात फटाके, शेतातील खुंट जाळणे, वाहनांचा धूर, बांधकामांची धूळ आणि थंड हवेमुळे प्रदूषित धूलिकण जमिनीलगतच तरंगत राहणे या कारणांमुळे प्रचंड प्रदूषण असते. एका आकडेवारीनुसार गेली चार वर्षे दिवाळीच्या दुसऱ्या दिवशी दिल्लीतील हवेची गुणवत्ता-पातळी ४०० च्या वर होती. 'एक्यूआय' (एअर क्वालिटी इंडेक्स) म्हणून ओळखली जाणारी ही गुणवत्ता-पातळी खरे तर अवगुण किती कमी वा जास्त हे दाखवणारी असते. तिचे ० ते ५० हे प्रमाण योग्य, तर ३०१ ते ५०० हे प्रमाण अतिधोकादायक मानले जाते. यातून, दिवाळीनंतरच्या काळात दिल्लीची अवस्था एखाद्या गॅस चेंबरपेक्षा कमी नसते, हेच लक्षात येते.

या कारणांमुळेच २०२४ मध्ये दिल्लीमध्ये फटाकेविक्रीवर पूर्ण बंदी घालण्यात आली होती. पण केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार आणि तथाकथित हरित फटाके विक्रेते यांच्या याचिकेवर निर्णय देताना सरन्यायाधीश बी. आर. गवई आणि न्या. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने ती शिथिल केली. परंपरा आणि पर्यावरण तसेच फटाका उत्पादकांचा जगण्याचा, व्यवसाय करण्याचा हक्क यांचा एकत्रित विचार करत असल्याचे या खंडपीठाने नमूद केले. सध्या सगळीकडेच भारतीय परंपरेचा उदोउदो केला जातो. पण दिवाळीत फटाके वाजवणे ही काही प्राचीन परंपरा नाही. दिवाळी हा सुगीच्या काळात साजरा केला जाणारा प्रकाशाचा सण. गेली शेकडो वर्षे तो त्याच पद्धतीने साजरा केला जातो. पण पूर्वीच कधीतरी चीनमधून भारतात आलेले फटाके गेल्या अवघ्या शतकभरात दिवाळीशी जोडले गेले आणि आता अधिकाधिक कानठळ्या बसवणाऱ्या फटाक्यांची स्पर्धा ध्वनीच्या आणि हवेच्या प्रदूषणात दरवर्षी प्रचंड भर घालते आहे. फटाक्यांमुळे दरवर्षी होणारे अपघात हा मुद्दा आहेच, पण अशा आवाजांना घाबरणारी लहान मुले, वृद्ध माणसे, शांतताप्रेमी नागरिक, श्वसनविकाराचे रुग्ण, घराघरातले, रस्त्यावरचे प्राणी यांना होणाऱ्या त्रासाचा कोणताही विचार न करता फटाके वाजवले जातात.

जगाचे काय होईल ते होवो, माझा आनंद मी घेणार या वृत्तीचे लोक हा वेगळ्या चर्चेचा विषय आहे. पण त्यांच्यापेक्षा जास्त गंभीर आहे, ते लोकमतापुढे झुकून या मुद्द्यावर याचिका दाखल करणारी सरकारे आणि अशा याचिकांची घेतली जाणारी दखल. पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील परिसरात एक किलोमीटरच्या बफर झोनमध्ये बांधकामांना २०२२ मध्ये घातलेली बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने अशाच आणखी एका याचिकेची दखल घेऊन शिथिल केली होती. विकासप्रकल्पांच्या आखणीआधी पर्यावरणीय मंजुरीची अट न्यायालयानेच सरकारच्या विनंतीवरूनच शिथिल केली. चार धाम रस्ते प्रकल्पासाठी रस्त्याची रुंदी मर्यादित ठेवण्यात आली होती. पण संरक्षण मंत्रालय न्यायालयात गेल्यावर काही ठिकाणी ती वाढवण्यात आली. समुद्रकिनाऱ्यालगत मोठ्या बांधकामांना असलेले निर्बंध नंतर शिथिल करण्यात आले. न्यायालयानेच पर्यावरणाचा विचार करून घातलेले कठोर निर्बंध नंतर वेगवेगळ्या कारणांनी सवलती देत कसे मागे घेतले याची ही काही उदाहरणे फटाक्यांविषयीच्या ताज्या निर्णयामुळे चर्चेत आली आहेत. प्रदूषणमुक्त पृथ्वी पुढच्या पिढ्यांच्या हाती सोपवण्याच्या आणाभाका घेऊनही प्रत्यक्ष पावले उचलण्यापेक्षा लोकोपवादांना चुचकारण्यास प्राधान्य असणे, हे फटाक्यांपेक्षा जास्त प्रदूषणकारी आहे.

More Newspaper and Magazines Telegram Channel join Search https://t.me/Magazines_8890050582 (@Magazines_8890050582)

शांति का मतलब संघर्ष की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि इससे निपटने की क्षमता है। -महात्मा गांधी

अहमदाबाद से आशा

भारत के खेल इतिहास में एक और नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। दरअसल, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ की कार्यकारी समिति ने 2030 में होने वाले सौवें राष्ट्रमंडल खेलों के प्रस्तावित मेजबान शहर के रूप में अहमदाबाद के नाम की सिफारिश की है, जो देश के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण होने के साथ वैश्विक स्तर पर भारत की उभरती हुई ताकत का भी प्रतीक है। इस बाबत अंतिम निर्णय 26 नवंबर, 2025 को ग्लासगो में होने वाली महासभा में लिया जाएगा, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि यह मात्र औपचारिकता ही होगी। उल्लेखनीय है कि इस आयोजन के लिए नाइजीरिया की राजधानी अबुजा की तरफ से भी आवेदन मिला था, लेकिन एक व्यापक प्रक्रिया के तहत दोनों शहरों के प्रस्तावों का मूल्यांकन किया गया, जिसमें अहमदाबाद ने अपनी अत्याधुनिक सुविधाओं, विविधता और ऊर्जावान दृष्टिकोण से सभी को प्रभावित किया। गौरतलब है कि भारत ने पिछली बार 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी, जो खराब योजना, बुनियादी ढांचे के निर्माण में देरी और भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण प्रभावित हुआ था। लेकिन तब से देश की स्थितियों में काफी बदलाव आए हैं और खेलों में भी हमारी स्थिति मजबूत हुई है। 2022 के बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भारत कुल 61 पदक जीतकर तालिका में चौथे पायदान पर रहा था। अहमदाबाद में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन देश की खेल प्रतिभाओं को तो प्रोत्साहित करेगा ही, इसके साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने, पर्यटन को प्रेरित करने और गुजरात की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पटल पर उजागर करने का भी कार्य करेगा। हालांकि, यह सब इतना आसान नहीं होगा। दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन के दौरान सामने आई संगठनात्मक खामियों से सबक लेते हुए अहमदाबाद को पारदर्शी व कुशल प्रबंधन पर ध्यान देना होगा। आयोजन की लागत को नियंत्रित रखने, पर्यावरण का ख्याल रखते हुए बुनियादी ढांचों का विकास करने और समावेशी भागीदारी सुनिश्चित करने की चुनौतियां भी होंगी। ऐसे में, आयोजन को कामयाब बनाने के लिए

सरकार, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज को मिलकर काम करने की जरूरत है। यह भी सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है कि आयोजन की तैयारियों का आधार सतत विकास के मॉडल पर हो, ताकि बुनियादी ढांचे का उपयोग खेलों के बाद भी हो सके। अगर भारत इस मंच पर अपनी क्षमता दिखाता है, तो इससे एशियाई और ओलंपिक स्तर के आयोजनों के लिए भी एक विश्वसनीय मेजबान देश के रूप में उसकी स्थिति मजबूत होगी।

ट्रंप अभी चैन से नहीं बैठ सकते

इस्राइल-हमास युद्ध विराम का जैसा बखान ट्रंप कर रहे हैं, मैं उनके पक्ष या विपक्ष में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मुमकिन है कि वह सही राह पर हों। लेकिन उन्हें यह सलाह जरूर दी जा सकती है कि चूंकि हमास ने अब तक हथियार छोड़े नहीं हैं, इसलिए उन्हें तेजी-से आगे बढ़ते हुए कुछ निर्णायक जोखिम उठाने होंगे।

सोमवार को राष्ट्रपति ट्रंप जब इस्राइलियों और अरबों से यह कह रहे थे कि हम अभी पश्चिम एशिया में ऐतिहासिक सुबह देख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा था, जैसे ट्रंप अपने बैंकरों को एक जहरीले कचरे के ढेर पर दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे सुंदर, सबसे शानदार होटल बनाने की योजना के बारे में बता रहे हों। ऐसे में दिमाग में बस यही आता है कि क्या उन्हें इस जगह के इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता? आप यहां होटल बना ही नहीं सकते। लेकिन दूसरे ही क्षण ख्याल आता है कि अगर उन्होंने यह कर दिखाया तो? धमकाने, चापलूसी करने और बढ़ा-चढ़ाकर बात कहने की ट्रंप की क्षमता वास्तव में देखने लायक है, और यह सोमवार को इस्राइली संसद में तथा उसके बाद मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित एक सभा में 20 से अधिक विश्व नेताओं के समक्ष दिए गए उनके भाषण में दिखी।

थॉमस एल फ्रीडमैन
द न्यूयॉर्क टाइम्स

कोई भी पारंपरिक राजनयिक या विदेश नीति का प्रोफेसर राष्ट्रपति को ऐसे जोखिम उठाने की सलाह नहीं देता कि वह घोषणा करें कि हम पश्चिम एशिया में शांति की राह पर हैं और डोनाल्ड ट्रंप उस शांति बोर्ड की अध्यक्षता करेंगे, जो इसे लागू करेगा। दरअसल, ट्रंप की पढ़ाई एक बिजनेस स्कूल में हुई है, न कि विदेश सेवा के स्कूल में। उन्हें यकीन है कि वह येन-केन-प्रकारेण इस संघर्ष को एक सुखद अंत तक पहुंचा सकते हैं। इस मामले में, मैं उनके पक्ष या विपक्ष में दांव नहीं लगा सकता, लेकिन उन्हें एक मुफ्त सलाह जरूर दूंगा कि राष्ट्रपति महोदय, इस सौदे को पूरा करने के लिए आपको तेजी से आगे बढ़ना होगा और कुछ जोखिम उठाने होंगे। लेकिन अब तक इस दिशा में कुछ होता नहीं दिखता।

बेशक अभी समय है, लेकिन अभी तो मुझे अगले चरण की कोई शुरुआत भी नजर नहीं आ रही। संयुक्त राष्ट्र का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, जो एक उचित फलस्तीनी सुरक्षा बल का गठन होने तक गाजा में हमास के निरस्त्रीकरण और सुरक्षा की निगरानी के लिए अरब/अंतरराष्ट्रीय शांति सेना बनाने की बात करे। गाजा के पुनर्निर्माण के लिए जरूरी अरबों डॉलर की

धनराशि भी नहीं दिखती, और यह भी नहीं पता कि फलस्तीनी टेक्नोक्रेटों के मंत्रिमंडल की नियुक्ति और प्रबंधन कौन करेगा, जो हमास के बदले गाजा को चलाएंगे। एक पत्रकार होने के नाते, अगर मैं जानना चाहूं कि आगे क्या और कैसे होगा, तो मुझे समझ नहीं आता कि किससे बात करूं। यह मुसीबत का कारण है। जिस चीज ने बंधकों की रिहाई, कैदियों की अदला-बदली और युद्धविराम जैसी बड़ी सफलताएं दिलाईं, उससे पश्चिम एशिया में व्यापक शांति नहीं आएगी, जब तक कि ट्रंप इस्राइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और हमास के पर्यवेक्षकों (तुर्किये, मिस्र और कतर) के साथ मिलकर कानून नहीं बनाते।

ट्रंप के पास आराम करने के लिए एक पल भी नहीं है। पहला चरण जितना कठिन था, उससे ज्यादा मुश्किलें आगे आएंगी। उन्हें नेतन्याहू से यह भी पूछना होगा कि 'क्या आप इस्राइली राजनीति के केंद्र में आकर एक ऐसा गठबंधन बनाने जा रहे हैं, जो एक संशोधित फलस्तीनी प्राधिकरण के साथ मिलकर हमास की जगह ले सके और गाजा व पश्चिमी तट, दोनों पर शासन कर सके? या फिर आप वही खेल जारी रखेंगे, जो आपने 1996 से अमेरिकी राष्ट्रपतियों के साथ खेला है-और गाजा में हमास को चुपचाप जिंदा रखने और फलस्तीनी प्राधिकरण को कमजोर करने की कोशिश करेंगे, ताकि बता सकें कि दूसरा पक्ष शांति के लिए तैयार नहीं है?' कतर, तुर्किये और मिस्र तथा जो भी अरब देश गाजा में सेना भेजने के लिए तैयार हैं, उनसे भी ट्रंप को पूछना चाहिए कि 'क्या आप हमास को निरस्त्र करने के लिए मजबूर करेंगे और गाजा में फलस्तीनी प्राधिकरण के नेतृत्व की वापसी का मार्ग प्रशस्त करेंगे या हमास के साथ चालाकी से पेश आएंगे, क्योंकि वह वहां फिर से नियंत्रण स्थापित करना चाह रहा है?'

हालांकि, हमास ने संकेत दिया है कि वह गाजा में नागरिक शासन किसी अन्य फलस्तीनी इकाई को सौंपने को तैयार है, लेकिन उसने कभी सार्वजनिक रूप से नहीं कहा कि वह हथियार डाल देगा। यदि हमास निरस्त्रीकरण में विफल रहता है, तो इससे नेतन्याहू को युद्ध पुनः शुरू करने का बहाना मिल जाएगा, तथा अगले चरणों में आने वाली सभी राजनीतिक चुनौतियों से बचने का मौका मिल जाएगा। इस बात की बिल्कुल संभावना नहीं है कि ट्रंप इस संघर्ष विराम को स्थायी शांति में तब्दील कर सकें, जब तक कि हमास को यथाशीघ्र एक संशोधित फलस्तीनी प्राधिकरण द्वारा हटा नहीं दिया जाता। इस्राइली लेखिका अरी शावित ने बताया कि 'जब ट्रंप ने फरवरी में गाजा को गाजावासियों से खाली करने का सुझाव दिया, तो इस्राइल को लगा कि गाजा पर कब्जा कर लिया जाएगा और अगला कदम वेस्ट बैंक होगा। अब आठ महीने बाद ट्रंप उन्हीं इस्रालियों से कह रहे हैं कि गाजा और वेस्ट बैंक पर कब्जा नहीं किया जाएगा।' जल्द ही ट्रंप को यह एहसास हो जाएगा कि यदि गाजा में स्थायी शांति चाहिए, तो उन्हें शीघ्र वहां एक संशोधित फलस्तीनी प्राधिकरण स्थापित करना होगा।

जून 2007 में हमास द्वारा हटाए जाने से पहले, फलस्तीनी प्राधिकरण गाजा पट्टी पर शासन करता था, और यह सब एक कानूनी, आर्थिक और व्यापारिक ढांचे के तहत होता था, जिस पर ओस्लो समझौते के तहत इस्राइलियों और फलस्तीनी राजी हुए थे। बस उस ढांचे को फिर से इस्तेमाल करने की जरूरत है। गाजा में नए सिरे से शासन व्यवस्था को व्यवस्थित होने में महीनों लगेंगे, और हमास इस खालीपन का फायदा उठाएगा। मेरे विचार से फलस्तीनी राष्ट्र का संचालन संशोधित फलस्तीनी प्राधिकरण द्वारा होना चाहिए और उसे एक अरब/अंतरराष्ट्रीय शांति सेना का निरंतर समर्थन मिले, जो यह सुनिश्चित करेगा कि यह फलस्तीनी राष्ट्र इस्राइल के लिए कभी खतरा न बने, और उसे समर्थन देने वाला अंतरराष्ट्रीय 'शांति बोर्ड' उसकी आर्थिक सफलता की गारंटी देगा। लेकिन इसका एकमात्र रास्ता यही है कि हमास को जल्दी से निरस्त्र कर दिया जाए, और फलस्तीनी प्राधिकरण को जल्दी से पुनर्गठित करके गाजा में स्थापित कर दिया जाए।

©The New York Times 2025

त्योहार

इस दिवाली निभाएं कुछ जिम्मेदारियां

घरों की सफाई वातावरण को स्वच्छ करती है, तो गैर-जरूरी खरीदारी से क्षति पहुंचती है। संतुलन व नियंत्रण से त्योहार की रौनक बनी रहेगी, तो पर्यावरण भी संरक्षित रहेगा।

दीपावली के लिए घरों में सफाई और खरीदारी साथ-साथ चल रही है। घरों की सफाई स्वच्छ वातावरण को आमंत्रित करती है, तो गैर-जरूरी खरीदारी कहीं न कहीं पर्यावरण के लिए घातक सिद्ध हो जाती है। दीपावली पर नए कपड़े खरीदने और खाद्य पदार्थ बनाने व आपस में बांटने का प्रचलन सदियों पुराना है, लेकिन यह कब अपनी सीमाओं को लांघते हुए भौतिकवादी एवं उपभोक्तावादी युग में उत्तरदायित्व के बोध से दूर हो गया, यह इन्सान को संभवतया मालूम भी नहीं पड़ा।

भारत में त्योहारों के अवसरों पर खरीदारी में विस्फोटक रूप से बढ़ोतरी होती है, वहीं पश्चिमी देशों में भौतिकता एवं दिखावे का प्रभाव ज्यादा होने से इनकी खरीद एवं चलन सामान्य दिनों में भी बढ़ोतरी की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। इसी को दृष्टिगत रखते हुए यूरोपीय संघ ने हाल ही में विशेष कानून पारित करते हुए खाद्य एवं वस्त्र से उपजे अपशिष्ट पर 2030 तक कमी लाने के उद्देश्य से लक्ष्य तय किए हैं। हालांकि, भारत में 2014 के बाद कचरा प्रबंधन को लेकर काफी जागृति आई है, किंतु आज भी प्रचलित कानून में कचरा उत्पादनकर्ता की अपेक्षा सरकारी स्थानीय निकाय संस्थाओं को ही जिम्मेदार ठहराया गया है। लोग खाद्यान्न भी बर्बाद कर रहे हैं। हालांकि, भारत में खाद्यान्न अपशिष्ट यूरोप की अपेक्षा काफी कम मात्र 55 किलो प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष है, लेकिन यदि इस पर लगाम नहीं लगाई गई, तो इसे यूरोप के समकक्ष आने में देर नहीं लगेगी। इस संदर्भ में यूरोपीय कानून से सबक लेते हुए वर्तमान में जब कचरा प्रबंधन का उचित माहौल बना हुआ है, उपभोक्ता एवं उत्पादनकर्ता को उत्तरदायी बनाया जाना आवश्यक एवं उचित होगा।

डॉ. विवेक एस अग्रवाल

भारत में दिवाली सभी वर्गों का त्योहार माना जाता है, लेकिन इस अवसर पर संतुलन और नियंत्रण, दोनों ही गड़बड़ा जाते हैं। विगत कुछ दशकों में मिठाई, मेवे, चॉकलेट समेत खाद्य एवं पेय सामग्री के आदान-प्रदान संबंधी व्यवस्था का प्रचलन भी बेतहाशा बढ़ गया है। खास तौर पर तथाकथित प्रभावशाली एवं पदस्थ व्यक्तियों के यहां विभिन्न माध्यमों से हजारों किलो तक मिठाई इत्यादि पहुंच जाती है, जिसका उन्हें भी अंदाजा नहीं रहता और परिणामस्वरूप बड़ी मात्रा में वह बर्बाद हो जाती है। कुछ वर्ष पूर्व अन्नक्षेत्र नामक संस्था ने प्रभावशाली पदस्थ व्यक्तियों से शपथपत्र के माध्यम से अधिशेष मिठाई, नमकीन आदि एकत्रित करने का प्रकल्प प्रारंभ किया था, जिसके जरिये जयपुर शहर में एक बार में ही कई टन मिठाई को बर्बाद होने से न केवल बचाया गया, बल्कि वह अनेक लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का माध्यम भी बन गया।

बर्बादी को रोकने के लिए कानून सिर्फ जरिया बन सकता है, किंतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है व्यवहार में परिवर्तन लाना। आवश्यकताओं का सही आंकलन करते हुए सीमित रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में पैकेजिंग व्यवस्था को भी पुनः परिभाषित करने की जरूरत है। चलन में आम तौर पर 250 ग्राम से लेकर एक किलोग्राम तक के मिठाई पैकेट रहते हैं। त्योहारी बिक्री में एक किलोग्राम का पैक सबसे ज्यादा बिकता है। यदि सत्कार रूप में मिठाई इत्यादि की भेंट को दिखावे से हटकर छोटे पैकेट में तब्दील कर दिया जाए, तो वह अधिक उपयोगी होने के साथ बर्बादी भी रुकेगी। इस दिवाली उत्तरदायी होने के लिए यदि हम भेंट की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा की अपेक्षा गुणवत्ता पर ध्यान दें, तो प्रदूषण एवं विषमता, दोनों पर नियंत्रण पा सकते हैं।

edit@amarujala.com

हर उम्र का अपना एक सौंदर्य है

जिन्होंने जीवन को सही मायने में जिया, वे जानते हैं कि हर उम्र का अपना सौंदर्य है। एक व्यक्ति अपने जीवनकाल में सभी प्रकार के अनुभव प्राप्त करता है और ये अनुभव उसे एक पूर्ण और सार्थक जीवन की ओर ले जाते हैं।

आपने कभी लोगों को यह कहते नहीं सुना होगा, 'काश मैं 65 साल का होता।' लेकिन यह जरूर सुनते हैं, 'काश मैं फिर से जवान होता।' अगर वृद्धावस्था इतनी मूल्यवान होती, तो लोग हमेशा यह क्यों कहते? यह क्या दर्शाता है? असंतुष्ट जीवन। अधूरा जीवन। ऐसा जीवन, जिसे कोई अर्थ नहीं मिला। अगर आपको अपने जीवन में अर्थ मिल गया है, तो आप पीछे नहीं लौटना चाहते। आप आगे बढ़ना चाहते हैं। आप और दुनिया देखना चाहते हैं, और काम करना चाहते हैं। आप किसी उम्र में रुकना नहीं चाहते, बल्कि आगे निरंतर बढ़ना चाहते हैं। सभी को यह पता होना चाहिए कि अगर हम हमेशा बुजुर्ग होने से जूझते रहेंगे, तो हमेशा दुखी ही रहेंगे, क्योंकि यह तो वैसे भी होगा ही। सच तो यह है कि हम सभी अंततः मर जाएंगे।

मिच एल्बॉम

मुड़-मुड़ के देख

मैंने एक बार मॉरी से पूछा कि क्या उन्हें कभी युवा और स्वस्थ लोगों से ईर्ष्या होती है? मॉरी का जवाब था कि उम्र कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। उन्होंने कहा कि वह हर उस उम्र में हैं, जो उन्होंने कभी जी है, और चूंकि उन्होंने पहले ही युवावस्था का अनुभव कर लिया है, इसलिए उससे ईर्ष्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बुजुर्गों के पास वे सभी उम्र होती हैं, जो युवा लोग अभी प्राप्त नहीं कर पाए हैं। जिन्होंने जीवन को सही मायने में जिया, वे जानते हैं कि हर उम्र का अपना सौंदर्य है।

एक व्यक्ति अपने जीवनकाल में सभी प्रकार के अनुभव प्राप्त करता है और ये अनुभव उसे एक पूर्ण और सार्थक जीवन की ओर ले जाते हैं। यदि कोई एक ही उम्र में रहना चाहेगा, तो जीवन कभी सार्थक नहीं होगा। उसे हमेशा असंतुष्टि घेरे रहेगी। जैसे-जैसे आप बड़े होते हैं, आप और सीखते हैं। बीस-बाईस साल की उम्र में आप जितने अज्ञानी थे, उतने ही अज्ञानी बने रहते, यदि आप हमेशा उसी उम्र में रहते। वृद्धावस्था क्षय नहीं है, बल्कि यह विकास है। यह इस नकारात्मकता से कहीं बढ़कर है कि आप मरने वाले हैं, यह इस सकारात्मकता से कहीं बढ़कर है कि आप समझते हैं कि आप मरने वाले हैं, और इसलिए आप बेहतर जीवन जीते हैं। यह समय का अनोखा रूप है।

दूसरी पारी

सुख स्वाद में नहीं, आपके भीतर है

वाराणसी के 65 वर्षीय प्रेम शंकर के भोजन में स्वाद न आने की समस्या पर मनोविज्ञानी नीलकंठ ने उन्हें समझाया

मैं हमेशा से ही खाने-पीने का शौकीन रहा हूं, लेकिन पिछले कुछ समय से महसूस कर रहा हूं कि इसमें स्वाद आना कम हो गया है। क्या करूं?

वैसे तो उम्र बढ़ने के साथ सभी इंद्रियां कमजोर होने लगती हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इनमें से स्वाद इंद्रिय से जुड़ी समस्याएं बुजुर्गों में सबसे आम हैं। हाल ही में हुआ एक शोध बताता है कि तकरीबन तीन-चौथाई बुजुर्गों को किसी अन्य कमजोरी के बजाय स्वाद लेने से जुड़ी परेशानी अधिक पाई जाती है। इसलिए आपको इसको लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप यह समझ लें कि स्वाद लेने की क्षमता का ह्रास तो सबमें होता है, लेकिन यह इतना धीरे-धीरे होता है कि अमूमन लोगों को पता नहीं चल पाता।

कई बार तो युवाओं को भी यह समस्या आ जाती है। एक रोचक तथ्य यह भी है कि जिन लोगों को यह समस्या होती है, उन्हें भी पहले सूंघने की क्षमता में कमी आने का पता चलता है, क्योंकि ज्यादातर स्वाद का पहला संबंध गंध से ही होता है। कई बार स्वाद न आने की वजह से कुछ लोगों की भूख कम हो जाती है और वे कमजोर हो सकते हैं। कुछ लोग स्वाद बढ़ाने के लिए नमकीन, मीठे और वसायुक्त पदार्थों का सेवन करते हैं, जिससे टाइप 2 मधुमेह और हृदय रोग जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। आप ऐसा बिल्कुन न करें, क्योंकि ऐसा करने पर आप दूसरी कई बीमारियों को आमंत्रित कर लेंगे।

आपने यह नहीं बताया कि आपमें अवसाद जैसे कुछ लक्षण तो नहीं, क्योंकि स्वाद और गंध की कमी की समस्या अवसाद की देन भी हो सकती है, क्योंकि ये इंद्रिया दिमाग के भावनात्मक परिपथों से जुड़ी होती हैं। मसलन, भोजन अक्सर संस्कृति, परिवार और पहचान से जुड़ा होता है। अगर आपमें ऐसे कोई लक्षण हैं, तो कृपया तुरंत चिकित्सक से सलाह लें।

कई बार मसूड़ों, दांतों या जीभ के संक्रमण व सफाई संबंधी समस्याएं भी स्वाद ग्रंथि को कमजोर कर देती हैं। इसलिए, जरूरी है कि आप खूब पानी पिएं और जीभ की सफाई पर खास ध्यान दें। एक उम्र के बाद स्वाद और गंध से जुड़ी इंद्रियों में कुछ समस्याएं आना स्वाभाविक है। 60 की उम्र के बाद स्वाद कलिकाओं और गंध ग्राहियों की संख्या कम हो जाती है, क्योंकि आपका शरीर उन्हें पुनर्जीवित करने की क्षमता खो देता है। कई बार टाइप 2 डाइबिटीज, स्ट्रोक, अल्जाइमर और पर्किंसन जैसी बीमारियां और ब्लड प्रेशर की कुछ दवाएं भी स्वाद व गंध से जुड़ी परेशानियां पैदा करती हैं। अपनी इंद्रियों की क्षमताओं को बढ़ाने का एक प्राकृतिक उपाय प्राणायाम हो सकता है, जिसका अभ्यास आप यथासंभव रोज कर सकते हैं। एक बात और, भोजन जो दिखने में स्वादिष्ट लगे, वह स्वाद बढ़ा सकता है। भोजन में अतिरिक्त नमक या चीनी मिलाकर खाने से बचें, क्योंकि इससे उल्टा नुकसान ही होगा। ध्यान रखें, भोजन से हमें सुख मिलता है और यह सुख स्वाद या गंध से कम आपकी मनोदशा पर ज्यादा निर्भर करता है। इसलिए, हर हाल में खुश रहें।

*जिंदगी की **दूसरी पारी** बहुत महत्वपूर्ण होती है। हर शुक्रवार इस पर आपको नया पढ़ने को मिलेगा। आप अपने विचार, अनुभव या समस्याएं edit@amarujala.com पर भेज सकते हैं, विशेषज्ञों की मदद से हम कोशिश करेंगे कि संवाद का पुल बन सके।*

68 साल की दादी और स्केटबोर्डिंग

चीन की 68 वर्षीय दादी लियू के स्केटबोर्डिंग करते हुए वीडियो इंटरनेट पर धूम मचा रहे हैं। उन्होंने बेटी के साथ पार्क में छोटी-छोटी ट्रिक्स सीखीं और वीडियो शेयर किए। बड़ी उम्र के बावजूद बिना डर के उनका स्केटिंग करना लाखों लोगों को प्रेरित कर रहा है। दादी कहती हैं कि युवा हो या बुजुर्ग, सबको कुछ नया सीखने की कोशिश करनी चाहिए। बुजुर्गों के साथ ही युवा भी उनसे मिलकर प्रेरित हो रहे हैं। कई बुजुर्गों ने तो दादी से प्रेरणा लेकर खेलना शुरू कर भी दिया है।

वरिष्ठ नागरिकों के

काम की योजना

बुजुर्गों की सुरक्षा

उत्तर प्रदेश पुलिस की 'सवेरा योजना' बुजुर्गों को सुरक्षा प्रदान करती है। यूपी-112 पर कॉल कर या https://112.up.gov.in/registration पर पंजीकरण कराकर वरिष्ठ नागरिक सहायता ले सकते हैं। बुजुर्गों को जरूरत पड़ने पर निकटतम पुलिस थाने की पुलिस या पुलिस रिस्पांस व्हीकल पहुंचकर उन्हें सहायता प्रदान करते हैं। वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु जिला स्तर और प्रत्येक थाने में एक विशेष वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ का भी गठन किया गया है।

वृद्धों का समग्र कल्याण

वृद्धकेयर फाउंडेशन वृद्धों के समग्र कल्याण पर ध्यान केंद्रित करता है। यह वृद्धाश्रम में देखभाल करने वालों को प्रशिक्षित करने के साथ ही आंखों के इलाज, सरकारी और सामाजिक सेवाओं से बुजुर्गों को लाभान्वित करवाता है। आधिकारिक वेबसाइट पर https://www.vridhcare.com/ पर सहायता व जानकरी के लिए जाएं या हेल्पलाइन 8700851044 पर संपर्क कर इसका लाभ ले सकते हैं।

जीआईएम में पीजी मैनेजमेंट में कैट, जीमैट स्कोर से दाखिले

शैक्षणिक सत्र 2026-29 के लिए नामांकन की घोषणा

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (जीआईएम) ने शैक्षणिक सत्र 2026-29 बैच के लिए पोस्ट ग्रेजुएट मैनेजमेंट प्रोग्राम में दाखिले की घोषणा कर दी है। विभिन्न पीजी मैनेजमेंट प्रोग्राम में कैट 2025, एक्सएटी 2026 और जीमैट स्कोर के आधार पर दाखिला मिलेगा। इच्छुक अभ्यर्थी 23 अक्तूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

संस्थान के निदेशक प्रो. अजीत पारुलेकर ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2026-29 बैच के लिए पीजी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट (पीजीडीएम), पीजीडीएम हेल्थकेयर मैनेजमेंट (एचसीएम), पीजीडीएम बिंग डेटा एनालिटिक्स (बीडीए), पीजीडीएम बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड फाइनिशियल सर्विसेस (बीआईएफएस), इंटरनेशनल डबल डिग्री इन एनालिटिक्स (आईडीए) और पीजीडीएम बीडीए और एमएससी इन एनालिटिक्स प्रोग्राम में दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गई है। सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए स्नातक में 50% अंक तो आरक्षित वर्ग के लिए 45% अंक होने जरूरी हैं। स्नातक प्रोग्राम में अंतिम वर्ष के छात्र भी आवेदन कर सकते हैं।

इन पाठ्यक्रमों में सीट कैट, जीमैट, मैट, सीएमएटी जैसी राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं की मेरिट के आधार पर मिलेगी। इसके अलावा संस्थान अपना जीआईएम एनालिटिक्स एप्टीट्यूड टेस्ट का भी आयोजन करता है। सीट अकादमिक प्रदर्शन, प्रवेश परीक्षा के स्कोर, और अन्य पाठ्येतर गतिविधियों के आधार पर मिलेगी। इसके लिए दो चयन राउंड होंगे, जिसमें अचीवर्स राउंड (अकादमिक और पाठ्येतर उपलब्धियों पर आधारित) और पर्सेंटाइल राउंड (प्रवेश परीक्षा स्कोर पर आधारित)। अधिक जानकारी के लिए छात्र संस्थान की वेबसाइट पर है।

एनएमएमएस के तहत 1,450 ने भरे आवेदन

फरीदाबाद। नेशनल मीन्स-कम-मेरिट स्कॉलरशिप (एनएमएमएस) योजना के तहत जिलेभर के विद्यार्थियों ने आवेदन किए। बुधवार रात 12 बजे तक आवेदन भरने की अंतिम तिथि रही। अब तक 1,450 विद्यार्थियों ने आवेदन जमा करवाए। पानीपत में सर्वाधिक 4,207 आवेदन हुए हैं। यह उपलब्धि जिले के सभी शिक्षा अधिकारियों, शिक्षकों और विद्यार्थियों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। साथ ही गुरुग्राम में 3,395, नूंह में 1,885 और पलवल में 1,521विद्यार्थियों ने आवेदन किए हैं। इस बार विभाग का लक्ष्य था कि जिले के सभी मिडिल, हाई और सीनियर सेकेंडरी विद्यालयों से आवेदन करवाए जाएं, ताकि कोई भी पात्र विद्यार्थी इस छात्रवृत्ति योजना से वंचित न रहे। संवाद

डीयू में विदेशी छात्रों के लिए नए नियमों पर जागरूकता कार्यक्रम

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के विदेशी छात्र रजिस्ट्री ने वाइस-रीगल लॉज के कन्वेंशन हॉल में विदेशी छात्रों के लिए नए नियम और प्रक्रियाएं विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इसकी अध्यक्षता कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने की, जबकि आईपीएस अधिकारी और विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी (एफआरआरओ) दीपक यादव विशिष्ट अतिथि रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य विदेशी छात्रों के प्रवेश, पंजीकरण, वीजा नियमों और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी देना था।

प्रो. योगेश सिंह ने बताया कि डीयू उच्च शिक्षा में विदेशी छात्रों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने इस आयोजन को सभी के लिए उपयोगी बताया। वहीं, दीपक यादव ने अपनी प्रस्तुति में नए अप्रवासन व विदेशी अधिनियम, 2025 और नियमों की जानकारी दी। उन्होंने वीजा श्रेणियों, पंजीकरण और अनुपालन से जुड़े नियमों को भी समझाया। ब्यूरो

हिंदू कॉलेज पहुंचीं श्रीलंका की पीएम, पुराने दिन किए याद

प्रधानमंत्री डॉ. हरिणी अमरसूर्या ने प्रश्नोत्तर सत्र में लिया हिस्सा, शैक्षिक यात्रा व अनुभव साझा किए

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। हिंदू कॉलेज ने अपनी पूर्व छात्रा और श्रीलंका की प्रधानमंत्री डॉ. हरिणी अमरसूर्या के स्वागत में बृहस्पतिवार को समारोह का आयोजन किया। यह अवसर कॉलेज के लिए गर्व और पुरानी यादों से भरा रहा, क्योंकि डॉ. अमरसूर्या उस संस्थान में लौटीं जहां से उनकी नेतृत्व और शिक्षा की यात्रा शुरू हुई थी।

प्रधानमंत्री का स्वागत 16 एनसीसी कैडेट्स की टुकड़ी द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर के साथ किया गया। इस विशेष अवसर पर औपचारिक वृक्षारोपण समारोह हुआ। डॉ. अमरसूर्या ने गवर्निंग बॉडी, ट्रस्ट और परोपकारी सदस्यों, समाजशास्त्र विभाग के शिक्षकों और छात्रों अपनी समकालीन सहपाठियों, साथ ही कॉलेज संसद के छात्र नेताओं के साथ समूह चित्र खिंचवाए।

कार्यक्रम में दीप प्रज्ज्वलित करतीं श्रीलंका की प्रधानमंत्री। अमर उजाला

कॉलेज की प्राचार्य प्रो. अंजू श्रीवास्तव ने कहा कि आपकी घर वापसी हमें याद दिलाता है कि इस कॉलेज की दीवारों में बोए गए ज्ञान के बीज नेतृत्व, दृष्टिकोण और सेवा के रूप में देशों और पीढ़ियों तक फलते-फूलते हैं। प्रो. श्रीवास्तव ने कॉलेज के विकास पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जब आपने कॉलेज में प्रवेश लिया था, तब यहां लगभग 1500 छात्र थे, जो अब बढ़कर 4500 से अधिक हो गए हैं। पिछले 12 वर्षों में 1,90,000 वर्ग फुट से अधिक स्थान जोड़ा गया है।

प्रधानमंत्री डॉ. अमरसूर्या ने हिंदू कॉलेज में बिताए दिनों को याद किया और छात्रों व शिक्षकों के साथ एक इंटरेक्टिव प्रश्नोत्तर सत्र में हिस्सा लिया। उन्होंने अपनी शैक्षिक यात्रा और अनुभवों को साझा किया।

उन्होंने कॉलेज का एक संक्षिप्त दौरा किया, जिसमें कक्षा नंबर 27 भी शामिल था, जहां उन्होंने अपने छात्र जीवन के दिन बिताए थे। उन्होंने मौजूदा छात्रों से बातचीत की और उन्हें प्रोत्साहित किया।

डॉ. अमरसूर्या ने कॉलेज के स्किल ट्रेनिंग फैसिलिटी परफ्यूमरी लैब और सामाजिक एवं नृवंशविज्ञान अनुसंधान प्रयोगशाला का भी दौरा किया, जिसका नाम उनके सम्मान में रखा जाएगा।

कैंपस डायरी

कॉलेजों को 108 करोड़ सहायता के फैसले का एबीवीपी ने किया स्वागत

नई दिल्ली। एबीवीपी ने दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 वित्तपोषित कॉलेजों को 108 करोड़ रुपये के वित्तीय सहयोग देने के निर्णय का स्वागत किया है। एबीवीपी का मानना है कि यह निर्णय दिल्ली के उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण व सकारात्मक पहल है। इस निर्णय से डीयू के 12 वित्तपोषित कॉलेजों की अकादमिक स्थिति में सुधार होगा। वहां कार्यरत अध्यापक व कर्मचारियों को भी बड़ी राहत मिलेगी। इस कदम से इन कॉलेजों की वित्तीय और शैक्षणिक स्थिति दोनों ही मजबूत होंगी। एबीवीपी दिल्ली के प्रांत मंत्री सार्थक शर्मा ने कहा कि दिल्ली सरकार का यह निर्णय लंबे समय से चली आ रही वित्तीय समस्याओं को दूर करने की दिशा में सराहनीय कदम है। ब्यूरो

श्री अरबिंदो कॉलेज में दीपावली मंगल मिलन समारोह में नुक्कड़ नाटक का जलवा

नई दिल्ली। डीयू के श्री अरबिंदो कॉलेज में बृहस्पतिवार को दीपावली मंगल मिलन समारोह और मेले का आयोजन किया गया। कॉलेज परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों ने बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लिया। मेले में लोकनृत्य, नुक्कड़ नाटक और ग्रीन दीपावली का प्रदर्शन मुख्य आकर्षण रहा। साथ ही, छात्रों ने जरूरतमंद बच्चों और उनके परिवारों के लिए कपड़ों का दान भी इकट्ठा किया, जिसे जल्द ही झुग्गी बस्तियों में बांटा जाएगा। मेले का उद्घाटन कॉलेज के प्राचार्य प्रो. अरुण चौधरी ने किया। इस अवसर पर प्रो. चौधरी ने कहा कि दीपावली मेला प्राचीन भारतीय संस्कृति और परंपराओं को जीवंत करता है। ब्यूरो

कार्यक्रम में मौजूद लोग। अमर उजाला

जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज के नए कैंपस के लिए मांगा फंड

अमर उजाला ब्यूरो

ओखला में 426 करोड़ की लागत से बनने वाला एकीकृत कैंपस एक साल से ठप

नई दिल्ली। जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलीटेक्निक का ओखला में प्रस्तावित एकीकृत कैंपस अधर में लटका हुआ है। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने इस परियोजना को फिर से शुरू करने के लिए सरकार से फंड की मांग की है।

करीब 22 एकड़ क्षेत्र में बनने वाले इस कैंपस की अनुमानित लागत लगभग 426 करोड़ रुपये है। परियोजना को 2019 में स्वीकृति मिली थी और निर्माण कार्य 2024 में शुरू किया गया था लेकिन पर्याप्त फंड की कमी और पेड़ों की कटाई की अनुमति दोबारा मिलने में देरी से पिछले साल से काम ठप है। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद किसी भी परियोजना में 50 से अधिक पेड़ काटने के लिए मंजूरी जरूरी है। विभाग को पहले 2021 में वन विभाग और वृक्ष अधिकारी से अनुमति मिल चुकी थी लेकिन अब उस अनुमति की फिर से मान्यता करानी पड़ रही है। परियोजना के तहत आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक बड़ा कैंपस विकसित किया जाना है जिसमें प्रशासनिक ब्लॉक, दो शैक्षणिक भवन, 10 मंजिला छात्रावास, कार्यशालाएं और गतिविधि केंद्र शामिल होंगे।

साथ ही, कैंपस में सौर ऊर्जा संयंत्र, अग्निशमन प्रणाली, जल निकासी व्यवस्था और 16 यात्री लिफ्ट लगाने की योजना भी है। पहले चरण में छह मंजिला प्रशासनिक ब्लॉक और आठ-आठ मंजिल वाले दो शैक्षणिक ब्लॉक बनाए जाने हैं। दूसरे चरण में बाकी इमारतों और छात्र आवासों का निर्माण होगा। बजट स्वीकृत होते ही काम फिर से शुरू किया जा सकता है।

छात्रों को बताया स्वदेशी का महत्व

फरीदाबाद। सराय ख्वाजा स्थित गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बृहस्पतिवार को बिल्डथॉन 2025 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार और प्रसार हेतु इनोवेशन के लिए प्रेरणा दी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने और भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सभी को प्रोत्साहित करना है। प्राचार्य रविंद्र कुमार मनचंदा ने बताया कि बिल्डथॉन केवल एक प्रतियोगिता नहीं है बल्कि एक राष्ट्रीय आंदोलन है। संवाद

डीयू में कानून की पढ़ाई कर रहे छात्रों ने जाना विधानसभा का इतिहास

विधानसभा अध्यक्ष ने लॉ सेंटर-2 के छात्रों से किया विधानसभा परिसर में संवाद

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने डीयू में कानून की पढ़ाई कर रहे छात्रों को विधानसभा के इतिहास से रूबरू कराया। विधायी प्रक्रिया और संवैधानिक ढांचे के बारे में जानकारी दी। छात्रों ने अध्यक्ष के साथ विधानसभा सदन का भी भ्रमण किया।

विजेंद्र गुप्ता ने विधानसभा भवन के ऐतिहासिक महत्व को समझाते हुए बताया कि 1912 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। तब पुराना सचिवालय भवन केंद्रीय विधानसभा के रूप में काम करता था। लुटियंस दिल्ली के तैयार होने से पहले यहीं से देश की विधायी गतिविधियां चलती थीं। उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय और विट्ठलभाई पटेल जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान बताए, जिन्होंने भारत की लोकतांत्रिक परंपरा की मजबूत नींव रखी।

1993 में पहली बार दिल्ली में बनी निर्वाचित विधानसभा

विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि विधानसभा परिसर करीब 22 एकड़ में फैला है और यह देश के सबसे बड़े विधान परिसरों में से एक है। उन्होंने दिल्ली को मिले विशेष संवैधानिक दर्जे की जानकारी दी। बालकृष्णन समिति की सिफारिशों के आधार पर अनुच्छेद 239 (एए) जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत दिल्ली को 70 सदस्यों वाली विधानसभा का दर्जा मिला। उन्होंने बताया कि 1993 में दिल्ली में पहली बार निर्वाचित विधानसभा का गठन हुआ था।

गोवर्धन विद्या निकेतन में मनाई डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती

पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के बलबीर नगर विस्तार स्थित श्री गोवर्धन विद्या निकेतन विद्यालय में बुधवार को पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती मनाई गई। इस दौरान अतिथि के रूप में प्रख्यात कवि संजय गिरी, जोशीला टाइम्स सह संपादक योगेश कौशिक, विद्यालय प्रबंधक विष्णु दत्त शर्मा समेत विद्यालय के बच्चों व शिक्षकों ने डॉ. अब्दुल कलाम के चित्र के समक्ष नमन किया। कार्यक्रम में बच्चों ने डॉ. अब्दुल कलाम के संघर्षमयी जीवन को अपने शब्दों में व्यक्त किया। विद्यालय प्रबंधक विष्णु दत्त शर्मा ने बताया डॉ. अब्दुल कलाम का जीवन बेहद गरीबी से गुजरा, लेकिन शिक्षा के प्रति उनकी लगन मेहनत ने उनको देश का राष्ट्रपति ही नहीं दुनिया का सबसे शक्तिशाली वैज्ञानिक बनाया। ब्यूरो

शिक्षक पर हमला, डीटीएफ ने की निंदा

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। डीयू के भीम राव अंबेडकर कॉलेज में डीयू स्टूडेंट्स यूनियन की संयुक्त सचिव दीपिका झा और एबीवीपी के सदस्यों पर एक शिक्षक पर हमला करने का आरोप लगा है। डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट ने इस घटना की निंदा की है।

आरोप है कि दीपिका झा ने प्रो. सुजीत कुमार को थप्पड़ मारा और कई अन्य शिक्षकों के साथ धक्का-मुक्की की। प्रो. सुजीत अनुशासन समिति के संयोजक हैं, जो एबीवीपी सदस्यों द्वारा छात्रों पर हमले की जांच कर रहे थे। डूसू अध्यक्ष और संयुक्त सचिव सहित लगभग 50 छात्र कॉलेज में जबरन घुसे, शिक्षकों से बदतमीजी की और प्रो. सुजीत से इस्तीफा मांगा। प्राचार्य के कार्यालय में हुई इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध है।

इस घटना से आहत होकर अनुशासन समिति के सभी सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। डीटीएफ ने कहा कि यदि शिक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होगी तो वे अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाएंगे। डीटीएफ ने विश्वविद्यालय प्रशासन से तत्काल जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।

डीयू के अंबेडकर कॉलेज में वरिष्ठ शिक्षक पर हमला, कार्रवाई की मांग : नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के बीआर अंबेडकर कॉलेज में चौकाने वाली घटना सामने आई है। आरोप है कि कुछ छात्रों ने कॉलेज परिसर में एक वरिष्ठ शिक्षक के साथ मारपीट की है। आरोप के अनुसार, शिक्षक अपनी ड्यूटी पर थे तभी उन पर यह हमला हुआ। डीयू के कार्यकारी परिषद के सदस्य राजपाल सिंह पवार, वित्त समिति के सदस्य जेएल गुप्ता, डूटा सचिव बीमालेंदु तीर्थंकर आदि ने कुलपति प्रो. योगेश सिंह को पत्र लिखकर इस घटना की तत्काल जांच और दोषी छात्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

हरियाणा सरकार — निविदा सूचना

क्र. सं.	बोर्ड/निगम/ प्राधि. का नाम	कार्य सूचना निविदा का नाम	आरंभिक तिथि अंतिम तिथि (समय)	राशि/ ईएमडी (अनुमानित) रु. में	बोर्ड/निगम प्राधि. की वेबसाईट	नोडल अधिकारी /संपर्क जानकारी/ईमेल
1	नगर निगम रोहतक	वार्ड सं. 21 एमसी रोहतक में आजाद सिंह के मकान से सुरेश के मकान तक अमृत कालानी में आईपीबी टाइल्स गली एवं राम बहादुर मिस्त्री के मकान से जगदीश के मकान तक एवं सतबीर एएसआई के मकान से राम अवतार के मकान तक एवं मुकेश रोहिला के मकान तक सीसी का निर्माण+8 कार्य।	15.10.2025 23.10.2025	Rs. 185.91 LACS	https://etenders.hry.nic.in	9467283967 xenmcrohtak@gmail.com
2	नगर निगम रोहतक	राधे-राधे पार्क, वार्ड नं.6, एम.सी. रोहतक का सौंदर्यकरण एवं प्रोन्नयन+4 कार्य।	15.10.2025 23.10.2025	Rs. 54.61 LACS	https://etenders.hry.nic.in	9467283967 xenmcrohtak@gmail.com

अग्रिम जानकारी हेतु कृपया वेबसाईट www.haryanaeprocurement.gov.in या www.etenders.hry.nic.in पर जाएं।

SAMVAD:-13/2026/40/39540/I/1/7 Dt.16/10/2025

हरियाणा सरकार — निविदा सूचना

क्र. सं.	विभाग का नाम	कार्य सूचना निविदा का नाम	आरंभिक तिथि अंतिम तिथि	राशि/ईएमडी (अनुमानित) रु. में	विभाग की वेबसाईट	नोडल अधिकारी/ संपर्क जानकारी/ ईमेल
1	लोनिवि भवमा, पलवल	प्रान्तीय उप-मंडल, लोनिवि भवमा शाखा, हथिन में विभिन्न सड़कों के वार्षिक रखरखाव हेतु सामग्री का अग्रिम एकत्रीकरण (हथिन में लोनिवि स्टोर पर सामग्री का एकत्रीकरण) वर्ष 2025-26 हेतु (जीएसटी के बगैर)+2 कार्य।	CLOSING DATE 21.10.2025	12.48 LACS	https://etenders.hry.nic.in	9466219169 pwd-eepd- palwal@hry.nic.in
2	लोनिवि भवमा, करनाल	गांव मोहाना जिला सोनीपत में राजकीय महाविद्यालय का निर्माण (केवल ईएलवी सेवाओं का प्रावधान)+1 कार्य।	16.10.2025 27.10.2025	239.65 LACS	https://etenders.hry.nic.in	01842265696 pwd-eeed- karnal@hry.nic.in
3	महानिदेशक, आपूर्ति एवं निपटान पंचकूला, हरियाणा	मदों का विवरण : क्रम सं.1 से 04 मदों तक, शामिल सूची (04 मदों का एकल लॉट)	16.10.2025 12.11.2025		https://etenders.hry.nic.in dsndharyana.gov.in	0172-2570122 Supplies@hry.nic.in
4	महानिदेशक, आपूर्ति एवं निपटान पंचकूला, हरियाणा	मदों का विवरण : क्रम सं.1 से 05 मदों तक, शामिल सूची (05 मदों का एकल लॉट)	16.10.2025 12.11.2025		https://etenders.hry.nic.in dsndharyana.gov.in	0172-2570122 Supplies@hry.nic.in
5	महानिदेशक, आपूर्ति एवं निपटान पंचकूला, हरियाणा	मदों का विवरण : क्रम सं.1 से 06 मदों तक, शामिल सूची (06 मदों का एकल लॉट)	16.10.2025 12.11.2025		https://etenders.hry.nic.in dsndharyana.gov.in	0172-2570122 Supplies@hry.nic.in
6	महानिदेशक, आपूर्ति एवं निपटान पंचकूला, हरियाणा	मदों का विवरण : क्रम सं.1 से 09 मदों तक, शामिल सूची (09 मदों का एकल लॉट)	16.10.2025 12.11.2025		https://etenders.hry.nic.in dsndharyana.gov.in	0172-2570122 Supplies@hry.nic.in
7	महानिदेशक, आपूर्ति एवं निपटान पंचकूला, हरियाणा	मदों का विवरण : क्रम सं.1 से 34 मदों तक, शामिल सूची (34 मदों का एकल लॉट)	16.10.2025 12.11.2025		https://etenders.hry.nic.in dsndharyana.gov.in	0172-2570122 Supplies@hry.nic.in
8	महानिदेशक, आपूर्ति एवं निपटान पंचकूला, हरियाणा	मदों का विवरण : क्रम सं.1 से 29 मदों तक, शामिल सूची (29 मदों का एकल लॉट)	16.10.2025 12.11.2025		https://etenders.hry.nic.in dsndharyana.gov.in	0172-2570122 Supplies@hry.nic.in
9	पंचायती राज अम्बाला	गांव जटवार में कब्रिस्तान की सीमा दीवार का निर्माण तथा गांव बारी-बसी में सामुदायिक हाल की सीमा दीवार का निर्माण।	14.10.2025 23.10.2025	9.07 LACS	https://etenders.hry.nic.in	0171-2551368 prexeeng.amb@hry.nic.in
10	पंचायती राज अम्बाला	डी प्लान गांव लौटांव, ब्लॉक नरायणगढ़ में बीसी चौपाल का निर्माण तथा गांव राज्जु माजरा में एससी चौपाल का निर्माण।	15.10.2025 23.10.2025	13.04 LACS	https://etenders.hry.nic.in	0171-2551368 prexeeng.amb@hry.nic.in
11	पंचायती राज पंचकूला	गणेशपुर भोरियां-गांव गणेशपुर भोरिया, ब्लॉक पिंजौर, जिला पंचकूला में सामुदायिक केन्द्र का निर्माण।	14.10.2025 20.10.2025	57.26 LACS	https://etenders.hry.nic.in	9416915374 prexeeng.pkl@hry.nic.in
12	बागवानी गुआवा डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर भूना फतेहाबाद	सीईजी, भूना (फतेहाबाद) में ऑटोमेशन युनिट एवं माईक्रो इरीगेशन सिस्टम का संस्थापन तथा आपूर्ति हेतु ई-निविदा सूचना का प्रकाशन।	17.10.2025 06.11.2025	75000/-	https://etenders.hry.nic.in	9896389920 ddhbhuna@gmail.com

अधिक जानकारी हेतु कृपया वेबसाईट www.etenders.hry.nic.in पर जाएं।

PRDH : -11/2026/240/39526/I/1/7 Dt. 16/10/2025

शांति का मतलब संघर्ष की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि इससे निपटने की क्षमता है। -महात्मा गांधी

अहमदाबाद से आशा

भारत के खेल इतिहास में एक और नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। दरअसल, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ की कार्यकारी समिति ने 2030 में होने वाले सौवें राष्ट्रमंडल खेलों के प्रस्तावित मेजबान शहर के रूप में अहमदाबाद के नाम की सिफारिश की है, जो देश के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण होने के साथ वैश्विक स्तर पर भारत की उभरती हुई ताकत का भी प्रतीक है। इस बाबत अंतिम निर्णय 26 नवंबर, 2025 को ग्लासगो में होने वाली महासभा में लिया जाएगा, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि यह मात्र औपचारिकता ही होगी। उल्लेखनीय है कि इस आयोजन के लिए नाइजीरिया की राजधानी अबुजा की तरफ से भी आवेदन मिला था, लेकिन एक व्यापक प्रक्रिया के तहत दोनों शहरों के प्रस्तावों का मूल्यांकन किया गया, जिसमें अहमदाबाद ने अपनी अत्याधुनिक सुविधाओं, विविधता और ऊर्जावान दृष्टिकोण से सभी को प्रभावित किया। गौरतलब है कि भारत ने पिछली बार 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी, जो खराब योजना, बुनियादी ढांचे के निर्माण में देरी और भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण प्रभावित हुआ था। लेकिन तब से देश की स्थितियों में काफी बदलाव आए हैं और खेलों में भी हमारी स्थिति मजबूत हुई है। 2022 के बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भारत कुल 61 पदक जीतकर तालिका में चौथे पायदान पर रहा था। अहमदाबाद में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन देश की खेल प्रतिभाओं को तो प्रोत्साहित करेगा ही, इसके साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने, पर्यटन को प्रेरित करने और गुजरात की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पटल पर उजागर करने का भी कार्य करेगा। हालांकि, यह सब इतना आसान नहीं होगा। दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन के दौरान सामने आई संगठनात्मक खामियों से सबक लेते हुए अहमदाबाद को पारदर्शी व कुशल प्रबंधन पर ध्यान देना होगा। आयोजन की लागत को नियंत्रित रखने, पर्यावरण का ख्याल रखते हुए बुनियादी ढांचों का विकास करने और समावेशी भागीदारी सुनिश्चित करने की चुनौतियां भी होंगी। ऐसे में, आयोजन को कामयाब बनाने के लिए सरकार, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज को मिलकर काम करने की जरूरत है। यह भी सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है कि आयोजन की तैयारियों का आधार सतत विकास के मॉडल पर हो, ताकि बुनियादी ढांचे का उपयोग खेलों के बाद भी हो सके। अगर भारत इस मंच पर अपनी क्षमता दिखाता है, तो इससे एशियाई और ओलंपिक स्तर के आयोजनों के लिए भी एक विश्वसनीय मेजबान देश के रूप में उसकी स्थिति मजबूत होगी।

ट्रंप अभी चैन से नहीं बैठ सकते

इस्राइल-हमास युद्ध विराम का जैसा बखान ट्रंप कर रहे हैं, मैं उनके पक्ष या विपक्ष में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मुमकिन है कि वह सही राह पर हों। लेकिन उन्हें यह सलाह जरूर दी जा सकती है कि चूंकि हमास ने अब तक हथियार छोड़े नहीं हैं, इसलिए उन्हें तेजी-से आगे बढ़ते हुए कुछ निर्णायक जोखिम उठाने होंगे।

थॉमस एल फ्रीडमैन
द न्यूयॉर्क टाइम्स

सोमवार को राष्ट्रपति ट्रंप जब इस्राइलियों और अरबों से यह कह रहे थे कि हम अभी पश्चिम एशिया में ऐतिहासिक सुबह देख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा था, जैसे ट्रंप अपने बैंकरों को एक जहरीले कचरे के ढेर पर दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे सुंदर, सबसे शानदार होटल बनाने की योजना के बारे में बता रहे हों। ऐसे में दिमाग में बस यही आता है कि क्या उन्हें इस जगह के इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता? आप यहां होटल बना ही नहीं सकते। लेकिन दूसरे ही क्षण ख्याल आता है कि अगर उन्होंने यह कर दिखाया तो? धमकाने, चापलूसी करने और बढ़ा-चढ़ाकर बात कहने की ट्रंप की क्षमता वास्तव में देखने लायक है, और यह सोमवार को इस्राइली संसद में तथा उसके बाद मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित एक सभा में 20 से अधिक विश्व नेताओं के समक्ष दिए गए उनके भाषण में दिखी।

कोई भी पारंपरिक राजनयिक या विदेश नीति का प्रोफेसर राष्ट्रपति को ऐसे जोखिम उठाने की सलाह नहीं देता कि वह घोषणा करें कि हम पश्चिम एशिया में शांति की राह पर हैं और डोनाल्ड ट्रंप उस शांति बोर्ड की अध्यक्षता करेंगे, जो इसे लागू करेगा। दरअसल, ट्रंप की पढ़ाई एक बिजनेस स्कूल में हुई है, न कि विदेश सेवा के स्कूल में। उन्हें यकीन है कि वह येन-केन-प्रकारेण इस संघर्ष को एक सुखद अंत तक पहुंचा सकते हैं। इस मामले में, मैं उनके पक्ष या विपक्ष में दांव नहीं लगा सकता, लेकिन उन्हें एक मुफ्त सलाह जरूर दूंगा कि राष्ट्रपति महोदय, इस सौदे को पूरा करने के लिए आपको तेजी से आगे बढ़ना होगा और कुछ जोखिम उठाने होंगे। लेकिन अब तक इस दिशा में कुछ होता नहीं दिखता।

बेशक अभी समय है, लेकिन अभी तो मुझे अगले चरण की कोई शुरुआत भी नजर नहीं आ रही। संयुक्त राष्ट्र का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, जो एक उचित फलस्तीनी सुरक्षा बल का गठन होने तक गाजा में हमास के निरस्त्रीकरण और सुरक्षा की निगरानी के लिए अरब/अंतरराष्ट्रीय शांति सेना बनाने की बात करे। गाजा के पुनर्निर्माण के लिए जरूरी अरबों डॉलर की

धनराशि भी नहीं दिखती, और यह भी नहीं पता कि फलस्तीनी टेक्नोक्रेटों के मंत्रिमंडल की नियुक्ति और प्रबंधन कौन करेगा, जो हमास के बदले गाजा को चलाएंगे। एक पत्रकार होने के नाते, अगर मैं जानना चाहूं कि आगे क्या और कैसे होगा, तो मुझे समझ नहीं आता कि किससे बात करूं। यह मुसीबत का कारण है। जिस चीज ने बंधकों की रिहाई, कैदियों की अदला-बदली और युद्धविराम जैसी बड़ी सफलताएं दिलाईं, उससे पश्चिम एशिया में व्यापक शांति नहीं आएगी, जब तक कि ट्रंप इस्राइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और हमास के पर्यवेक्षकों (तुर्किये, मिस्र और कतर) के साथ मिलकर कानून नहीं बनाते।

ट्रंप के पास आराम करने के लिए एक पल भी नहीं है। पहला चरण जितना कठिन था, उससे ज्यादा मुश्किलें आगे आएंगी। उन्हें नेतन्याहू से यह भी पूछना होगा कि 'क्या आप इस्राइली राजनीति के केंद्र में आकर एक ऐसा गठबंधन बनाने जा रहे हैं, जो एक संशोधित फलस्तीनी प्राधिकरण के साथ मिलकर हमास की जगह ले सके और गाजा व पश्चिमी तट, दोनों पर शासन कर सके? या फिर आप वही खेल जारी रखेंगे, जो आपने 1996 से अमेरिकी राष्ट्रपतियों के साथ खेला है-और गाजा में हमास को चुपचाप जिंदा रखने और फलस्तीनी प्राधिकरण को कमजोर करने की कोशिश करेंगे, ताकि बता सकें कि दूसरा पक्ष शांति के लिए तैयार नहीं है?' कतर, तुर्किये और मिस्र तथा जो भी अरब देश गाजा में सेना भेजने के लिए तैयार हैं, उनसे भी ट्रंप को पूछना चाहिए कि 'क्या आप हमास को निरस्त्र करने के लिए मजबूर करेंगे और गाजा में फलस्तीनी प्राधिकरण के नेतृत्व की वापसी का मार्ग प्रशस्त करेंगे या हमास के साथ चालाकी से पेश आएंगे, क्योंकि वह वहां फिर से नियंत्रण स्थापित करना चाह रहा है?'

हालांकि, हमास ने संकेत दिया है कि वह गाजा में नागरिक शासन किसी अन्य फलस्तीनी इकाई को सौंपने को तैयार है, लेकिन उसने कभी सार्वजनिक रूप से नहीं कहा कि वह हथियार डाल देगा। यदि हमास निरस्त्रीकरण में विफल रहता है, तो इससे नेतन्याहू को युद्ध पुनः शुरू करने का बहाना मिल जाएगा, तथा अगले चरणों में आने वाली सभी राजनीतिक चुनौतियों से बचने का मौका मिल जाएगा। इस बात की बिल्कुल संभावना नहीं है कि ट्रंप इस संघर्ष विराम को स्थायी शांति में तब्दील कर सकें, जब तक कि हमास को यथाशीघ्र एक संशोधित फलस्तीनी प्राधिकरण द्वारा हटा नहीं दिया जाता। इस्राइली लेखिका अरी शावित ने बताया कि 'जब ट्रंप ने फरवरी में गाजा को गाजावासियों से खाली करने का सुझाव दिया, तो इस्राइल को लगा कि गाजा पर कब्जा कर लिया जाएगा और अगला कदम वेस्ट बैंक होगा। अब आठ महीने बाद ट्रंप उन्हीं इस्रालियों से कह रहे हैं कि गाजा और वेस्ट बैंक पर कब्जा नहीं किया जाएगा।' जल्द ही ट्रंप को यह एहसास हो जाएगा कि यदि गाजा में स्थायी शांति चाहिए, तो उन्हें शीघ्र वहां एक संशोधित फलस्तीनी प्राधिकरण स्थापित करना होगा।

जून 2007 में हमास द्वारा हटाए जाने से पहले, फलस्तीनी प्राधिकरण गाजा पट्टी पर शासन करता था, और यह सब एक कानूनी, आर्थिक और व्यापारिक ढांचे के तहत होता था, जिस पर ओस्लो समझौते के तहत इस्राइलियों और फलस्तीनी राजी हुए थे। बस उस ढांचे को फिर से इस्तेमाल करने की जरूरत है। गाजा में नए सिरे से शासन व्यवस्था को व्यवस्थित होने में महीनों लगेंगे, और हमास इस खालीपन का फायदा उठाएगा। मेरे विचार से फलस्तीनी राष्ट्र का संचालन संशोधित फलस्तीनी प्राधिकरण द्वारा होना चाहिए और उसे एक अरब/अंतरराष्ट्रीय शांति सेना का निरंतर समर्थन मिले, जो यह सुनिश्चित करेगा कि यह फलस्तीनी राष्ट्र इस्राइल के लिए कभी खतरा न बने, और उसे समर्थन देने वाला अंतरराष्ट्रीय 'शांति बोर्ड' उसकी आर्थिक सफलता की गारंटी देगा। लेकिन इसका एकमात्र रास्ता यही है कि हमास को जल्दी से निरस्त्र कर दिया जाए, और फलस्तीनी प्राधिकरण को जल्दी से पुनर्गठित करके गाजा में स्थापित कर दिया जाए।

©The New York Times 2025

त्योहार

इस दिवाली निभाएं कुछ जिम्मेदारियां

घरों की सफाई वातावरण को स्वच्छ करती है, तो गैर-जरूरी खरीदारी से क्षति पहुंचती है। संतुलन व नियंत्रण से त्योहार की रौनक बनी रहेगी, तो पर्यावरण भी संरक्षित रहेगा।

डॉ. विवेक एस अग्रवाल

दीपावली के लिए घरों में सफाई और खरीदारी साथ-साथ चल रही है। घरों की सफाई स्वच्छ वातावरण को आमंत्रित करती है, तो गैर-जरूरी खरीदारी कहीं न कहीं पर्यावरण के लिए घातक सिद्ध हो जाती है। दीपावली पर नए कपड़े खरीदने और खाद्य पदार्थ बनाने व आपस में बांटने का प्रचलन सदियों पुराना है, लेकिन यह कब अपनी सीमाओं को लांघते हुए भौतिकवादी एवं उपभोक्तावादी युग में उत्तरदायित्व के बोध से दूर हो गया, यह इन्सान को संभवतया मालूम भी नहीं पड़ा।

भारत में त्योहारों के अवसरों पर खरीदारी में विस्फोटक रूप से बढ़ोतरी होती है, वहीं पश्चिमी देशों में भौतिकता एवं दिखावे का प्रभाव ज्यादा होने से इनकी खरीद एवं चलन सामान्य दिनों में भी बढ़ोतरी की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। इसी को दृष्टिगत रखते हुए यूरोपीय संघ ने हाल ही में विशेष कानून पारित करते हुए खाद्य एवं वस्त्र से उपजे अपशिष्ट पर 2030 तक कमी लाने के उद्देश्य से लक्ष्य तय किए हैं। हालांकि, भारत में 2014 के बाद कचरा प्रबंधन को लेकर काफी जागृति आई है, किंतु आज भी प्रचलित कानून में कचरा उत्पादनकर्ता की अपेक्षा सरकारी स्थानीय निकाय संस्थाओं को ही जिम्मेदार ठहराया गया है। लोग खाद्यान्न भी बर्बाद कर रहे हैं। हालांकि, भारत में खाद्यान्न अपशिष्ट यूरोप की अपेक्षा काफी कम मात्र 55 किलो प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष है, लेकिन यदि इस पर लगाम नहीं लगाई गई, तो इसे यूरोप के समकक्ष आने में देर नहीं लगेगी। इस संदर्भ में यूरोपीय कानून से सबक लेते हुए वर्तमान में जब कचरा प्रबंधन का उचित माहौल बना हुआ है, उपभोक्ता एवं उत्पादनकर्ता को उत्तरदायी बनाया जाना आवश्यक एवं उचित होगा।

भारत में दिवाली सभी वर्गों का त्योहार माना जाता है, लेकिन इस अवसर पर संतुलन और नियंत्रण, दोनों ही गड़बड़ा जाते हैं। विगत कुछ दशकों में मिठाई, मेवे, चॉकलेट समेत खाद्य एवं पेय सामग्री के आदान-प्रदान संबंधी व्यवस्था का प्रचलन भी बेतहाशा बढ़ गया है। खास तौर पर तथाकथित प्रभावशाली एवं पदस्थ व्यक्तियों के यहां विभिन्न माध्यमों से हजारों किलो तक मिठाई इत्यादि पहुंच जाती है, जिसका उन्हें भी अंदाजा नहीं रहता और परिणामस्वरूप बड़ी मात्रा में वह बर्बाद हो जाती है। कुछ वर्ष पूर्व अन्नक्षेत्र नामक संस्था ने प्रभावशाली पदस्थ व्यक्तियों से शपथपत्र के माध्यम से अधिशेष मिठाई, नमकीन आदि एकत्रित करने का प्रकल्प प्रारंभ किया था, जिसके जरिये जयपुर शहर में एक बार में ही कई टन मिठाई को बर्बाद होने से न केवल बचाया गया, बल्कि वह अनेक लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का माध्यम भी बन गया।

बर्बादी को रोकने के लिए कानून सिर्फ जरिया बन सकता है, किंतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है व्यवहार में परिवर्तन लाना। आवश्यकताओं का सही आंकलन करते हुए सीमित रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में पैकेजिंग व्यवस्था को भी पुनः परिभाषित करने की जरूरत है। चलन में आम तौर पर 250 ग्राम से लेकर एक किलोग्राम तक के मिठाई पैकेट रहते हैं। त्योहारी बिक्री में एक किलोग्राम का पैक सबसे ज्यादा बिकता है। यदि सत्कार रूप में मिठाई इत्यादि की भेंट को दिखावे से हटकर छोटे पैकेट में तब्दील कर दिया जाए, तो वह अधिक उपयोगी होने के साथ बर्बादी भी रुकेगी। इस दिवाली उत्तरदायी होने के लिए यदि हम भेंट की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा की अपेक्षा गुणवत्ता पर ध्यान दें, तो प्रदूषण एवं विषमता, दोनों पर नियंत्रण पा सकते हैं।

edit@amarujala.com

हर उम्र का अपना एक सौंदर्य है

जिन्होंने जीवन को सही मायने में जिया, वे जानते हैं कि हर उम्र का अपना सौंदर्य है। एक व्यक्ति अपने जीवनकाल में सभी प्रकार के अनुभव प्राप्त करता है और ये अनुभव उसे एक पूर्ण और सार्थक जीवन की ओर ले जाते हैं।

मिच एल्बॉम

आपने कभी लोगों को यह कहते नहीं सुना होगा, 'काश मैं 65 साल का होता।' लेकिन यह जरूर सुनते हैं, 'काश मैं फिर से जवान होता।' अगर वृद्धावस्था इतनी मूल्यवान होती, तो लोग हमेशा यह क्यों कहते? यह क्या दर्शाता है? असंतुष्ट जीवन। अधूरा जीवन। ऐसा जीवन, जिसे कोई अर्थ नहीं मिला। अगर आपको अपने जीवन में अर्थ मिल गया है, तो आप पीछे नहीं लौटना चाहते। आप आगे बढ़ना चाहते हैं। आप और दुनिया देखना चाहते हैं, और काम करना चाहते हैं। आप किसी उम्र में रुकना नहीं चाहते, बल्कि आगे निरंतर बढ़ना चाहते हैं। सभी को यह पता होना चाहिए कि अगर हम हमेशा बुजुर्ग होने से जूझते रहेंगे, तो हमेशा दुखी ही रहेंगे, क्योंकि यह तो वैसे भी होगा ही। सच तो यह है कि हम सभी अंततः मर जाएंगे।

मैंने एक बार मॉरी से पूछा कि क्या उन्हें कभी युवा और स्वस्थ लोगों से ईर्ष्या होती है? मॉरी का जवाब था कि उम्र कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। उन्होंने कहा कि वह हर उस उम्र में हैं, जो उन्होंने कभी जी है, और चूंकि उन्होंने पहले ही युवावस्था का अनुभव कर लिया है, इसलिए उससे ईर्ष्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बुजुर्गों के पास वे सभी उम्र होती हैं, जो युवा लोग अभी प्राप्त नहीं कर पाए हैं। जिन्होंने जीवन को सही मायने में जिया, वे जानते हैं कि हर उम्र का अपना सौंदर्य है।

मुड़-मुड़ के देख

एक व्यक्ति अपने जीवनकाल में सभी प्रकार के अनुभव प्राप्त करता है और ये अनुभव उसे एक पूर्ण और सार्थक जीवन की ओर ले जाते हैं। यदि कोई एक ही उम्र में रहना चाहेगा, तो जीवन कभी सार्थक नहीं होगा। उसे हमेशा असंतुष्टि घेरे रहेगी। जैसे-जैसे आप बड़े होते हैं, आप और सीखते हैं। बीस-बाईस साल की उम्र में आप जितने अज्ञानी थे, उतने ही अज्ञानी बने रहते, यदि आप हमेशा उसी उम्र में रहते। वृद्धावस्था क्षय नहीं है, बल्कि यह विकास है। यह इस नकारात्मकता से कहीं बढ़कर है कि आप मरने वाले हैं, यह इस सकारात्मकता से कहीं बढ़कर है कि आप समझते हैं कि आप मरने वाले हैं, और इसलिए आप बेहतर जीवन जीते हैं। यह समय का अनोखा रूप है।

सुख स्वाद में नहीं, आपके भीतर है

वाराणसी के 65 वर्षीय **प्रेम शंकर** के भोजन में स्वाद न आने की समस्या पर मनोविज्ञानी **नीलकंठ** ने उन्हें समझाया

मैं हमेशा से ही खाने-पीने का शौकीन रहा हूं, लेकिन पिछले कुछ समय से महसूस कर रहा हूं कि इसमें स्वाद आना कम हो गया है। क्या करूं?

वैसे तो उम्र बढ़ने के साथ सभी इंद्रियां कमजोर होने लगती हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इनमें से स्वाद इंद्रिय से जुड़ी समस्याएं बुजुर्गों में सबसे आम हैं। हाल ही में हुआ एक शोध बताता है कि तकरीबन तीन-चौथाई बुजुर्गों को किसी अन्य कमजोरी के बजाय स्वाद लेने से जुड़ी परेशानी अधिक पाई जाती है। इसलिए आपको इसको लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप यह समझ लें कि स्वाद लेने की क्षमता का ह्रास तो सबमें होता है, लेकिन यह इतना धीरे-धीरे होता है कि अमूमन लोगों को पता नहीं चल पाता।

कई बार तो युवाओं को भी यह समस्या आ जाती है। एक रोचक तथ्य यह भी है कि जिन लोगों को यह समस्या होती है, उन्हें भी पहले सूंघने की क्षमता में कमी आने का पता चलता है, क्योंकि ज्यादातर स्वाद का पहला संबंध गंध से ही होता है। कई बार स्वाद न आने की वजह से कुछ लोगों की भूख कम हो जाती है और वे कमजोर हो सकते हैं। कुछ लोग स्वाद बढ़ाने के लिए नमकीन, मीठे और वसायुक्त पदार्थों का सेवन करते हैं, जिससे टाइप 2 मधुमेह और हृदय रोग जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। आप ऐसा बिल्कुल न करें, क्योंकि ऐसा करने पर आप दूसरी कई बीमारियों को आमंत्रित कर लेंगे।

आपने यह नहीं बताया कि आपमें अवसाद जैसे कुछ लक्षण तो नहीं, क्योंकि स्वाद और गंध की कमी की समस्या अवसाद की देन भी हो सकती है, क्योंकि ये इंद्रिया दिमाग के भावनात्मक परिपथों से जुड़ी होती हैं। मसलन, भोजन अक्सर संस्कृति, परिवार और पहचान से जुड़ा होता है। अगर आपमें ऐसे कोई लक्षण हैं, तो कृपया तुरंत चिकित्सक से सलाह लें।

कई बार मसूड़ों, दांतों या जीभ के संक्रमण व सफाई संबंधी समस्याएं भी स्वाद ग्रंथि को कमजोर कर देती हैं। इसलिए, जरूरी है कि आप खूब पानी पिएं और जीभ की सफाई पर खास ध्यान दें। एक उम्र के बाद स्वाद और गंध से जुड़ी इंद्रियों में कुछ समस्याएं आना स्वाभाविक है। 60 की उम्र के बाद स्वाद कलिकाओं और गंध ग्राहियों की संख्या कम हो जाती है, क्योंकि आपका शरीर उन्हें पुनर्जीवित करने की क्षमता खो देता है। कई बार टाइप 2 डाइबिटीज, स्ट्रोक, अल्जाइमर और पर्किंसन जैसी बीमारियां और ब्लड प्रेशर की कुछ दवाएं भी स्वाद व गंध से जुड़ी परेशानियां पैदा करती हैं। अपनी इंद्रियों की क्षमताओं को बढ़ाने का एक प्राकृतिक उपाय प्राणायाम हो सकता है, जिसका अभ्यास आप यथासंभव रोज कर सकते हैं। एक बात और, भोजन जो दिखने में स्वादिष्ट लगे, वह स्वाद बढ़ा सकता है। भोजन में अतिरिक्त नमक या चीनी मिलाकर खाने से बचें, क्योंकि इससे उल्टा नुकसान ही होगा। ध्यान रखें, भोजन से हमें सुख मिलता है और यह सुख स्वाद या गंध से कम आपकी मनोदशा पर ज्यादा निर्भर करता है। इसलिए, हर हाल में खुश रहें।

*जिंदगी की **दूसरी पारी** बहुत महत्वपूर्ण होती है। हर शुक्रवार इस पर आपको नया पढ़ने को मिलेगा। आप अपने विचार, अनुभव या समस्याएं edit@amarujala.com पर भेज सकते हैं, विशेषज्ञों की मदद से हम कोशिश करेंगे कि संवाद का पुल बन सके।*

68 साल की दादी और स्केटबोर्डिंग

चीन की 68 वर्षीय दादी लियू के स्केटबोर्डिंग करते हुए वीडियो इंटरनेट पर धूम मचा रहे हैं। उन्होंने बेटी के साथ पार्क में छोटी-छोटी ट्रिक्स सीखीं और वीडियो शेयर किए। बड़ी उम्र के बावजूद बिना डर के उनका स्केटिंग करना लाखों लोगों को प्रेरित कर रहा है। दादी कहती हैं कि युवा हो या बुजुर्ग, सबको कुछ नया सीखने की कोशिश करनी चाहिए। बुजुर्गों के साथ ही युवा भी उनसे मिलकर प्रेरित हो रहे हैं। कई बुजुर्गों ने तो दादी से प्रेरणा लेकर खेलना शुरू कर भी दिया है।

वरिष्ठ नागरिकों के

काम की योजना

बुजुर्गों की सुरक्षा

उत्तर प्रदेश पुलिस की 'सवेरा योजना' बुजुर्गों को सुरक्षा प्रदान करती है। यूपी-112 पर कॉल कर या https://112.up.gov.in/registration पर पंजीकरण कराकर वरिष्ठ नागरिक सहायता ले सकते हैं। बुजुर्गों को जरूरत पड़ने पर निकटतम पुलिस थाने की पुलिस या पुलिस रिस्पांस व्हीकल पहुंचकर उन्हें सहायता प्रदान करते हैं। वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु जिला स्तर और प्रत्येक थाने में एक विशेष वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ का भी गठन किया गया है।

वृद्धों का समग्र कल्याण

वृद्धकेयर फाउंडेशन वृद्धों के समग्र कल्याण पर ध्यान केंद्रित करता है। यह वृद्धाश्रम में देखभाल करने वालों को प्रशिक्षित करने के साथ ही आंखों के इलाज, सरकारी और सामाजिक सेवाओं से बुजुर्गों को लाभान्वित करवाता है। आधिकारिक वेबसाइट पर https://www.vridhcare.com/ पर सहायता व जानकारी के लिए जाएं या हेल्पलाइन 8700851044 पर संपर्क कर इसका लाभ ले सकते हैं।

भीड़ में नहीं भटकेंगे यात्री, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर स्थायी होल्डिंग एरिया किया तैयार

त्योहारी सीजन को देखते हुए भीड़ नियंत्रण के लिए अत्याधुनिक इंतजाम

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। त्योहारी सीजन में यात्रियों की भीड़ देखते हुए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर स्थायी होल्डिंग एरिया तैयार किया गया है। यात्रियों के प्लेटफॉर्म या सड़कों पर फंसने की स्थिति में यह एरिया राहत देगा। करीब सात हजार यात्रियों की क्षमता वाले इस क्षेत्र में बैठने, टिकटिंग, पानी और शौचालय की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इस एरिया में टिकट काउंटर भी शिफ्ट कर दिया गया है। रेलवे ने दीपावली और छठ पर्व की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए यह व्यवस्था शुरू की है।

रेलवे ने पूरे क्षेत्र को तीन जोनों में बांटा है। पहले जोन में 1155, दूसरे में 2842 और तीसरे में 1284 यात्रियों की क्षमता है। यहां 25 टिकट काउंटर, 22 टिकट वेंडिंग मशीनें, 24 अनाउंसमेंट सिस्टम और 18 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। यात्री यहां से अनारक्षित विंडो से टिकट खरीद सकेंगे। महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग लाइन और बैठने की विशेष व्यवस्था की गई है।

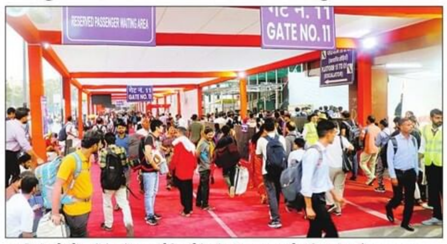

यात्रियों की भीड़ को देखते हुए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधा केंद्र तैयार। अमर उजाला

150

से अधिक शौचालयों की सुविधा

■ टिकटिंग, पानी और शौचालय की आधुनिक सुविधाएं भी यात्रियों के लिए उपलब्ध

एआई कैमरे रखेंगे नजर

- रेलवे ने भीड़ प्रबंधन के लिए एआई आधारित कैमरों और सेंट्रल पब्लिक एड्रेस सिस्टम का प्रयोग शुरू किया है।
- एआई कैमरे भीड़ की रीयल टाइम निगरानी करेंगे और सीमा पार होते ही कंट्रोल रूम को अलर्ट भेजेंगे। 35 डिजिटल वॉकी-टॉकी डिवाइस स्टाफ को दिए गए हैं ताकि साइलेंट कोऑर्डिनेशन के जरिए भीड़ को संभाला जा सके।
- दिल्ली डिवीजन के सभी प्रमुख स्टेशनों पर मिनी-कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जो मुख्य कंट्रोल रूम को लगातार रीयल टाइम डेटा भेजेंगे।

यात्री सुविधा केंद्र में आधुनिक इंतजाम

होल्डिंग एरिया के यात्री सुविधा केंद्र में 150 से अधिक शौचालय, प्यूरीफाइड वॉटर की व्यवस्था और 200 यात्रियों के बैठने की क्षमता है। 18 एचवीएलएस पंखे लगाए गए हैं, 18 सीसीटीवी कैमरे और 5 लगेज स्कैनर और 5 डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर भी स्थापित किए गए हैं। स्टेशन परिसर में मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर एक के पास होल्डिंग एरिया बनाया गया है। यहां फुटओवर ब्रिज के पास से पैदल एरिया में जाना होगा।

यात्री सुविधा केंद्र में बैठे यात्री। अमर उजाला

कचरा फेंकने में लापरवाही करने पर एनजीटी ने अफसरों को लगाई फटकार

संवाद न्यूज एजेंसी

घर के सामने खाली प्लॉट में कूड़े के ढेर लगने और इससे फैल रही दुर्गंध, मच्छरों से स्वास्थ्य जोखिमों की शिकायत की थी

नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने रिहायशी इलाके में खाली प्लॉट पर कचरा फेंकने की शिकायत पर कार्रवाई में देरी को लेकर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) और नगर निगम (एमसीडी) को कड़ी फटकार लगाई है। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेष सदस्य डॉ. ए सेंथिल वेल की पीठ ने कहा कि पहले दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया गया। इससे स्थानीय निवासियों को स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

अधिकरण ने कहा कि आदेशों का अनुपालन नहीं होना गंभीर लापरवाही है। पीठ ने याचिका में शामिल सभी पक्षों को पक्षकार बनाया और सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने के आदेश दिए। याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह सेवा प्रमाण पत्र अगली सुनवाई से एक सप्ताह पहले दाखिल करें। मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी, 2026 को होगी। एनजीटी ने चेतावनी दी कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

याचिकाकर्ता संदीप चौधरी ने अपने घर के सामने खाली प्लॉट पर कूड़े के ढेर लगने और इससे फैल रही दुर्गंध, मच्छरों, चूहों व अन्य कीड़ों से उत्पन्न स्वास्थ्य जोखिमों की शिकायत की थी। ऐसे में एनजीटी ने 21 मई, 2025 को डीपीसीसी और एमसीडी को साइट का निरीक्षण कर उचित निवारक और उपचारात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।

वहीं, डीपीसीसी की 19 जून, 2025 की निरीक्षण रिपोर्ट में पाया गया कि प्लॉट पूरी तरह कचरे से भरा हुआ था, आसपास भयानक दुर्गंध फैली हुई थी और कीट-पतंगों का प्रकोप था। डीपीसीसी ने 23 जून, 2025 को एमसीडी को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और न ही कोई रिपोर्ट सौंपी गई। रिपोर्ट के बाद कार्रवाई होगी।

नई तकनीक से अब कार्बन उत्सर्जन मापना होगा आसान

संवाद न्यूज एजेंसी

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित प्लेटफॉर्म रिकॉर्ड करेगा सटीक और पारदर्शी डाटा

नई दिल्ली। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब कार्बन उत्सर्जन मापने और रिकॉर्ड करने के लिए सटीक और भरोसेमंद तकनीक मिल गई है। यह तकनीक एक स्टार्टअप कंपनी और यूके की ग्रीन इकॉनमी पार्टनरशिप ने मिलकर तैयार की है। दोनों संस्थाओं ने मिलकर एक खास डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसका नाम पेरिस समझौता कार्यान्वयन मंच (पीएआईपी) है। यह प्लेटफॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है। इसकी मदद से किसी भी देश में होने वाले कार्बन उत्सर्जन का सटीक और पारदर्शी रिकॉर्ड तैयार किया जा सकेगा।

अभी तक दुनिया भर में कार्बन उत्सर्जन को मापने की कोई एकसमान और भरोसेमंद तकनीक नहीं थी। इसी वजह से जलवायु समझौते लागू करने में कई समस्याएं आ रही थीं। लेकिन अब यह प्लेटफॉर्म इस बड़ी समस्या का समाधान बन सकता है। यह प्लेटफॉर्म सभी देशों की सरकारों को बिलकुल मुफ्त दिया जाएगा।

खास बात यह है कि यह विकासशील देशों जैसे भारत के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि इससे उन्हें अपने जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने और पर्यावरण से जुड़े फंड हासिल करने में मदद मिलेगी। इस नए प्लेटफॉर्म का औपचारिक लॉन्च अगले साल ब्राजील में होने वाले कॉप 30 सम्मेलन में किया जाएगा।

17 से 26 अक्तूबर तक दिल्ली में पार्सल सेवाएं बंद

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली, दिल्ली जंक्शन और आनंद विहार टर्मिनल से पार्सल सेवाओं पर रोक

नई दिल्ली। उत्तर रेलवे ने रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए दिल्ली क्षेत्र में पार्सल यातायात पर अस्थायी रोक लगा दी है।

नई दिल्ली, दिल्ली जंक्शन और आनंद विहार टर्मिनल से चलने वाली ट्रेनों में 17 से 26 अक्तूबर तक सभी प्रकार के पार्सल लेन-देन पर रोक रहेगी। साथ ही, रेलवे के माध्यम से सीधी पार्सल बुकिंग पर भी 15 से 26 अक्तूबर तक रोक रहेगी।

इस अवधि में पार्सल गोदामों और प्लेटफॉर्मों को पार्सल पैकिंग या लेन-देन से मुक्त रखा जाएगा। हालांकि, यात्री डिब्बों में व्यक्तिगत सामान की अनुमति होगी। इसके अलावा सभी आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद पंजीकृत समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की बुकिंग की अनुमति दी जाएगी। यह अस्थायी प्रतिबंध न केवल दिल्ली क्षेत्र के प्रमुख स्टेशनों पर लागू रहेगा बल्कि उन ट्रेनों पर भी लागू होगा जो दिल्ली क्षेत्र से होकर गुजरती हैं और यहां लोडिंग या अनलोडिंग का स्टॉपिज रखती हैं।

रेलवे के कई आरक्षण केंद्र सायंकालीन पारी में रहेंगे बंद

नई दिल्ली। उत्तर रेलवे ने दीपावली के अवसर पर दिल्ली में अपने यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) केंद्रों के कामकाज में आंशिक बदलाव किया है। 20 अक्तूबर को दीपावली के दिन कई आरक्षण केंद्रों में केवल सुबह की पारी में काम होगा, जबकि कुछ केंद्र पूरे दिन बंद रहेंगे। रेलवे के अनुसार आईआरसीए भवन, दिल्ली जंक्शन और हजरत निजामुद्दीन आरक्षण कार्यालयों में सायंकालीन पारी में सेवाएं शाम 6 बजे तक उपलब्ध रहेंगी।

सायंकालीन पारी में दोपहर 2 से रात 8 बजे तक सरोजिनी नगर, कीर्ति नगर, शकूरबस्ती, दिल्ली शाहदरा, गाजियाबाद, कड़कड़डूमा, ओखला, नोएडा, तुगलकाबाद, सब्जी मंडी, आदर्श नगर, लाजपत नगर, रोहिणी, एम्स और अंतरराष्ट्रीय टूरिस्ट ब्यूरो केंद्र बंद रहेंगे। इन केंद्रों पर सुबह की पारी सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक सामान्य रूप से कार्यरत रहेंगी। संसद भवन, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, रेलवे बोर्ड, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट स्थित आरक्षण केंद्र पूरे दिन बंद रहेंगे। यह व्यवस्था अस्थायी रूप से लागू की गई है। ब्यूरो

समस्तीपुर और गोरखपुर के लिए श्री गंगानगर से 19 से विशेष ट्रेनें

दीपावली और छठ को देखते हुए उत्तर रेलवे ने लिया फैसला, ट्रेन में एसी, स्लीपर और सामान्य श्रेणी के कोच भी होंगे

नई दिल्ली। उत्तर रेलवे ने दीपावली और छठ पर्व पर यूपी और बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए श्रीगंगानगर से समस्तीपुर और गोरखपुर के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है।

ट्रेन में वातानुकूलित, स्लीपर और सामान्य श्रेणी के डिब्बे शामिल होंगे। 04731 श्रीगंगानगर–समस्तीपुर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 19, 26 अक्तूबर और दो नवंबर को दोपहर 1:25 बजे श्रीगंगानगर से रवाना होगी। अगले दिन रात 11:00 बजे समस्तीपुर पहुंचेगी। 04732 समस्तीपुर–श्रीगंगानगर स्पेशल 21, 28 अक्तूबर और चार नवंबर को रात 1:00 बजे समस्तीपुर से रवाना होकर अगले दिन दोपहर 12:20 बजे श्रीगंगानगर पहुंचेगी।

यह ट्रेन मार्ग में सादुलशहर, हनुमानगढ़, हिसार, रोहतक, दिल्ली जंक्शन, गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, सीतापुर, बस्ती, गोरखपुर, छपरा, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर समेत कई प्रमुख स्टेशनों पर ठहरेगी। 04729 श्रीगंगानगर–गोरखपुर स्पेशल 23 और 30 अक्तूबर को (दो फेरों में) बृहस्पतिवार को चलेगी। यह दोपहर 1:25 बजे श्रीगंगानगर से रवाना होकर अगले दिन शाम 4:30 बजे गोरखपुर पहुंचेगी।

वापसी में 04730 गोरखपुर–श्रीगंगानगर स्पेशल 24 और 31 अक्तूबर को शुक्रवार को चलेगी, जो रात 7:30 बजे गोरखपुर से रवाना होकर तीसरे दिन सुबह 2:45 बजे श्रीगंगानगर पहुंचेगी। ब्यूरो

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर जाने के लिए लाइन में खड़े यात्री। फोटो : जी पाल

ताज लेक पैलेस के खिलाफ एआई-जनित अपमानजनक वीडियो हटाने का दिया आदेश

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने अज्ञात उपयोगकर्ता की ओर से अपलोड किए गए और एआई तकनीक से बनाए गए इंस्टाग्राम वीडियो को हटाने का आदेश दिया। इसमें उदयपुर के ताज लेक पैलेस के खिलाफ अपमानजनक दावे किए गए थे। यह मामला द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड से संबंधित है। न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने प्रथम दृष्टया राय दी कि वीडियो में दिए गए दावे झूठे हैं, मेटा इसे 36 घंटे के भीतर हटाए।

टाटा ग्रुप की कंपनी जो ताज होटल श्रृंखला की मालिक है ने तर्क दिया कि इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड एआई वीडियो में झूठा दावा किया गया कि 2018 में होटल के कर्मचारियों ने धनी मेहमानों को जहर देकर हत्या की थी और इस मामले को दबा दिया गया था। कंपनी ने कोर्ट को बताया कि पूरी तरह से एआई जनित और संदिग्ध दावों वाले इस वीडियो को व्यापक रूप से प्रसारित किया गया, जिसे इंस्टाग्राम पर 20,000 से अधिक बार देखा गया। कंपनी ने हाईकोर्ट से इस वीडियो को हटाने का आदेश देने की मांग की।

न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने प्रथम दृष्टया राय दी कि वीडियो में दिए गए दावे झूठे हैं और इसे हटाया जाना चाहिए। कोर्ट ने इंस्टाग्राम के मालिक मेटा को 36 घंटे के भीतर वीडियो हटाने का निर्देश दिया। साथ ही, अज्ञात अपलोडर को सोशल मीडिया या ऑनलाइन किसी भी ऐसे कंटेंट को प्रसारित करने, प्रकाशित करने या वितरित करने से रोक दिया गया, जो ताज की मानहानि करता हो या उसके ट्रेडमार्क का उल्लंघन करता हो।

महिला सहकर्मी को अश्लील संदेश भेजना सैन्य बल के लिए अनुचित : हाईकोर्ट

नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने सैन्य बल के अंदर अपनी ही महिला सहकर्मी को अश्लील संदेश भेजना अनुचित बताया। अदालत ने सीआईएसएफ सब-इंस्पेक्टर पर लगाए गए वेतन कटौती की सजा को बरकरार रखा। सब इंस्पेक्टर पर एक महिला सहकर्मी को अश्लील संदेश भेजने और परेशान करने वाले फोन कॉल के आरोप थे। न्यायमूर्ति सुब्रह्मण्यम प्रसाद और न्यायमूर्ति विमल कुमार यादव की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा, जैसा कि जांच कार्यवाही और पुनरीक्षण प्राधिकरण में ठीक ही बताया गया। याचिकाकर्ता जो एक वर्दीधारी सेवा का सदस्य है, पहले से विवाहित है, को किसी अन्य महिला को अश्लील संदेश भेजने का कोई अधिकार नहीं था। यह आचरण निश्चित रूप से एक वर्दीधारी बल के अधिकारी के लिए अनुचित है। अधिकारी की अपील को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि दुराचार को देखते हुए सजा उचित थी और उल्लेख किया कि अधिकारी के साथ बहुत हल्का व्यवहार किया गया है। सजा में दो साल के लिए वेतन कटौती शामिल थी, जिसके दौरान उसे कोई वेतन वृद्धि नहीं मिलेगी। ब्यूरो

राष्ट्रमंडल खेल गांव में बरातघर के खिलाफ याचिका का निपटारा

नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने राष्ट्रमंडल खेल गांव के निवासी कल्याण संघ (आरडब्ल्यूए) द्वारा दायर एक याचिका का निपटारा कर दिया है। उसमें दावा किया गया था कि खेल परिसर के अंदर एक बरातघर का निर्माण पर्यावरणीय मंजूरी के बिना किया जा रहा है। हालांकि, अधिकरण ने पाया कि उल्लंघन का कोई सबूत पेश नहीं किया गया।

सुनवाई के दौरान एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. ए सेंथिल वेल की अध्यक्षता वाली पीठ ने अहम टिप्पणी की। अदालत ने पाया कि आवेदक यह बताने में विफल रहा कि परियोजना ने पर्यावरणीय मानदंडों का उल्लंघन कैसे किया। अप्रैल 2025 में आरडब्ल्यूए द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि डीडीए ने पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना के तहत पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त किए बिना ही सामुदायिक भवन का काम शुरू कर दिया था। संवाद

कोर्ट डायरी

नरेश बाल्यान से जुड़े मकोका मामले में मनोज कैरा को न्यायिक हिरासत में भेजा

नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट में पूर्व आप विधायक नरेश बाल्यान से जुड़े मकोका मामले में बृहस्पतिवार को सुनवाई हुई। विशेष न्यायाधीश (पीसी अधिनियम) डॉ. विशाल गोगने की अदालत ने आरोपी रोहित कुमार दलाल को गैर-जरूरी दस्तावेजों की सूची मिलने तक स्पष्टीकरण आवेदन दाखिल करने की अनुमति दी। आरोपी को चिकित्सा आधार पर जेल अधीक्षक को इलेक्ट्रिक केतली और गर्म पानी की थैली उपलब्ध कराने के आवेदन पर नोटिस जारी कर अगली तारीख पर जवाब मांगा है। अन्य आरोपी के आवेदन पर कोर्ट ने आंशिक राहत दी। आरोपी ने जेल अधिकारियों से कलाई घड़ी, व्यक्तिगत डायरी और फीतेदार जूतों की मांग की थी। दो वस्तुओं पर कोई निर्देश नहीं दिए। कोर्ट ने प्रारंभिक जांच चरण को देखते हुए कैरा को 31 अक्तूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। संवाद

संजय भंडारी मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी को दस्तावेज सौंपने का आदेश

नई दिल्ली। भगोड़े हथियार डीलर संजय भंडारी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में बृहस्पतिवार को सुनवाई हुई। विशेष न्यायाधीश सुशांत चंगोत्रा ने आरोपी सीसी थम्पी को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी। हाईकोर्ट के 31 जुलाई के आदेश का हवाला देते हुए कोर्ट ने ईडी को एक सप्ताह में अप्रमाणित दस्तावेजों की सूची आरोपी को देने को कहा है। थम्पी के वकील के अनुसार, ईडी ने अभी तक अनुपालन नहीं किया, जबकि ईडी पक्ष ने तत्काल अनुपालन का वादा किया। गैर-विश्वसनीय दस्तावेजों की रिपोर्ट 6 दिसंबर को प्रस्तुत होगी। ब्यूरो

दिल्ली दंगा : छह दोषियों की सजा पर जिरह टली

नई दिल्ली। कड़कड़डूमा कोर्ट ने बृहस्पतिवार को फरवरी 2020 दिल्ली दंगा मामले में छह दोषियों की सजा पर जिरह को 28 अक्तूबर तक के लिए टाल दिया है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह की अदालत ने सुनाया। बीते 18 सितंबर को कोर्ट ने छह आरोपी हरिओम गुप्ता, बसंत कुमार मिश्रा, गोरखनाथ, रोहित गौतम, कपिल पांडे और भीम सैनी को दंगे और अवैध रूप से एक जगह पर एकत्रित होने के मामले में दोषी करार दिया था। संवाद

आस्था | दिल्ली से आरंभ होगी चरण सुहावा गुरु चरण यात्रा, 1 नवंबर को होगा समापन

पटना ले जाएंगे जोड़ा साहिब, 23 से होगी यात्रा : पुरी

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बृहस्पतिवार को बताया कि उनके परिवार के पास संरक्षित गुरु गोबिंद सिंह और माता साहिब कौर के पवित्र जोड़ा साहिब अब तख्त श्री पटना साहिब को अर्पित किए जाएंगे। इन्हें संगत के दर्शनार्थ चरण सुहावा गुरु चरण यात्रा के रूप में दिल्ली से पटना साहिब ले जाया जाएगा।

पुरी ने बताया कि उनके परिवार ने पवित्र जोड़ा साहिब की सेवा-संभाल तीन सौ वर्षों से की है और अब उन्हें गुरु साहिब के जन्मस्थान पटना साहिब में स्थायी रूप से समर्पित करने का निर्णय लिया गया है। यात्रा के दौरान गुरु ग्रंथ साहिब के पावन स्वरूप और पांच प्यारे भी साथ रहेंगे ताकि हर नगर और गुरुद्वारे में लोग जोड़ा साहिब के दर्शन कर सकें।

यात्रा की शुरुआत से एक दिन पहले 22 अक्तूबर की शाम को गुरुद्वारा मोती बाग साहिब में विशेष कीर्तन समागम में जोड़ा साहिब संगत के दर्शन के लिए रखे जाएंगे। इसके बाद 23 अक्तूबर को यात्रा मोती बाग साहिब से रवाना होगी और विभिन्न शहरों से होती हुई एक नवंबर को तख्त श्री पटना साहिब पहुंचेगी। 23 अक्तूबर को फरीदाबाद, 24 को आगरा, 25 को बरेली, 26 को महंगापुर, 27 को लखनऊ, 28 को कानपुर, 29 को प्रयागराज, 30 को वाराणसी होते हुए सासाराम, 31 अक्तूबर को गुरुद्वारा गुरु का बाग पटना साहिब और एक नवंबर को तख्त श्री हरमंदिर साहिब, पटना में यात्रा का समापन होगा। यह यात्रा गुरु साहिब के प्रति श्रद्धा और सेवा की भावना का प्रतीक होगी।

सीस दिया पर सिररु ना दिया, दिल्ली से अमृतसर निकलेगी साइकिल यात्रा

नई दिल्ली। श्री गुरु तेग बहादुर के 350वें शहादत दिवस के उपलक्ष्य में 15 नवंबर को दिल्ली से अमृतसर तक ऐतिहासिक साइकिल यात्रा सीस दिया पर सिररु ना दिया निकाली जाएगी। यह यात्रा गुरुद्वारा सीसगंज साहिब दिल्ली से शुरू होकर गुरु साहिब के जन्मस्थान गुरुद्वारा गुरु का महल अमृतसर में 20 नवंबर को संपन्न होगी। यात्रा का आयोजन साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मनजीत सिंह जीके करेंगे। मनजीत सिंह जीके ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य गुरु तेग बहादुर साहिब की शहादत, निर्भयता और धार्मिक स्वतंत्रता की भावना को जन-जन तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि यह यात्रा सिख समुदाय को धार्मिक पहचान, धर्मांतरण, धार्मिक लिबास, नशे और नस्ली सफाई जैसे बढ़ते खतरों के प्रति जागरूक करेगी। जीके ने कहा कि एक दौर था जब सिख अपनी पगड़ी और धर्म की रक्षा के लिए सिर देने को तैयार रहते थे, लेकिन अब नशे और धर्मांतरण के खतरे को लेकर उदासीनता है। संवाद

हरियाणा सरकार
[आबकारी एवं कराधान विभाग]
कार्यालय उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री कर), रोज़का मेव (Meo), नूंह (मेवात)
ई-मेल: detcst-mwt.etd@hry.gov.in

नीलामी सूचना

आदेश संख्या 45130 दिनांक 05.06.2025, ARN संख्या ZD 060725016085J और आदेश संख्या 45131 दिनांक 05.06.2025, ARN संख्या ZD060725016046L, पारित किया गया और नीचे उल्लिखित माल को हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 129 और केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की समवर्ती धारा/एकीकृत माल और सेवा अधिनियम, 2017 की धारा 20 के प्रावधानों के अनुसार निरुद्ध और जब्त किया गया।

माल का विवरण :

जब्त माल का विवरण

क्र. सं.	वस्तु	मात्रा	टिप्पणी	मूल मूल्य (रु.)
1.	प्रीमियम जर्दा	18,90,000 पाउच	60 कार्टून जिसमें 18,90,000 पाउच हैं	6,49,668/-
2.	तानसेन पान मसाला	18,37,500 पाउच	350 बैग तानसेन पान मसाला जिसमें 18,37,500 पाउच हैं	39,04,688/-

उक्त आदेश के परिणामस्वरूप, कोई भी व्यक्ति जुर्माना भरने के लिए आगे नहीं आया है।

देय राशियों का सार

क्र. सं.	शीर्षक	सीजीएसटी	एसजीएसटी	आईजीएसटी	उपकर	कुल
1.	जुर्माना	0	0	91,08,752/-(उपकर सहित)	-	91,08,752/-
2.	कुल	0	0	91,08,752/-(उपकर सहित)	-	91,08,752/-

1. माल की जब्ती के अनुसरण में, विभाग ने प्रावधानों के अनुसार माल का वास्तविक कब्ज़ा ले लिया है।
2. अब, एचजीएसटी/सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 129(6) के अनुसरण में, अधोहस्ताक्षरी माल के पूर्व मालिक को 15 दिनों का उचित समय देने के बाद बिक्री आय प्राप्त करने के लिए उपरोक्त माल का निपटान करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कोई भी जुर्माना भरने के लिए आगे नहीं आया। इसलिए, अधोहस्ताक्षरी के पास हरियाणा जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 79 के प्रावधान के अनुसार सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से जब्त माल का निपटान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।

1.	सीलबंद लिफाफे में बोली जमा करने की अंतिम तिथि	कार्यालय समय के दौरान 06-11-2025
2.	ईएमडी	रु. 9,11,000/-
3.	सीलबंद बोली लिफाफा खोलने की तिथि और नीलामी का स्थान	दिनांकः 07-11-2025 प्रातः 11:00 बजे, उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (एसटी) कार्यालय, नूंह (मेवात), हुडा फील्ड हॉस्टल, रोजका मेव, नूंह (मेवात)

नियम एवं शर्तें:

1. जब्त माल उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (एसटी) कार्यालय, नूंह (मेवात) के परिसर में संग्रहीत है। इच्छुक बोलीदाता 06-11-2025 को प्रातः 11:30 बजे से अपराह्न 03:30 बजे तक अपने खर्चे पर माल की मात्रा और गुणवत्ता का सत्यापन कर सकते हैं (क्योंकि नियम 144ए के अनुसार माल शीघ्र खराब होने वाला है)।
2. बोली की न्यूनतम राशि 91,08,752/- रुपये (कर एवं उपकर सहित) होगी।
3. जो व्यक्ति माल की नीलामी में भाग लेने के इच्छुक हैं, उन्हें 06-11-2025 को सायं 04.00 बजे तक उचित अधिकारी, नूह के पक्ष में आहरित डी.डी. के माध्यम से 9,11,000/- रुपये (नौ लाख ग्यारह हजार रुपये मात्र) की बयाना राशि जमा करानी होगी। असफल बोलीदाता को बयाना राशि वापस कर दी जाएगी तथा बोली राशि में समायोजित कर दी जाएगी।
4. संपर्क के लिए, बोलीदाता को अपना आधार कार्ड, पता, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी प्रस्तुत करनी होगी।
5. बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे अपनी बोली ईएमडी के साथ सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करें और 06-11-2025 को शाम 04.00 बजे तक डीईटीसी (एसटी), नूह (मेवात) के कार्यालय के नाजिर को जमा करें।
6. यदि कोई बोली प्राप्त नहीं होती है या पर्याप्त भागीदारी की कमी या कम बोलियों के कारण नीलामी गैर-प्रतिस्पर्धी होती है, तो नीलामी प्रक्रिया रद्द कर दी जाएगी। हालाँकि, यदि उल्लिखित न्यूनतम राशि के लिए कम से कम एक बोली है, तो बोली लगाने वाले व्यक्ति को सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा, भले ही वह एकमात्र बोलीदाता हो।
7. नीलामी को स्वीकार या अस्वीकार या स्थगित करने का अधिकार उपायुक्त (राज्य कर), नूंह के पास है।
8. सफल बोलीदाता को हथौड़ा गिरते ही बोली राशि का 25% मौके पर ऑनलाइन जमा करना होगा और शेष राशि अर्थात बोली राशि का 75% 5 दिनों के भीतर जमा करना होगा। उक्त खरीद को यूआरडी खरीद के रूप में माना जाएगा।
9. यदि सफल बोलीदाता मौके पर बोली राशि का 25% जमा करने में विफल रहता है, तो ईएमडी जब्त कर ली जाएगी और बोली अगले उच्चतम बोलीदाता को दे दी जाएगी। यदि सफल बोलीदाता 5 दिनों के भीतर बोली राशि का 75% जमा करने में विफल रहता है, तो बिक्री रद्द मानी जाएगी और बोली राशि का 25% जब्त कर लिया जाएगा।
10. बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत बोली राशि कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी और जिस बोलीदाता ने उच्चतम मूल्य उद्धृत किया है, उसे बोली राशि का भुगतान करने पर नीलाम किए जाने वाले सामान को उठाने के लिए सूचित किया जाएगा।
11. बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत बोली राशि कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी और उच्चतम मूल्य उद्धृत करने वाले बोलीदाता को बोली राशि का भुगतान करने पर नीलाम किए जाने वाले सामान को उठाने के लिए सूचित किया जाएगा।
12. सफल बोलीदाता को पूरी बोली राशि का भुगतान करने के बाद तीन कार्यदिवसों के भीतर सामान उठाना होगा।
13. असफल बोलीदाता को नीलामी की कार्यवाही पूरी होने के बाद ईएमडी वापस मिल जाएगी।
14. यदि दो या अधिक सफल बोलीदाता समान मूल्य उद्धृत करते हैं, तो सफल बोलीदाता का चयन लकी ड्रा के आधार पर किया जाएगा।
14. वसूली प्रक्रिया पर किया गया प्रशासनिक व्यय भी वसूली के लिए देय राशि का हिस्सा होगा और तदनुसार ही उसका निपटान किया जाएगा।
15. शेष शर्तें नीलामी के समय घोषित की जाएंगी।

उप आबकारी एवं कर आयुक्त (एसटी)
नूंह (मेवात)

PRDH:-1037/11/301/2026/39516/1/7Dt.16/10/2025

Became member of my community and Get Access to 3 channels In just 19 Rupees

♦ Indian Newspapers Channel 🗞️

♦ Magazine Channel [National & International📚]

♦ International Newspapers🗽

Click here

It's one time Fee to Become Members, and after that you don't need to pay subscription fees.